R.N.I. NO.HIN/2002/8718
www.akshnews.com
M.P./BHOPAL/642/2021-23

वर्ष 19, अंक-19
1 से 15 जुलाई 2021
पृष्ठ-48
मूल्य 25 रूपये

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

- कागजों पर रोपे गए 2,500 करोड़ पौधे
- भाई को मप्र में नई भूमिका की तलाश

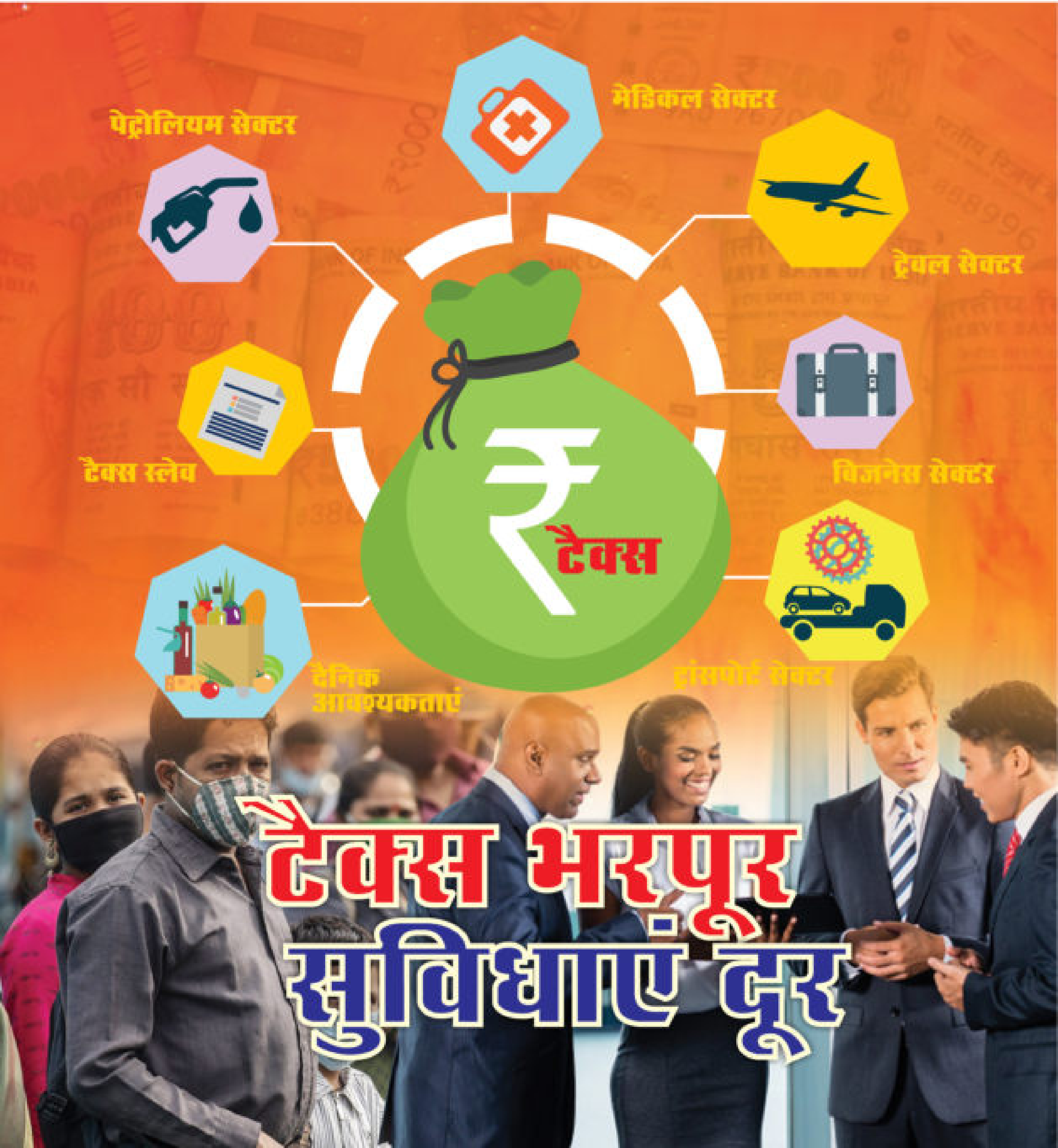
पेट्रोलियम सेक्टर
मेडिकल सेक्टर
ट्रेवल सेक्टर
टैक्स स्लेब
₹
टैक्स
बिजनेस सेक्टर
दैनिक आवश्यकताएं
ट्रांसपोर्ट सेक्टर

टैक्स भरपूर सुविधाएं दूर

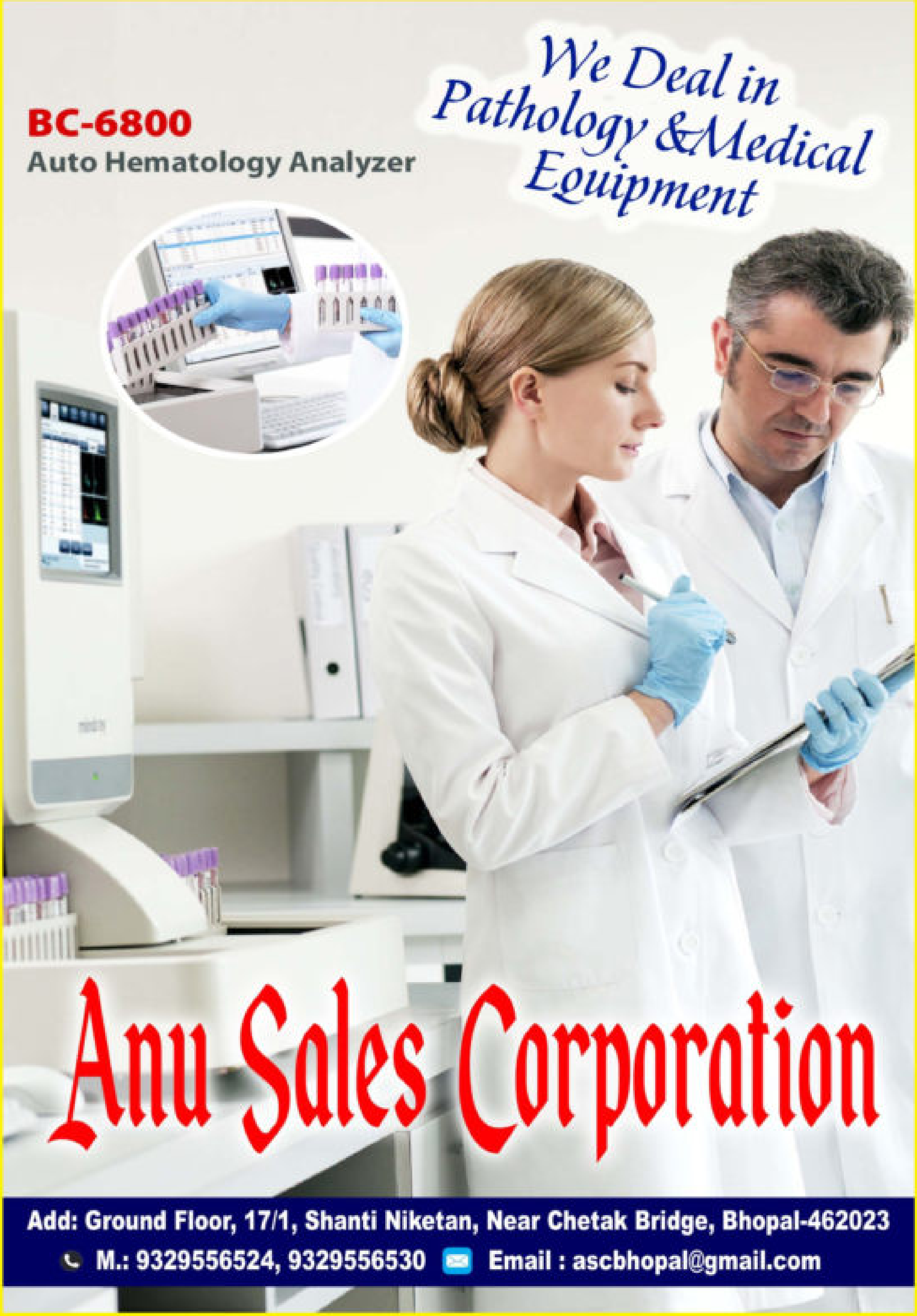

BC-6800
Auto Hematology Analyzer

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Anu Sales Corporation

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
☎ M.: 9329556524, 9329556530 ✉ Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

जांच-पड़ताल

9 | भ्रष्ट योगीराज से 1.10 करोड़...

मप्र के सबसे भ्रष्टतम अफसरों में शामिल बर्खास्त स्वास्थ्य संचालक डॉ. योगीराज शर्मा से 110.62 लाख (1 करोड़ 10 लाख 62 हजार) की राशि वसूलनी है। इसके लिए सरकार ने भोपाल कलेक्टर को अधिकृत किया है।

राजपथ

10-11 | सेवा करें... दिखावा नहीं

3 साल के लंबे अंतराल के बाद मप्र भाजपा की कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जहां कोरोनाकाल में पार्टी और सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई, वहीं नेताओं को नसीहत दी गई कि राजनीति...

इंदौर

14 | देशभर में फिर चमका इंदौर

स्वच्छता में 4 बार देश में परचम लहरा चुके इंदौर ने एक और उपलब्धि हासिल की है। उसे अब 'इंडिया स्मार्ट सिटीज अवॉर्ड्स कॉन्टेस्ट 2020' की 7 विभिन्न श्रेणियों में पहला स्थान मिला है। ऐसे ही, राज्यों की श्रेणी में मप्र को दूसरा स्थान मिला है।

भर्राशाही

15 | मेगा प्रोजेक्ट्स की मंद रफ्तार

50 दिन के कोरोना कर्फ्यू में निर्माण कार्यों पर रोक नहीं थी, लेकिन कहीं मटेरियल तो कहीं लेबर की दिक्कतों के कारण शहर में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक सा लग गया है। दफ्तरों में केवल 10 फीसदी स्टाफ की अनुमति होने से फील्ड में चल रहे कार्यों से जुड़ी टेक्निकल ड्राइंग तैयार करने...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

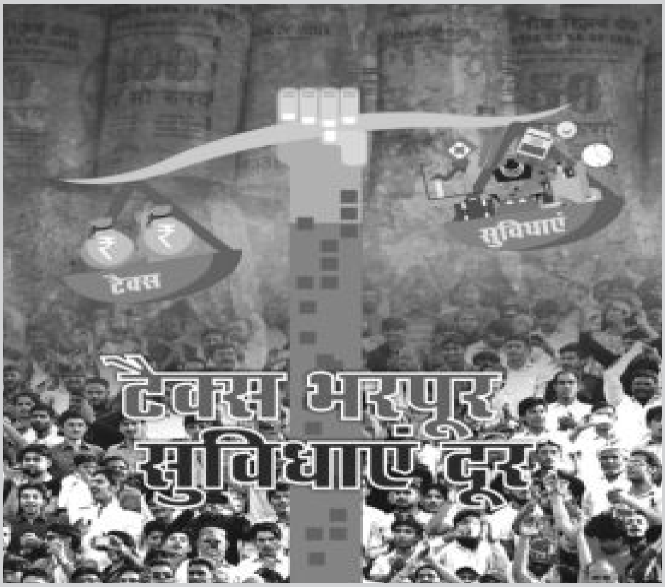

25 जून को अपनी जन्मभूमि कानपुर देहात में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जबसे कहा है कि देश के विकास के लिए टैक्स जरूरी है और मैं भी पौने तीन लाख रुपया टैक्स देता हूं। तबसे देश में यह बहस चल पड़ी है कि देश में कितने लोग टैक्स देते हैं और क्या उस टैक्स के बदले उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। अगर देखा जाए तो देश में हर व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर टैक्स दे रहा है। इसके बावजूद स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों का अभाव है।

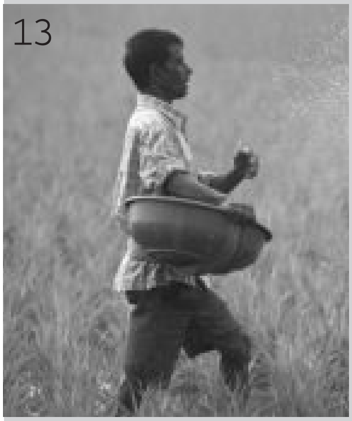
13

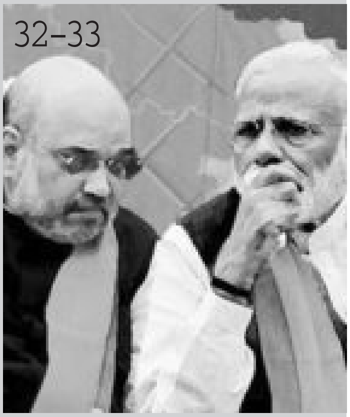
32-33

39

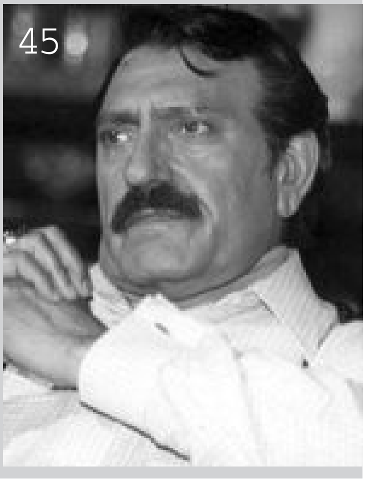
45

राजनीति

30-31 | विपक्षी एकजुटता किसके खिलाफ?

विपक्षी एकजुटता के नाम पर हो रही ताजा जमघट अलग तो है। मानना पड़ेगा। मानना इसलिए नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं, बल्कि, इसलिए क्योंकि हर चीज बड़ी ही सावधानी के साथ होती नजर आ रही है। कहने की जरूरत नहीं जब भी ऐसी कोई सियासी कवायद...

महाराष्ट्र

35 | किसे चुनेगी भाजपा?

कोरोना महामारी की दूसरी लहर में वैक्सीन, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता पर महाविकास आघाड़ी सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ भरपूर हमला बोला। लेकिन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नरम रहे। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी उद्धव...

बिहार

38 | 'चिराग' तो बुझना ही था!

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान की डिक्शनरी से सुकून नाम का शब्द गायब हो गया था। पहले एलजेपी के 208 से ज्यादा नेता, फिर पार्टी का एकलौता विधायक और अब उनके चाचा पशुपति कुमार...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

एक तीर से कई निशाने साधे शिवराज ने....

मुनव्वर राणा का एक शेर है...

हमारा तीर कुछ भी हो निशाने तक पहुंचता है।
परिन्दा कोई मौसम हो ठिकाने तक पहुंचता है।।

यह शेर मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी रणनीति पर सटीक बैठता है। हाल ही में उन्होंने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा है। करीब डेढ़ साल बाद मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिला है। प्रभार की सूची देखकर साफ कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। यानी उन्होंने हर मंत्री को उनके कद के अनुसार जिला दिया है। वहीं हर वरिष्ठ नेता की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा गया है। यानी एक संतुलन देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सत्ता, संगठन और संघ के समन्वय से सूची को अंतिम रूप दिया गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंदौर जिले का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही नरोत्तम शिवराज कैबिनेट में सबसे ताकतवर और नंबर वन मंत्री हो गए हैं। वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव नंबर दो पर हैं। उन्हें जबलपुर और निवाड़ी जिले का प्रभार सौंपा गया है। तीसरे नंबर पर सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट हैं। उन्हें ग्वालियर-हरदा का प्रभार मिला है। सिलावट भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी हैं। सतना, नरसिंपुर के प्रभारी बनाए गए वन मंत्री विजय शाह चौथे नंबर पर हैं। पांचवे नंबर पर वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा हैं, उन्हें उज्जैन, कटनी का प्रभार दिया है। वरिष्ठता के हिसाब से छह नंबर पर खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह हैं। सातवें नंबर पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हैं, उन्हें देवास और आगर-मालवा का प्रभार दिया है। मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह आठवें नंबर पर हैं, इन्हें भोपाल का प्रभार मिला है। नौवें नबर पर अजजा मंत्री मीना सिंह हैं, इन्हें सीधी, अनूपपुर का प्रभार दिया है। दस नंबर पर कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, उन्हें खरगोन, छिंदवाड़ा का प्रभार मिला है। प्रदेश सरकार में 30 मंत्री हैं। जिनमें से 22 मंत्रियों को दो-दो जिलों का प्रभार सौंपा गया है। जबकि भूपेन्द्र सिंह, नरोत्तम समेत 8 मंत्रियों को एक-एक जिले का प्रभार दिया गया है। मंत्रियों को जिलों का प्रभार बांटने के साथ ही सियासत में ग्वालियर-चंबल के बंटवारे की चर्चा चल पड़ी है। ग्वालियर संभाग के जिलों का प्रभार सिंधिया समर्थक मंत्रियों को दिया गया है। भिंड जिले का प्रभार भी सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह को दिया है। चंबल के श्योपुर और मुरैना जिले का प्रभार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी मंत्री भारत सिंह कुशवाह को दिया गया है। जिलों के प्रभारी मंत्रियों की जारी सूची में ये चौंकाने वाला बदलाव इंदौर के राजनीतिक समीकरण को भी बदल देगा। एक तीर से कई निशाने साधते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां इंदौर की भीषण गुटबाजी और पड़ने वाले दबाव-प्रभाव से खुद को बचाने के प्रयास तो किए ही, वहीं नाराज चल रहे नरोत्तम को साधने का काम भी बखूबी कर लिया। पिछले दिनों परिवर्तन की जो मुहिम शुरू की गई उसकी हवा हालांकि पिछले दिनों भोपाल में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में निकल गई, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सराहना कर दी। इंदौर में ताई-भाई, भाभी से लेकर साहब की जो गुटबाजी चलती रही, उसमें अब नवागत प्रभारी मंत्री का एक नया गुट तैयार होगा। इंदौर की राजनीति से लेकर यहां लिए जाने वाले सारे फैसले पूरे प्रदेश पर असर डालते हैं। अब देखना यह है कि करीब डेढ़ साल बाद काम पर लगाए गए मंत्री किस तरह सत्ता और संगठन की मंशा पर खरे उतरते हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक
अक्स

वर्ष 19, अंक 19, पृष्ठ-48, 1 से 15 जुलाई, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो

मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता**:- इंद्रकुमार, **जयपुर**:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़**:- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ** :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिंलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

ग्रामीणों में जागरूकता लाएं

प्रदेश में ग्रामीण आबादी में साक्षरता दर बढ़ने के बावजूद आधुनिक चिकित्सा के प्रति भरोसा उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। गांवों में जागरूकता अभियान को गहन करना होगा। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के साथ ही उन्हें जागरूक करना चाहिए।

● **प्रणव कुमार,** भोपाल (म.प्र.)

किसानों का धान बर्बाद

वर्ष 2019–20 में किसानों से खरीदा गया 80 करोड़ रुपए की 3.28 लाख क्विंटल धान नान की लापरवाही के चलते बर्बाद हो गया। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और लापरवाही करने वाले अधिकारी–कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिए।

● **धीरेंद्र सिंह,** इंदौर (म.प्र.)

नाथ को नहीं भरोसा

अपने करीबी नेताओं पर विश्वास करके सत्ता गंवा चुके कमलनाथ अब राजनीति में हर कदम फूंक–फूंककर रख रहे हैं। उनकी कार्यप्रणाली से यह साफ है कि अब उनको किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए वे अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। इससे उनके खिलाफ पार्टी में माहौल निर्मित हो रहा है।

● **मलखान गुर्जर,** ग्वालियर (म.प्र.)

कर्ज लेकर जीने को मजबूर

देश में कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी आपदा बनकर सामने आई है। एक तो पहले से ही लोग अपने काम–धंधे से हाथ धोकर बैठे हुए हैं। ऊपर से परिवार का इलाज कराने के लिए उधारी लेकर जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के कारण आए आर्थिक संकट ने ज्यादा से ज्यादा परिवारों को कर्ज में डुबो दिया है। महामारी की दूसरी लहर और इसके चलते लगाए गए लॉकडाउन ने पारिवारिक आमदनी को गहरी चोट पहुंचाई है। परिवारों ने उधार ले–लेकर अपना काम चलाया है। लोगों ने परिवार के इलाज के लिए वर्षों की जमापूंजी तो खर्च की ही, साथ ही साथ परिचितों से उधार लेकर भी परिवार का इलाज कराया। कईयों ने सोने के जेवरों को गिरवी रखकर कर्जा लिया।

● **राजकुमार मीणा,** जबलपुर (म.प्र.)

समझदारी और सावधानी जरूरी

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भले ही थमने लगी है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में समझदारी और सावधानी दोनों जरूरी है। दूसरी लहर में जो कहर बरपा है, उसे हम सभी ने महसूस किया है। आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से दोगुनी खतरनाक हो सकती है। इसलिए हर एक को सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी हटते ही दुर्घटना घट सकती है। इसलिए इस परिस्थिति में हर व्यक्ति को हर समय कोविड–19 की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है।

● **सुरेंद्र धानक,** राजगढ़ (म.प्र.)

मजदूरी में देरी

कोरोना के संक्रमणकाल में जहां एक तरफ शहरों से लोग गांवों में पलायन करने को मजबूर थे। वहीं गांव के लोगों के मनरेगा संजीवनी बनकर उभरी थी। लेकिन मनरेगा द्वारा मजदूरों को भुगतान करने में देरी हो रही है। जिससे गरीबों को जीवन–यापन करने में परेशानी हो रही है। को भारत में मनरेगा के तहत भुगतान में देरी का मामला बीते पांच वर्षों में बढ़ता गया है। देश में मनरेगा के तहत भुगतान में 16 से 30 दिनों की देरी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है।

● **दिनेश शर्मा,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष
जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

अमरिंदर का बढ़ता संकट

पंजाब में विधानसभा चुनाव मात्र कुछ माह बाद होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर चल रहा घमासान विपक्षी दलों को खासा सुहा रहा है तो कांग्रेस आलाकमान को हलाकान कर रहा है। पिछले दिनों इस मसले को सुलझाने के लिए गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंप दी। उम्मीद की जा रही है कि सोनिया गांधी इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द कुछ फैसला लेगीं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ बागी होते दिख रहे नवजोत सिंह सिद्धू संग उनकी पोस्टर वॉर जारी है। तो दूसरी तरफ असंतुष्ट पार्टी नेताओं ने उनके करीबियों को टारगेट करना तेज कर दिया है। इन नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी समझे जाने वाले राज्य के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा जानबूझकर कई संवेदनशील मामलों में पैरवी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। नतीजा यह रहा कि राज्य की एडिशनल एडवोकेट जनरल रमीजा हकीम को इस्तीफा देना पड़ा। रमीजा हकीम, अतुल नंदा की पत्नी हैं। इस बीच अमूमन असंतुष्ट नेताओं और मुख्यमंत्री के बीच संतुलन बनाने वाले प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुनील झाखड़ के सुर भी मुख्यमंत्री के खिलाफ होते नजर आने लगे हैं। सूत्रों की मानें तो पार्टी के कई बागी नेता सोनिया गांधी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

फुल फार्म में अखिलेश

उप्र में जहां एक तरफ भाजपा भारी अंतर्कलह से जूझ रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 2022 की शुरुआत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसती नजर आने लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों छोटे दलों के नेताओं संग लगातार बैठकें कर चुनाव पूर्व मजबूत गठबंधन तैयार करने में जुट गए हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो अखिलेश यादव कांग्रेस और बसपा संग गठबंधन नहीं करने का मन बना चुके हैं। बड़े दलों के बजाय उनका फोकस 'सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी', 'अपना दल (सोनेलाल)' जैसी छोटी पार्टियों पर है। साथ ही अखिलेश इन दिनों सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला बनाने में जुटे हैं। खबर जोरों पर है कि जल्द ही बसपा के कई बड़े नेताओं की वे सपा में एंट्री कराने जा रहे हैं। खबर इस बात की भी गर्म है कि भाजपा के कुछ विधायक एवं योगी सरकार के एक कद्दावर मंत्री भी पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारों की माने तो अखिलेश का लक्ष्य मायावती का जाटव वोट बैंक और भाजपा से नाराज चल रहा ब्राह्मण वोट बैंक है। इस सबके बीच सपा का प्रोमोशनल सॉन्ग 'मुरलीधर वेश बदलकर आ रहे हैं' उप्र की राजनीति में भारी हलचल मचा रहा है।

बैकफुट पर भाजपा

भाजपा का शस्त्र अब उस पर ही प्रहार करता कई राज्यों में नजर आने लगा है। मोदी-शाह पर पार्टी को विस्तार देने के लिए विपक्षी दलों में सेंधमारी करने और केंद्रीय एजेसिंयों को विपक्षी नेताओं के पीछे लगाने का आरोप लगता रहा है। बीते 7 बरसों में उत्तराखंड, मप्र, राजस्थान, असम, गोवा समेत अनेक प्रदेशों में बड़े पैमाने पर दलबदल हुआ। उत्तराखंड में सबसे पहले तत्कालीन हरीश रावत सरकार को गिराने का प्रयास भाजपा ने किया। कांग्रेस के दस विधायकों से दल बदल कर रावत सरकार को अल्पमत में लाने का प्रयास हुआ। यह अलग बात है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के चलते अपनी सरकार बचा पाने में सफल रही। लेकिन मप्र में कमलनाथ सरकार बच न सकी। राजस्थान में भी तमाम हथकंड़ों के बाद भी भाजपा गहलोत सरकार को न गिरा सकी। पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस में बड़े स्तर की सेंधमारी कर जमाने का भरकस प्रयास किया लेकिन ममता ने उसके मंसूबों पर पानी फेर डाला। सत्ता में वापसी के साथ ही ममता आक्रामक तरीके से पलटवार करने में जुट गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने तृणमूल में वापसी कर डाली है। खबर है कि कई भाजपा विधायक जल्द ही ममता की शरण में जाने वाले हैं।

अंतर्कलह की शिकार

जयललिता के निधन के बाद से ही अन्नाद्रमुक के भीतर घमासान शुरू हो गया था। पहले पार्टी पर कब्जा करने का प्रयास जयललिता की खास सहेली रहीं शशिकला ने किया। बेचारी मुख्यमंत्री बनने ही जा रही थीं कि भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें चार बरस कारावास की सजा सुना दी गई। उनके जेल जाने के बाद पार्टी और मुख्यमंत्री पद के लिए पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच महाभारत शुरू हो गई। दोनों ने हालांकि वक्त की नजाकत भांपते हुए समझौता कर लिया पलानीस्वामी मुख्यमंत्री तो पनीरसेल्वम उपमुख्यमंत्री बन गए। दोनों ने ही मिलकर शशिकला को बाहर का रास्ता दिखा डाला। अब शशिकला एक बार फिर से अन्नाद्रमुक में कब्जा करने के लिए सक्रिय हो चली हैं। खबर है कि अन्नाद्रमुक का कैडर बड़ी संख्या में शशिकला की वापसी चाह रहा है। इससे चिंतित पलानीस्वामी ने शशिकला से संपर्क रखने का आरोप लगाते हुए 16 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निलंबित कर डाला है। कई बड़े नेताओं पर शशिकला समर्थक होने चलते गाज गिरनी तय है।

कौन बनेगा सीवीसी बोलो!

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) में इन दिनों एक पद रिक्त है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर नजर रखने वाला यह आयोग खासा महत्वपूर्ण एवं ताकतवर माना जाता है। किसी भी उच्च स्तरीय सरकारी नियुक्ति से पहले सतर्कता आयोग से एनओसी लेना जरूरी है। आयोग चयनित व्यक्ति को एक प्रकार से चरित्र प्रमाण पत्र जारी करता है जिसके बाद ही उस व्यक्ति को पद मिल सकता है। लंबे अर्से तक मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं दो सतर्कता आयुक्त आईएएस संवर्ग से हुआ करते थे। लेकिन मोदी सरकार के आते ही यह परंपरा टूट गई। 2015 में इनकम टैक्स सेवा के वरिष्ठ अधिकारी केवी चौधरी को मोदी सरकार ने मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया था। चौधरी की सेवानिवृत्ति के पश्चात एक बार फिर से आईएएस संवर्ग के संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त 2020 में बनाए गए। वर्तमान में तीन सदस्यीय इस आयोग में सतर्कता आयुक्त का एक पद रिक्त है। देखना है कि यह पद किसे मिलता है।

दक्षिण का बजेगा डंका

मप्र की नौकरशाही में उप्र, बिहार, राजस्थान के मूलनिवासियों का सबसे अधिक दबदबा रहता है, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति और परिस्थिति बदल गई है। जहां प्रशासनिक मुखिया पंजाब के मूलनिवासी हैं, वहीं पुलिस विभाग के मुखिया मप्र के तथा अन्य प्रमुख पदों पर विभिन्न राज्यों के मूलनिवासियों का कब्जा है। यानी वरिष्ठता और योग्यता के अनुसार पद बंटे हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में दक्षिण का डंका बजने वाला है। इसको लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चाएं गर्म हैं। दरअसल, प्रदेश की राजनीति में दक्षिण भारत के एक राजनेता की हैसियत बढ़ी है। बताया जाता है कि उक्त दक्षिण भारतीय माननीय को जबसे मप्र की कमान मिली है, उनके पास दक्षिण भारतीय मूल के आईएएस और आईपीएस अफसरों का जमावड़ा लगने लगा है। माननीय यहां रहें या दिल्ली हर जगह ये अफसर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। 2007 बैच के एक आईपीएस अधिकारी अपने दक्षिण भारतीय दोस्त के माध्यम से भोपाल डीआईजी की कुर्सी के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि साहब की जुगाड़ भोपाल के वर्तमान डीआईजी के आगे फींका पड़ रहा है। उधर, 2001 बैच के एक आईएएस अधिकारी को भी अपना भाग्य चमकता दिख रहा है। कई बड़े जिलों की कलेक्टरी और प्रमुख विभागों की कमान संभाल चुके ये साहब अब कोई बड़ा पद चाहते हैं।

रसूख की वर्जिश

कोरोना के संक्रमणकाल में योग और व्यायाम, आम और खास सबके लिए दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। सरकार भी इस पर जोर दे रही है। लेकिन प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इस समय एक रसूखदार के बेटे की वर्जिश की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, साहबजादे का रसूख ही कुछ ऐसा है। वैसे सरकार के सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति के पुत्र होने के कारण उन्हें पहले से ही प्रोटोकॉल मिलता रहा है। लेकिन इन दिनों साहबजादे को वर्जिश का शौक चढ़ गया है। उनका यह शौक अन्य लोगों पर भारी पड़ रहा है। सूत्रों का कहना है कि साहबजादे को राजधानी के ह्दयस्थल पर बने सबसे बड़े खेल मैदान पर वर्जिश करने में मजा आ रहा है। आलम यह है कि जिस दिन साहबजादे उस खेल मैदान पर आमद देते हैं, पूरी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। वहां की पूरी व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी जाती है। यही नहीं साहबजादे जब तक वर्जिश करते हैं वहां अन्य लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। इससे उन लोगों को काफी परेशानी और फजीहत का सामना करना पड़ता है, जो नियमित रूप से वहां बाल-बच्चों के साथ व्यायाम करने जाते हैं। लेकिन करें भी तो क्या... साहबजादे का रसूख ही कुछ ऐसा है।

ईमानदारी की अग्निपरीक्षा

दैनिक जीवन में भले ही ईमानदारी की सलाह दी जाती है, लेकिन उसका पालन करने वालों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी में इन दिनों 2009 बैच की एक तेज तर्रार और ईमानदार आईएएस अधिकारी फंसी हुई है। दरअसल, मैडम नियमानुसार काम करने की आदी हैं। लेकिन इन दिनों उन पर राजनेताओं द्वारा अपने हिसाब से काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। आलम यह है कि मैडम नियमानुसार काम करने पर अड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ उन्हें बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल, मैडम जिस विभाग में पदस्थ हैं उस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति हुई है। लेकिन मुफ्त का चंदन, घिस मोरे नंदन की तर्ज पर अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले अपने हिसाब से पदस्थापना भी चाहते हैं। मैडम नियमानुसार किसी को भी ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में दो-तीन लोगों ने जुगाड़ लगाने के लिए राजनेताओं के पास गुहार लगा दी है। उनकी गुहार सुनने के बाद मैडम पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे जैसे भी हों इन लोगों को उनकी मंशानुसार जगह पर अनुकंपा नियुक्ति का आदेश दे दें। सूत्र बताते हैं कि मैडम किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं। हद तो यह है कि मैडम के पास सरकार के मुखिया तक की सिफारिश आ चुकी है, लेकिन मैडम ने उनसे भी कह दिया है कि मैं नियमानुसार काम कर रही हूं। जबकि मैडम के पास मौका था कि वे मुखिया की बात मानकर उनकी नजर में अपने हैसियत बढ़ा लेतीं। पर वे भी क्या करें, एक-दो मामले हों तो बात है, पर यहां तो तीन-चार दर्जन है।

साहबजादे का वसूली अभियान

मंत्रियों के परिजनों द्वारा मंत्री के रसूख की आड़ में कमाई करने के कई मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन इस समय एक मंत्री के साहबजादे इसलिए चर्चा में हैं कि वे जिलों में जाकर वसूली कर रहे हैं और दाता के नाम पर दे दे की तर्ज पर जो भी मिलता है उसे ले लेते हैं। गौरतलब है कि साहबजादे के पिताश्री के पास तीन विभाग हैं। वे जिलों में जाकर हर विभाग की वसूली करते हैं। सूत्र बताते हैं कि वे कहते हैं कि जो मिल रहा है उसे लेने में बुराई ही क्या है, न जाने कब यह मौका हाथ से निकल जाए। विगत दिनों साहबजादे राजधानी के पास के एक जिले में वसूली करने के अभियान में जुटे हुए थे। उसी दौरान उनको जानने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे और उनसे पूछा कि आप लोग यहां कैसे? तो साहबजादे ने तपाक से जवाब दिया- हमें जाना ही पड़ता है। मंत्रीजी जहां जाते हैं वहां तैयारियां देखने के लिए हम जाते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी हकीकत सामने आने लगी है। इसलिए वे कन्नी काटकर वहां से निकल पड़े। कुछ अन्य मंत्रियों के साहबजादे भी इसी राह पर हैं।

न खुदा मिला न...

न खुदा ही मिला न विसाल-ए-सनम न इधर के हुए न उधर के हुए...रहे दिल में हमारे ये रंज-ओ-अलम न इधर के हुए न उधर के हुए। ऐसी ही स्थिति मप्र कैडर के एक युवा आईएएस की हो गई है। 2014 बैच के इस युवा आईएएस अधिकारी ने जिस तेजी के साथ शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसी तेजी से परिदृश्य से गायब हो गए हैं। साहब ने तो बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन उनके दावे धरे के धरे रह गए। उहोंने जिस विस्फोटक अंदाज में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे अनुमान हो चला था कि ये मामला कुछ तो गुल खिलाएगा ही। पावर गैलरी की हर हरकत पर नजरें भी लगी थीं कि अचानक खबर फैल गई कि साहब पत्रकारों से सीधे चर्चा करना चाहते हैं। उड़ती-उड़ती चर्चा ये भी होने लगी कि किसी बड़ी सियासी हस्ती का कच्चा-चिट्ठा सामने आने वाला है। लेकिन न जाने साहब को क्या हुआ कि उन्होंने सारे विवाद से मुंह मोड़ लिया है और अपने काम-काज में लग गए। बताते हैं कि ये परिवर्तन एक फोन आने के बाद ही हुआ।

अक्स का आईना

कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का फोकस ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि बंगाल पर था। लोगों की जान प्रधानमंत्री के आंसुओं से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से बचाई जा सकती थी। लेकिन चुनाव बाद आंसू बहाने का नाटक कर अपनी गलती छुपाने की कोशिश की।

● **राहुल गांधी**

वर्तमान राजनीतिक हालातों में तीसरे मोर्चे का कोई रोल नहीं है। भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में हराने के लिए पूरे विपक्ष को एकसाथ रहना होगा। हालांकि मैं विपक्ष की रणनीति का हिस्सा नहीं हूं। इसलिए मेरे इस विचार से किसी और का कोई लेना-देना नहीं है। न ही मैं किसी मोर्चे की राजनीति का हिस्सा हूं। जो भी हो रहा है, सामने आएगा।

● **प्रशांत किशोर**

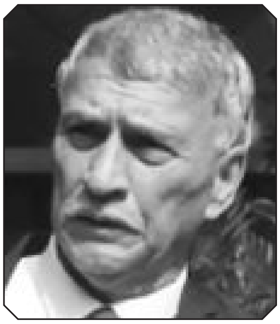

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम की गेंदबाजी स्तरहीन रही है। मुझे यह अपमान जैसा लगा। हैरानी की बात तो यह है कि इंग्लिश माहौल में हुए इस चैम्पियनशिप में भारतीय गेंदबाजों का स्विंग दिखा ही नहीं। टीम चयन में भी गड़बड़ी हुई है। अगर टीम में भुवनेश्वर कुमार को रखा जाता तो वे न्यूजीलैंड पर भारी पड़ते।

● **रोजर बिन्नी**

देश में सभी कांग्रेस विशेषज्ञ हैं। कांग्रेस पर निशाना साधना एक राष्ट्रीय खेल बन चुका है। सत्ता से चिपकना सभी पार्टियों को भाता है। कांग्रेस एनजीओ नहीं है, सत्ता के लिए लड़ती है। कांग्रेस से गलतियां भी हुई हैं। कमजोरियां भी हैं। उन्हें दूर करना जरूरी है।

● **जयराम रमेश**

मैंने पुरुषों, महिलाओं और खुद से सेक्सिज्म का सामना किया है। मैं यह भी स्वीकार करती हूं कि मैंने महिला होने के कारण कभी-कभी अपने आप को कम आंका है। हालांकि, समय के साथ मैंने महसूस किया है कि इससे बाहर निकलने का भी एक रास्ता है। अब मैं अपने जेंडर के कारण खुद को कभी पीछे नहीं रखती हूं। मैं लोगों के देखने के लिए फिल्में बनाती हूं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी फिल्मों को देखते हैं, उतनी ही ज्यादा खुशी मुझे मिलती है। मेरी कई फिल्मों को लेकर लोगों के अजब-गजब विचार हैं। लेकिन समाज में व्याप्त बुराईयों और समस्याओं को बाहर लाकर मैं काफी संतुष्ट होती हूं।

● **विद्या बालन**

वाक्युद्ध

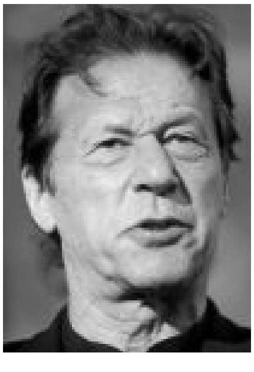

यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं के पीछे महिलाओं के छोटे कपड़े जिम्मेदार हैं। उन्हें समाज को बहकाने से बचना चाहिए। अगर कोई महिला कम कपड़े पहनती है, तो इसका असर पुरुषों पर पड़ेगा। अगर वह रोबोट नहीं है तो। यह कॉमन सेंस है। इसलिए महिलाओं को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए और ढंग के कपड़े पहनना चाहिए।

● **इमरान खान**

किसी देश के प्रधानमंत्री की सोच और विचार उस देश की मानसिकता को दर्शाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर जो टिप्पणी की है, वह यह दर्शाता है कि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। इमरान को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है।

● **स्मृति ईरानी**

भ्रष्ट योगीराज से 1.10 करोड़ की वसूली कब...?

वसूली का सरकारी आदेश

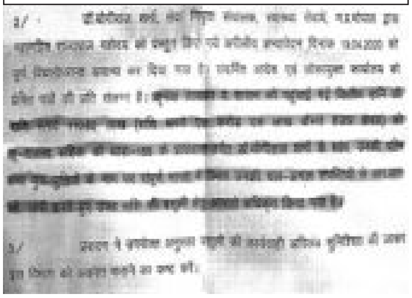

मप्र के सबसे भ्रष्टतम अफसरों में शामिल बर्खास्त स्वास्थ्य संचालक डॉ. योगीराज शर्मा से 110.62 लाख (1 करोड़ 10 लाख 62 हजार) की राशि वसूलनी है। इसके लिए सरकार ने भोपाल कलेक्टर को अधिकृत किया है। इस संदर्भ में 2020 में कलेक्टर भोपाल को पत्र भेजकर निर्देश दिया गया था, लेकिन कलेक्टर ने शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और शर्मा उच्च न्यायालय में चले गए थे, जिसके कारण उनसे वसूली नहीं हो पाई थी। अब एक बार फिर सरकार ने दोबारा 16 जून 2021 को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे डॉ. योगीराज शर्मा से 110.62 लाख रुपए की राशि वसूलें। निर्देश में यह भी कहा गया है कि भू-राजस्व संहिता की धारा-155 के प्रावधान अंतर्गत डॉ. योगीराज शर्मा के स्वयं, उनकी पत्नी तथा पुत्र-पुत्रियों के नाम पर संपूर्ण भारत में स्थित उनकी चल-अचल संपत्तियों से आरआरसी जारी करते हुए उक्त राशि को वसूला जाए।

सूत्रों का कहना है कि सरकार के दूसरे पत्र के बाद भी कलेक्टर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस पर सवाल उठने लगा है कि आखिर सरकार को करोड़ों रुपए की हानि पहुंचाने वाले अफसर पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है। गौरतलब है कि डॉ. योगीराज शर्मा और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और षड्यंत्र करने का आरोप है। डॉ. योगीराज शर्मा, जब संचालक, स्वास्थ्य सेवा में पदस्थ थे तो स्वास्थ्य विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। जिसकी जांच करने पर उनके भ्रष्टाचार की परतें खुलती चली गईं। जांच के बाद शर्मा को आरोप पत्र जारी किए गए। इसके अनुसार वर्ष 2006-07 में डॉ. योगीराज शर्मा, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल के पद पर पदस्थ रहते हुए दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए परिवार स्वास्थ्य कार्ड का मुद्रण आदेश वित्तीय क्षेत्राधिकार से बाहर अनियमित रूप से जारी किए गए। मुद्रण आदेश शासकीय मुद्रणालय को संबोधित होकर भी सीधे प्रेस को न दिए जाकर निजी मुद्रकों को दिए गए। उपरोक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उप नियम 1.2.3. के अनुसार कदाचरण की श्रेणी में आता है। शासन को हुई वित्तीय हानि 110.62 लाख की वसूली का निर्णय लिया जाकर 13.11.2014 को आदेश जारी किए गए। शर्मा उसके बाद न्यायालय में चले गए। न्यायालयीन निर्णय अनुसार विभागीय पत्र दिनांक 13.12.2016 द्वारा डॉ. शर्मा को विभागीय जांच प्रतिवेदन से असहमत होने के कारणों एवं आधार का उल्लेख करते हुए नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस में किए गए उल्लेख कदाचरण के बारे में डॉ. शर्मा द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। डॉ. शर्मा को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 24.01.2017 को पत्र जारी किया गया। उक्त पत्र तामील होने के उपरांत भी डॉ. शर्मा उपस्थित नहीं हुए। पूर्व में भी डॉ. शर्मा की विभागीय जांच की सुनवाई में भी इसी प्रकार का व्यवहार रहा है। इस प्रकार व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर को समाप्त किया गया।

परिवार स्वास्थ्य कार्ड के मुद्रण के कार्यादेश डॉ. योगीराज शर्मा द्वारा संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की हैसियत से हस्ताक्षरित किए गए, जबकि संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के रूप में उन्हें दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का कार्य आवंटित नहीं था। परिवार स्वास्थ्य कार्ड के मुद्रण का कार्यादेश, आईईसी ब्यूरो द्वारा किया है, किंतु उपरोक्त आदेश आईईसी ब्यूरो से जारी करने के बजाय संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल के स्टोर तथा आरसीएच के स्टोर से जारी कराए गए। आईईसी ब्यूरो की नस्ती होने के कारण यह मुद्रण आदेश आईईसी ब्यूरो से दिए जाने थे, किंतु एक ही सप्ताह में 50 लाख स्वास्थ्य परिवार कार्ड के मुद्रण को टुकड़ों में बांटकर डॉ. योगीराज शर्मा, तत्कालीन संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल द्वारा सीधे जारी किए गए। यह अपने आप में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। डॉ. शर्मा द्वारा सम्यक वित्तीय परीक्षण किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

शासकीय मुद्रणालय से प्रिंटिंग के कार्य का आंकलन प्राप्त किया जाना चाहिए था। जिस पर बजट की स्थिति एवं बजट की उपलब्धता तथा वित्तीय अधिकारों का विश्लेषण करते हुए आगे निर्णय लिया जाना चाहिए था, लेकिन डॉ. योगीराज शर्मा द्वारा बिना किसी सम्यक परीक्षण किए, आदेश अपने ही स्टेनो कार्यालय से जारी कर दिए गए। दस्तावेजों में, जिन्हें विभागीय जांचकर्ता अधिकारी को आरोप-पत्र एवं आधार-पत्र के साथ दस्तावेजीय साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए गए थे अंकित है कि दिए गए आदेशों को किसी भी स्तर पर जावक नहीं पाया गया एवं इसी कारण से प्रिंटिंग कंपनियों को सीधे आदेश दे दिए गए।

● **सुनील सिंह**

पौने 7 रुपए के कार्ड की छपाई 10 रुपए में करवाई

दस्तावेजों में यह भी उल्लेखित है कि शासन की एक अन्य संस्था माध्यम से मुद्रण दर प्राप्त की गई थी, जो कि प्रति कार्ड 6 रुपए 75 पैसे थी। माध्यम भी राज्य शासन की संस्था है एवं संचालक को मुद्रण आदेश देने के पूर्व शासकीय मुद्रणालय से दरें प्राप्त कर, दोनों संस्थाओं की दरों एवं गुणवत्ता की तुलना की जाना चाहिए थी, जो नहीं की गई। इसके फलस्वरूप नियंत्रक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री को 10 रुपए से अधिक प्रति कार्ड का भुगतान किया गया। एएफपी बिना वित्तीय सम्यक परीक्षण के आर्डर प्रदाय की कार्यवाही करने की बजह से शासकीय धन का अपव्यय हुआ, जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है और जिसका उत्तरदायित्व डॉ. योगीराज शर्मा का होने के कारण अपने आपको इस राशि की वसूली किए जाने का उत्तरदायी बना लिया गया। मप्र वित्तीय अधिकार पुस्तिका, 1995 के खण्ड-1 में संचालक, स्वास्थ्य को प्रदत्त वित्तीय अधिकार सरल क्रमांक-10 में अंकित राशि 50,000 रुपए तक के वित्तीय अधिकार थे, इससे अधिक कार्यादेश जारी करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली जाना अनिवार्य था।

समाज है आराध्य हमारा सेवा है आराधना
प्रदेश कार्यसमिति
कार्यसमिति

सेवा करें... दिखावा नहीं

3 साल के लंबे अंतराल के बाद मप्र भाजपा की कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जहां कोरोनाकाल में पार्टी और सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई, वहीं नेताओं को नसीहत दी गई कि राजनीति सेवाकार्य है और नेता सेवा करें, दिखावा नहीं। इस बैठक में राजनीति से जुड़े तमाम मुद्दों पर मंथन चला। बैठक के विभिन्न सत्रों में राजनीतिक प्रस्ताव और कोरोनाकाल में किए गए कामों के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मप्र में विपक्ष की भूमिका, आगामी राजनीतिक हालातों के अलावा कार्यसमिति सदस्यों को भाजपा के काम करने के तरीके और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया।

भाजपा की कार्यसमिति में दिल्ली से वर्चुअल जुड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां पदाधिकारियों को पार्टी की आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी, वहीं पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को जमकर कोसा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की **जमकर तारीफ** की। वहीं बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने नसीहतों की घुट्टी पिलाई। दोनों नेताओं ने मंत्रियों, पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि भाजपा की प्राथमिकता जनता की सेवा है। इसलिए सभी सेवा भाव से राजनीति करें। जो दिखावा करेगा, उसे पार्टी में उचित स्थान नहीं मिलेगा। दरअसल, भाजपा में पिछले कुछ सालों से दिखावा करने की राजनीति जोर पकड़ रही है। पार्टी के नेताओं की जनता से दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में संघ कई बार सत्ता और संगठन को हिदायतें दे चुका है। उसके बाद भी कुछ नेता पार्टी गाइडलाइन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नसीहत दी। समापन सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए काम करें। दिखावा बंद करें। उन्होंने कहा कि देश का बड़ा वर्ग हमें अच्छा तो मानता है, लेकिन अपना नहीं मानता। समाज में हमें सभी अपना मानें और विश्वास करें इसके लिए हमें काम करना है। सेवा के लिए सेवा करें, दिखावे के कार्यक्रम न करें। उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर इशारों में यह भी कहा कि देश का बड़ा वर्ग हमें अपना नहीं मानता।

शिवप्रकाश की नसीहत के सवाल पर प्रेस कांफ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक समुदाय में जिंदगी भर फूट डालकर राज करने की नीति पर जीवित रही। ऐसे लोगों का विश्वास भी जीतना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने नारा दिया- सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। समाज के सभी वर्ग का विश्वास जीतने के लिए भाजपा का प्रयास जारी है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश

> भाजपा देश की एकमात्र पार्टी है, जो हमेशा मिशन मोड में रहती है। मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं, लेकिन भाजपा अभी से चुनावी तैयारी में जुट गई है। इसके लिए गत दिनों 3 साल बाद प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें आगामी रणनीति के साथ ही नसीहतें भी दी गईं। पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को कहा गया कि वे सेवा करें, दिखावा न करें।

शिवराज सरकार के साथ है केंद्र सरकार

मप्र भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव ने एक बार फिर से शिवराज सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के पीछे केंद्र सरकार मजबूती के साथ खड़ी हुई है। प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। मुरलीधर राव ने 2023 में मुख्यमंत्री शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि 2023 की बात कैसे कर सकता हूं। मैं राजनीति से हूं, भविष्य वक्ता नहीं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चर्चा होने या कांग्रेस के नेताओं के कहने या कुछ करवाने से भाजपा में कुछ तय नहीं होता है। कांग्रेस बाहर कोविड की तरह वेव चला रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस को विध्वंसकारी लोगों के साथ जुड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों की अंब्रेला बनती जा रही है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि इस मामले में वे खुद और उनकी पार्टी के नेता कांग्रेस के किसी भी नेता से पूरे देश में कहीं पर भी चर्चा करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का साथ देने पर कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। कांग्रेस के इस रवैए को लेकर भाजपा देश के एक-एक घर तक जाएगी। हमारे लिए देश पहले है, देश हित में हमारी पार्टी और हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। प्रदेश में भी कांग्रेस की हालत यही हो चली है।

में कई चुनोतियां हैं। हम संगठन को मजबूत करेंगे।

मुरलीधर राव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस अब धीरे-धीरे विध्वंस की राजनीति में लग गई है। सांप्रदायिक, नक्सलियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस कर रही है। आतंकियों को सम्मान देने का काम कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की इस सोच को लेकर जाएंगे। ताकि कांग्रेस के दोनों चेहरे जनता के सामने तक पहुंच सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। राव ने कहा कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जिसने कोविड के नियमों के तहत प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को डिजाइन किया। कोरोनाकाल में यह बैठक एक उदाहरण है। हमने पार्टी की गतिविधियों को सुस्त नहीं होने दिया। पार्टी में आगे और कैसे काम करना है ये हमने तीन दिन की कार्यसमिति की बैठक में तय किया है। दूसरी पार्टियों के लिए यह एक उदाहरण है। राव ने बताया कि कार्यसमिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को हमने प्राथमिकता देते हुए और उन्हें महत्वपूर्ण मानते हुए इनके उत्थान और विकास को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कार्यसमिति में जो निर्णय हुए हैं, वह शीघ्र ही पार्टी के रोडमैप के जरिए सभी को दिखाई देंगे।

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी संगठन आदर्श संगठन है। इसे और आगे किस तरह बढ़ाया जाए, कार्यसमिति की बैठक में इस बात पर विचार हुआ। संगठन की मजबूती के लिए हमने तय किया है कि हमारे मंडल स्वाबलंबी बनें तथा बूथ अधिक सक्रियता से काम करें, इसे लेकर भी चर्चा हुई और पार्टी नेताओं ने इस बात पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए कि कार्यसमिति सदस्य इस काम में किस तरह अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम हो और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता तैयार रहे, इसकी योजना बनाने पर भी चर्चा की गई।

मप्र भाजपा की मीडिया सेल की होगी सर्जरी

भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी शिवराज डाबी को हटाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कई प्रवक्ताओं की छुट्टी भी करने की तैयारी है। वजह है, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव सोशल मीडिया टीम से नाराज हैं। प्रदेश संगठन के ऑफिशियल सोशल मीडिया ग्रुप में फॉलोअर की संख्या मप्र कांग्रेस से कम है। इतना ही नहीं, मीडिया में पार्टी का पक्ष रखने वाले प्रवक्ताओं में आक्रामकता दिखाई नहीं दे रही है। राव ने बैठक में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष एक बार फिर नाराजगी व्यक्त की। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने 22 जून को भोपाल प्रदेश मुख्यालय में आईटी सोशल मीडिया टीम की बैठक ली थी। टीम के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। जिसमें राव ने सोशल मीडिया में और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार करने के साथ ही फॉलोअर बढ़ाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कांग्रेस के सोशल मीडिया में फॉलोअर ज्यादा होने का मुद्दा भी उठाया। कहा- इस अंतर को दूर करें।

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पास राजनीतिक प्रस्ताव में कोरोना रोकने की नाकामी का ठीकरा तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर फोड़ा गया। इसके साथ ही जनता के हित की योजनाओं को बंद करने का आरोप भी लगाया गया। राजनीतिक प्रस्ताव में कांग्रेस नेताओं पर मप्र को टूलकिट की प्रयोगशाला बनाने का आरोप लगाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर साजिश करने के साथ ही कोरोना के इंडियन वैरिएंट और भारत महान नहीं बदनाम जैसे बयानों से दहशत फैलाने के आरोप लगाए गए। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में वादाखिलाफी, अपहरण उद्योग, तबादला उद्योग, किसानों के साथ धोखे, प्रशासनिक अराजकता, संगठित और अवैध आर्थिक वसूली की बात बताई गई। संबल योजना, पंचपरमेश्वर योजना, मेधावी छात्रों को लैपटॉप, कन्यादान, फसल बीमा, आदिवासियों को एक हजार रुपए जैसी योजनाएं बंद करने के आरोप लगे।

वहीं केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया। सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2020 लागू करने, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करने का श्रेय दिया तथा धारा 370, 35-ए हटाने को उपलब्धि बताया गया। कृषि सुधार कानून को लेकर प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को धन्यवाद दिया गया। बैठक में कोरोना के दौरान किए गए सरकार और संगठन के सेवा कार्यों को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया। मप्र में कोरोना की रोकथाम के लिए शिवराज सरकार ने कदम उठाए। संगठन कार्यकर्ताओं ने जान पर खेलकर सेवा की। सरकार ने ऑक्सीजन के लिए हर स्तर पर प्रयास किए। दो मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई गई। सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया।

कार्यसमिति के दौरान और इससे पहले सत्ता और संगठन के पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें हुईं, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिनमें मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने और निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां प्रमुख रहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आने वाले दिनों में मंत्रियों को जिलों का प्रभार दे सकते हैं। इसके साथ ही निगम-मंडलों में नियुक्तियां भी जल्दी होने के संकेत मिले हैं। ऐसे अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बंद कमरे में बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि निगम-मंडलों में नियुक्तियां पिछले साल नवंबर से टलती आ रही हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 23 जून को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से अलग-अलग बैठक की थी। बैठक में सिंधिया ने निगम-मंडलों में नियुक्तियों को लेकर मंथन हुआ था। इससे पहले मुख्यमंत्री ने निगम-मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य पदों की जानकारी ली थी। माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी के साथ बैठक होने के बाद अब सरकार जल्दी ही आदेश जारी करेगी।

● **कुमार राजेन्द्र**

वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकार्ड मप्र के नाम

कोविड-19 टीकाकरण कें
CIVIL SU
PEPE JEANS

यह संतोष और गर्व का विषय है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। ग्लोबल वैक्सीनेशन ट्रैकर के अनुसार टीकाकरण के मामले में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी आदि को पीछे छोड़ दिया है। इस ट्रैकर में चीन को जगह नहीं मिली तो इसीलिए क्योंकि जिस तरह उसके कोविड रोधी टीके अविश्वसनीय हैं, उसी तरह टीकाकरण के उसके आंकड़े भी। वहीं एक दिन में 16 लाख 95 हजार 592 लोगों का वैक्सीनेशन कर मप्र वर्ल्ड रिकार्डधारी बना है। लंदन की संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड माना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भेजा है। एक दिन में मप्र में करीब 17 लाख आबादी को टीका लगाया गया। इतनी आबादी को वैक्सीनेट करने वाला मप्र दुनिया का पहला राज्य बन गया है। रिकॉर्ड में बताया गया है कि मप्र में एक दिन में किया गया ये वैक्सीनेशन भूटान और मॉरीशस की कुल आबादी के बराबर है।

दरअसल, योग दिवस 21 जून से देशभर में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मोहम्मद सुलेमान ने योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर कोरोना से सुरक्षा के लिए टीकाकरण महाअभियान को रिकार्डधारी बनाया। एक दिन में 16 लाख 95 हजार 592 लोगों ने वैक्सीन लगवाकर सुरक्षा कवच प्राप्त किया। इसमें से 16 लाख 12 हजार 629 लोगों ने वैक्सीन की प्रथम डोज और 82 हजार 963 ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। एक दिन में हुए कुल वैक्सीनेशन में 18 से 45 वर्ग के युवाओं की सर्वाधिक भागीदारी 70 प्रतिशत रही।

टीकाकरण महाअभियान में 60 वर्ष से अधिक आयु के एक लाख 22 हजार 186 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इनमें से 74 हजार 404 ने वैक्सीन का प्रथम डोज और 47 हजार 782 ने दूसरी डोज लगवाई। इसी प्रकार 45 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में 2 लाख 68 हजार 717 ने वैक्सीनेशन करवाया। इनमें 2 लाख 46 हजार 365 ने वैक्सीन की प्रथम डोज और 22 हजार 352 ने दूसरी डोज लगवाई। अभियान में 18 वर्ष से 45 आयु वर्ग के 12 लाख 98 हजार 670 युवाओं ने वैक्सीनेशन करवाया। इसमें 12 लाख 91 हजार 237 युवाओं को वैक्सीन का प्रथम डोज और 7,433 को दूसरा डोज लगाया गया। इसके अतिरिक्त 2400 हेल्थ वर्कर्स और 3619 फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन हुआ। धन्य है मप्र की जनता, जिसने वैश्विक महामारी कोरोना से अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन को व्यापक पैमाने पर स्वीकार किया। मात्र एक दिन में 16 लाख 95 हजार लोगों ने कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्राप्त कर न केवल अपनी और अपनों की जान बचाने का प्रण लिया बल्कि पूरे देश को जन-सहभागिता का एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। प्रदेशवासियों के इस जज्बे को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासन-प्रशासन के कार्यों में जिस तरह से जनभागीदारी को बढ़ावा दिया है। उसे प्रदेश की जनता ने सहज रूप से स्वीकारते हुए अच्छे परिणाम भी दिए हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी प्रदेशवासियों ने राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जब प्रदेश में चरम पर था, उस समय आमजन और सामाजिक संस्थाओं ने कोरोना वॉलेंटियर्स के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संकटकाल में जनभागीदारी से हुए अभूतपूर्व कार्यों ने मप्र के जनभागीदारी मॉडल को पूरे देश में अनुकरणीय बनाया। अनेक राज्यों ने मप्र के जनभागीदारी मॉडल को अपने राज्य में अपनाने का मन बनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण महाअभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से हम प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वैक्सीनेशन से छूटे हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित किया जाना है, इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों में सभी सहभागी बने।

● लोकेंद्र शर्मा

प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों की सक्रियता रंग लाई

कोरोना महामारी को हराने के लिए प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिन-रात एक कर शहर से लेकर गांवों तक सक्रियता से कार्य किया है। इसमें मुख्य भूमिका अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान की रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें जो टारगेट दिया उसे उन्होंने बखूबी पूरा किया। आज मप्र 2 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण कराने वाले प्रदेशों में शामिल हो गया है।इसमें शासन-प्रशासन के साथ ही आमजन की भी बराबर भागीदारी है। लोगों की सक्रियता के कारण ही इस महामारी पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका है। इस कार्य में प्रशासनिक अफसरों के साथ-साथ गांव के सरपंच और सचिव सहित अन्य जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ नागरिकों ने भी चुनौती लेकर कार्य किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आव्हान पर प्रदेशवासियों ने टीकाकरण महाअभियान को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया। महाअभियान के लिए प्रदेश में 7 हजार वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे। इन सभी केंद्रों पर आम लोगों ने जिस उत्साह से भाग लिया, वह अपने आप में एक रिकॉर्ड बनकर सामने आया। प्रदेश की शहरी और ग्रामीण आबादी भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्व-प्रेरणा से अभियान में सहभागी बनी। महाअभियान में सहयोग देने वालों की सूची इतनी लंबी रही कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

नकली खाद-बीज बाजार में

मप्र में प्री मानसून की हलचल के साथ ही खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारी शुरू हो गई है। किसानों की तैयारी को देखते हुए नकली खाद-बीज बेचने वालों के साथ ही कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए हैं। इसको देखते हुए सरकार ने पहरा बैठा दिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से कहा कि वे सीधे मुझे शिकायत करें। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में किसानों के साथ ठगी नहीं होनी चाहिए।

सोया स्टेट मप्र में पिछले 4 साल से सोयाबीन की फसल खराब हो रही है। इस कारण किसान उच्च क्वालिटी का बीज तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इसको देखते हुए कंपनियां, माफिया, कालाबाजारी संगठित होकर नकली बीज के साथ ही नकली खाद किसानों को बेच रहे हैं।

शासन-प्रशासन की सक्रियता के बाद भी नकली खाद-बीज बेचने वालों पर अंकुश नहीं लग रहा है। यही कारण है कि नकली खाद-बीज बेचने वाले लगातार पकड़े जा रहे हैं। गत दिनों सेंधवा क्षेत्र की जोगवाड़ा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था से किसानों को 48 बैग अमानक खाद बेचे जाने का मामला सामने आया है। कृषि विभाग ने नकली उर्वरक भंडारण की सूचना प्राप्त होने पर आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था जोगवाड़ा पर छापामार कार्रवाई कर मौके पर 150 बैग एनपीके खाद जब्त की। वहीं बिना अनुमति उक्त खाद बनाने वाली मेसर्स पैरामाउंट एग्री टेक्नोलाजिस्ट फैक्ट्री यूनिट ग्राम सिमरोट तहसील सांवेर के प्रोपायटर प्रकाश सोनी के विरुद्ध सेंधवा ग्रामीण पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है।

उपसंचालक कृषि केएस खपेड़िया के अनुसार उक्त सोसायटी में अमानक उर्वरक संग्रहित होने की सूचना मिलने पर कृषि विभाग के पदाधिकारियों की टीम बनाकर उक्त संस्था पर छापामार कार्रवाई की गई। टीम में सम्मिलित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भीकासिंह सिसौदिया, उर्वरक निरीक्षक अनिता खरतिया ने संस्था के गोदाम का निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर 150 बैग पैरामाउंट एग्री टेक्नोलाजिस्ट फैक्ट्री यूनिट ग्राम सिमरोट तहसील सावेर के संग्रहित हैं। इस संबंध में संस्था के प्रबंधक सीताराम पाटीदार ने पूछताछ में बताया कि कंपनी द्वारा उन्हें शासकीय अनुमति पत्र नहीं दिया गया है। इस पर समिति के सदस्यों ने संस्था के स्टाक बुक, बिल बुक व अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। इस पर समिति के सदस्यों ने उच्च स्तर पर उक्त जानकारी देते हुए जहां संग्रहित 150 बैग उर्वरक जब्त किया, वहीं इसे बनाने वाले सांवेर के प्रोपायटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन भी दिया है। साथ ही संस्था प्रबंधक के विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित की है।

कृषि उपसंचालक केएस खपेड़िया कहते हैं कि जोगवाड़ा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था से किसानों को 48 बैग अमानक खाद बेचा जाना पाया गया है। वहीं मौके से 150 बैग अमानक खाद जब्त किया गया। कंपनी के प्रोप्रायटर के विरुद्ध एफआईआर के लिए ग्रामीण पुलिस को आवेदन दिया गया है। संस्था प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला सहकारी बैंक को लिखा है।

बीज के नाम पर ऊंचा दाम

कृषि मंत्री कमल पटेल भी इस बात को मानते हैं कि मप्र में नकली खाद-बीज की जमकर कालाबाजारी हो रही है। वह कहते हैं कि सरकार ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि वे किसानों तक खाद-बीज पहुंचने से पहले उसकी पड़ताल कर लें। मंत्री का कहना है कि शासन और प्रशासन की सतर्कता से कई नकली कारोबारी पकड़ में आ चुके हैं। गत दिनों राजधानी भोपाल में एक ऐसा कारोबारी पकड़ाया जो बीज के नाम पर राजस्थान से सोयाबीज लाकर ऊंचे दाम पर बेच रहा था। जानकारी के अनुसार भोपाल जिले की हुजूर तहसील के अंतर्गत ग्राम परवलिया निवासी पवन जैन बड़ी मात्रा में राजस्थान से सोयाबीन लाकर उसे छानकर किसानों को बीज के नाम पर बेच रहा था। सूत्रों ने बताया कि मप्र के व्यापारी रोज राजस्थान से सोयाबीन की गाड़ी बुला रहे हैं और उसे मंडी से ज्यादा दाम पर बेचकर व्यापारी मोटा मुनाफा कमा रहा है। प्रदेश में सोयाबीन के बीज के साथ ही खाद की भी कालाबाजारी जोरों पर है। किसानों को नकली खाद महंगे दामों पर बेचा जा रहा है।

इसी तरह धार जिले में कई सहकारी समितियों में अमानक खाद मिले हैं। जानकारी के अनुसार सेवा सहकारी समिति कानवन में दिव्य ज्योति एग्रीटेक प्रा.लि. उत्सव एवेन्यू जावरा कम्पाउंड इंदौर के पास से प्रोम (देवपुत्र) खाद के 450 बैग जब्त किए गए। इसी तरह त्रम्बकेश्वर एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि. मेघनगर झाबुआ के पास से प्रोम (उत्तमफास) खाद के 350 बैग जब्त किए गए। वहीं एडवांस कॉप केयर इंडस्ट्रीज प्रा.लि. देवास के पास से प्रोम (एडप्रोम) खाद के 126 बैग जब्त किए गए। इसी तरह वृहत्तकार सेवा सहकारी समिति नागदा में पैरामाउंट एग्रो टेक्नालोजिस्ट 505 ओम गुरुदेव प्लाजा सयाजी होटल के पास विजय नगर इंदौर के पास से बायो एनपीके (गोग्रीन) खाद के 500 बैग जब्त किए गए।

गौरतलब है कि कृषि मंत्री को मिली शिकायत के बाद पूर्व में खंडवा में 3 नकली बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापे मारकर उन्हें सील कर दिया गया। जिन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें बालाजी, प्रगति और उत्तम बीज कंपनियां हैं। यहां से भारी मात्रा में नकली टेग और बीज बरामद किए गए हैं। वहीं राजगढ़ जिले के खिलचीपुर क्षेत्र के फतेहपुर गांव में शिवसिंह के खेत पर बने मकान में नकली डीएपी और एनपीके खाद बरामद की गई है।

कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार, सरकार की सतर्कता के बावजूद प्रदेश में हर साल अरबों रुपए के नकली खाद और बीज का काला कारोबार होता है। नकली खाद-बीज को ब्रांडेड कंपनियों के बारदाने में पैकिंग कर बेचा जाता है। हर साल पुलिस फैक्ट्रियों, गोदामों, घरों पर छापा मारकर नकली खाद-बीज पकड़ती है। लेकिन उसके बाद भी काला कारोबार चलता रहता है।

● प्रवीण कुमार

देशभर में फिर चमका इंदौर

मप्र को पिछले कुछ सालों से अवार्ड जीतने की आदत सी हो गई है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवाईस कॉन्टेस्ट 2020 में इंदौर ने जहां एक बार फिर से अपना लोहा मनवाया है, वहीं प्रदेश की अन्य 4 स्मार्ट सिटीज भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर ने भी अपनी धाक जमाई है।

स्वच्छता में 4 बार देश में परचम लहरा चुके इंदौर ने एक और उपलब्धि हासिल की है। उसे अब 'इंडिया स्मार्ट सिटीज अवॉर्ड्स कॉन्टेस्ट 2020' की 7 विभिन्न श्रेणियों में पहला स्थान मिला है। ऐसे ही, राज्यों की श्रेणी में मप्र को दूसरा स्थान मिला है। केंद्रीय मंत्री (आवास एवं शहरी कार्य) हरदीपसिंह पुरी ने वर्चुअल मीट के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में 'इंडिया स्मार्ट सिटी अवॉर्ड्स कॉन्टेस्ट 2020' के परिणाम घोषित किए। कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में स्मार्ट सिटी शहरों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर अवॉर्ड की घोषणा की गई। मप्र की 5 स्मार्ट सिटीज को विभिन्न श्रेणियों में 11 अवॉर्ड मिले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 20 अवॉर्ड श्रेणियों में से 11 अवॉर्ड मप्र को मिले हैं। इनमें से भी 7 इंदौर को मिले हैं।

कॉन्टेस्ट में मप्र की 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को पुरस्कार हासिल हुए हैं, जबकि कुल 20 में से अकेले मप्र ने 11 पुरस्कार हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मप्र को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर खुशी जाहिर की। इंदौर को सूरत के साथ ओवरऑल विनर घोषित किया गया। 5 कैटेगरी में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर को 11 अवॉर्ड मिले हैं। अर्बन एन्वॉयर्नमेंट थीम में भोपाल को चेन्नई के साथ क्लीन एनर्जी के लिए पहला पुरस्कार मिला है। इंदौर सिटी को 7 पुरस्कार मिले हैं।

इंदौर को बिल्ट एन्वॉयर्नमेंट में 56 दुकान के लिए पहला स्थान मिला। क्योंकि खान-पान व लजीज व्यंजनों के लिए 56 दुकान देशभर में प्रसिद्ध है। इसका सौंदर्यीकरण किया गया। पहले जहां रोज 5 हजार फुटफॉल हुआ करता था, सौंदर्यीकरण के बाद 15 से 20 हजार तक हो गया है। यहां अंडर ग्राउंड गैस, सीवरेज, बिजली व स्टॉर्म वाटर लाइन डाली गई है। सीसीटीवी सर्विलांस, कार्य की मॉनिटरिंग के लिए टाइमर, ग्रीन स्पेस, नो व्हीकल जोन आदि हैं।

भोपाल ने भी दिखाया दम

अर्बन एन्वॉयर्नमेंट थीम में भोपाल को चेन्नई के साथ क्लीन एनर्जी में पहला स्थान मिला है। भोपाल ने इस थीम में कई बेहतर कार्य किए हैं। बड़े तालाब पर 2.50 करोड़ रुपए की लागत से 2400 सोलर पैनल लगाए गए हैं। वहीं 44 लाख रुपए से आईएसबीटी बस स्टैंड पर 120 किलोवॉट का सोलर प्लांट लगाया गया है। माता मंदिर स्थित नगर निगम कार्यालय में 35 किलोवॉट का प्लांट भी लगाया गया, जिसकी लागत 19.11 लाख रुपए हैं। स्मार्ट सिटी सीईओ आदित्य सिंह ने बताया कि सोलर प्लांट के अलावा एलईडी लाइट, ई-बाइक व इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसके चलते अवॉर्ड मिला है। अगली बार अन्य कैटेगरी में भी पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करेंगे।

सिटी अवॉर्ड श्रेणी में इंदौर को पहला और जबलपुर को तीसरा स्थान मिला है। वहीं सैनिटेशन थीम में इंदौर को तिरुपति शहर के साथ पहला स्थान मिला है। दरअसल, स्वच्छता सर्वेक्षण में 4 साल से इंदौर पहले स्थान पर है। इसके तहत नागरिकों द्वारा स्वप्रेरणा से सूखे व गीले कचरे को अलग-अलग एकत्र करना। फिर अगली प्रकिया में इसे तीन प्रक्रियाओं रिड्यूज्ड, रीयूज व रिसाइकिल को अपनाना। इससे कचरे की गुणवत्ता में सुधार हुआ। कचरा निपटान के लिए 300 टन क्षमता का प्लांट स्थापित किया गया। इसके तहत दो प्लांट से डेढ़ करोड़ का प्रीमियम हर साल मिलने लगा। कल्चर थीम के अंतर्गत कंजर्वेशन ऑफ बिल्ट हैरिटेज के लिए इंदौर को पहला स्थान मिला। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्थान राजबाड़ा, गोपाल मंदिर, सराफा बाजार, होल्कर छत्री, कृष्णपुरा छत्री, बोलिया छत्री, लालबाग पैलेस आदि का संरक्षण व जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इन स्थानों को पुनर्जीवित कर दर्शनीय स्थानों में बदला जा रहा है। इसके लिए 80 करोड़ की राशि खर्च की गई।

इकोनॉमी थीम के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए पहला स्थान मिला है। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड व नगर निगम द्वारा तीन प्रोजेक्ट से 1.70 लाख टन कार्बन वातावरण मिलने से रोककर स्थापित प्लांट से 69 लाख रुपए कमाए हैं। भविष्य में स्लज हाईजिनेशन प्लांट, प्लास्टिक क्रेडिट, सोलर प्लांट, एलईडी लाइट व ई व्हीकल से कार्बन डाईऑक्साइड व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने पर कार्बन क्रेडिट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने से दोनों विभागों को आय होगी। इनोवेशन आइडिया अवार्ड श्रेणी के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए पहला स्थान मिला। दरअसल, कार्बन क्रेडिट एक परमिट है जो कंपनी को कार्बन डाईऑक्साइड व ग्रीन हॉउस गैसों की एक निश्चित मात्रा में उत्सर्जित करता है। कार्बन क्रेडिट ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि को कम करना राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के घटक हैं। विभिन्न कम्पोस्ट, बायोमेथेनाइजेशन व सोलर प्लांट द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित कर दिया जाता है।

आज इंदौर देश के अन्य शहरों के साथ ही मप्र की राजधानी के लिए आईना बना हुआ है। सभी शहर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वे इंदौर की तरह बनें। लेकिन जैसा जज्बा इंदौर के अफसरों और वहां के लोगों में दिखता है, वैसा अन्य किसी में नहीं दिखता है।

● **विकास दुबे**

मेगा प्रोजेक्ट्स की मंद रफ्तार

> ‘ राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल सहित कई मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण और बजट के अभाव में इन प्रोजेक्ट की रफ्तार काफी कम है। ’

50 दिन के कोरोना कर्फ्यू में निर्माण कार्यों पर रोक नहीं थी, लेकिन कहीं मटेरियल तो कहीं लेबर की दिक्कतों के कारण शहर में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक सा लग गया है। दफ्तरों में केवल 10 फीसदी स्टाफ की अनुमति होने से फील्ड में चल रहे कार्यों से जुड़ी टेक्निकल ड्राइंग तैयार करने जैसे काम नहीं होने से प्रोजेक्ट पर असर पड़ा। अब एक बार फिर इन कामों को गति देने के प्रयास शुरू हो गए हैं।

एम्स से सुभाष नगर क्रॉसिंग तक 6.2 किमी रूट के सिविल वर्क का बजट 247 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट में कोरोना कर्फ्यू के कारण ब्रेक सा लग गया। कर्फ्यू की घोषणा से पहले अलकापुरी से हबीबगंज क्रॉसिंग तक गर्डर लॉन्चिंग की तैयारी थी। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में काम शुरू होता उसके पहले ही कर्फ्यू लग गया। लेबर से जुड़ी समस्याओं के कारण गर्डर लॉन्चिंग का काम रोकना पड़ा। ग्रीन पेट्रोल पंप को पीछे शिफ्ट करने के लिए टैंक आदि निर्माण करने का काम भी रुक गया। इस रूट पर मेट्रो संचालन के हिसाब से देखें तो 25 प्रतिशत काम पूरा हो सका है।

हालांकि कोरोना कर्फ्यू खत्म होते ही काम शुरू हो गए हैं। अलकापुरी गेट नंबर 2 और गायत्री मंदिर के पास गर्डर लॉन्चिंग शुरू हो गई हैं। हबीबगंज रेलवे क्रॉसिंग पर मेट्रो के पिलर के लिए रेलवे ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अब यहां मेट्रो के गुजरने के लिए एक आरओबी बनेगा। इसके लिए नए सिरे से टेक्निकल ड्राइंग बनाई जा रही है। सुभाष नगर आरओबी लगभग एक साल से तैयार है। लेकिन इसकी एप्रोच रोड को मेन रोड से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो के पिलर को रोटरी की तरह उपयोग किया जाना है। जब तक मेट्रो की गर्डर लॉन्चिंग पूरी नहीं हो जाती, सुभाष नगर आरओबी पर ट्रैफिक चालू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी वजह से पीडब्ल्यूडी ने फिनिशिंग के काम रोक रखे हैं। पीडब्ल्यूडी के अफसरों के अनुसार अधिकतम दो माह के भीतर यहां ट्रैफिक शुरू हो सकता है।

हबीबगंज रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम लगभग 95 फीसदी पूरा हो चुका है। हालांकि चार महीने पहले कहा गया था कि मार्च अंत तक यह तैयार हो जाएगा और प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इस समय फिनिशिंग के काम चल रहे हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार प्रोजेक्ट में लगी लेबर के निवास की व्यवस्था कंपनी ने ही की है, इसलिए लेबर की कमी नहीं आई और मटेरियल भी पहले से साइट पर रखा हुआ है, इसलिए कोरोना के कारण काम पर असर नहीं पड़ा।

गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक करीब 2.7 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए फरवरी में भूमिपूजन हुआ। मार्च में जमीन पर काम शुरू हुआ, काम गति पकड़ता इसके पहले अप्रैल में कोरोना कर्फ्यू लग गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए फील्ड में लेबर की संख्या कम रखी गई। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर (ब्रिज) संजय खांडे कहते हैं, हमने काम की गति को बरकरार रखने की कोशिश की है। दो साल की तय समय सीमा में कॉरिडोर तैयार हो जाएगा।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

तेजी से शुरू हुआ, फिर 5 माह से अटका काम

गायत्री मंदिर से लेकर मानसरोवर होते हुए हबीबगंज नाके के गणेश मंदिर तक शहर के सबसे लंबे फ्लाईओवर का काम तो तेजी से शुरू हुआ, लेकिन कोविड के चलते बीते 5 माह से काम लगभग बंद है। रीवा की कंपनी को काम दिया हुआ है और अब अफसर काम शुरू कराने गुहार लगा रहे हैं। 140 करोड़ रुपए से करीब ढाई किमी लंबे फ्लाईओवर का काम दो साल में पूरा होना है, जिसमें से 30 फीसदी समय बीत चुका हैं। ऐसे में ये प्रोजेक्ट भी शहर के अन्य प्रोजेक्ट की तरह लेटलतीफी में उलझता नजर आ रहा है। 2020 के आखिर में इसके लिए एजेंसी तय हुई थी। केंद्र सरकार ने सेंट्रल रोड फंड (सीआरएफ) से इसके लिए राशि तय की हुई हैं। कही राशि लैप्स न हो जाए, इसलिए इसका काम जल्दी से शुरू हुआ, अब ये बेहद धीमा है। फ्लाईओवर की कुल लागत 140 करोड़ रुपए है। इसमें 120 करोड़ का सिविल वर्क पर खर्च है। इसका निर्माण गणेश मंदिर से मानसरोवर होते हुए प्रगति पेट्रोल पंप, बोर्ड ऑफिस, गुरुदेव गुप्त चौहारा, गायत्री मंदिर तक होगा। ब्रिज गणेश मंदिर से नर्मदा अस्पताल के मोड़ तक 400 मीटर के हिस्से में बीआरटीएस दो भागों में बांट देगा। इससे इतनी डेडिकेटेड लेन खत्म कर दी गई है।

ऊर्जा से भरपूर हैं माननीय ऊर्जामंत्री

वाकई मप्र अजब है, गजब है। इस बार तो एक मंत्रीजी खासे चर्चा में हैं। अपने ऊल-जुलूल कामों के कारण सुर्खियों में रहने वाले इन मंत्रीजी की करतूतों को देखकर अब तो लोग कहने लगे हैं कि क्या मंत्रीजी बेकाम के हैं, जो अजब-गजब काम में समय गंवा रहे हैं।

मप्र के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जबसे मंत्री (कमलनाथ शासन से लेकर अब तक) बने हैं, वे सुर्खियां बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जनता के हित के नाम पर चप्पल त्यागकर नंगे पैर घूमने वाले मंत्रीजी अब तो ऐसे-ऐसे कारनामे कर रहे हैं, जिससे जनता भी अचंभित हो रही है। कभी ट्रांसफार्मर सफाई के लिए पोल पर चढ़ जाते हैं, तो कभी गांव में बिजली बहाली के लिए खटिया पर सो जाते हैं। मंत्रीजी की कार्यप्रणाली को अब लोग दिखावा मानने लगे हैं। दरअसल, मंत्री का एक संवैधानिक ओहदा होता है। मंत्री को प्रोटोकॉल के अनुसार रहना पड़ता है। अगर कहीं खामियां नजर आती हैं, तो मंत्री अधिकारियों को उसका समाधान करने के लिए निर्देश-आदेश देते हैं। लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर तो खुद काम में जुट जाते हैं। ऐसे में लोग व्यंग्य करने लगे हैं कि बे'काम' हैं का मंत्रीजी?

अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तोमर ने जनहित के लिए खटिया बिछा दी। दरअसल, मंत्रीजी विगत दिनों भोपाल से सुबह 4 बजे ट्रेन से ग्वालियर पहुंचे और अपने आवास जा रहे थे, तो हरिहर नगर में अंधेरा देखकर रुक गए। ग्रामीणों ने मंत्रीजी को स्थिति से अवगत कराया तो मंत्रीजी ने वहां खाट बिछाकर डेरा डाल दिया। मंत्रीजी के पहुंचने की खबर सुनते ही बिजली कंपनी के अधिकारी भी पहुंच गए और गांव की बिजली दुरुस्त करने लगे। जब तक काम चलता रहा मंत्री प्रद्युम्न सिंह खटिया डालकर मौके पर ही लेट गए। कॉलोनी में तीन खंभे और 200 मीटर लाइन डालने में साढ़े छह घंटे लग गए। जब कॉलोनी के घर रोशन हो गए तब मंत्रीजी रवाना हुए। इससे पहले विधानसभा क्षेत्र में जनता की समास्याओं का जायजा लेने ग्वालियर के मोती झील इलाके में पहुंचे तो उनकी नजर ट्रांसफार्मर और खंभे पर चढ़ी बेल (पौधे) पर गई। ट्रांसफार्मर पर ऊपर तक घास होने की वजह से बिजली में लगातार गड़बड़ी आ रही थी। मंत्रीजी लोगों की इस समस्या का निवारण करने के लिए खुद सीढ़ी लगाकर खंभे पर चढ़ गए। इसके बाद उन्होंने ट्रांसफार्मर और तारों से बेल, घास-फूस को हटाया। यही नहीं नीचे उतरने के बाद ऊर्जा मंत्री ने ट्रांसफार्मर के रख-रखाव को लेकर अफसरों को भी जमकर फटकार लगाई। मंत्रीजी कभी रात को बिजली कार्यालय में घूमते नजर आते हैं तो कभी कॉल सेंटर में फोन लगाकर लोगों से स्थिति का जायजा लेते हैं।

मंत्रीजी ऐसे कई काम कर चुके हैं, जो खासे चर्चा में रहे हैं। कभी मजदूरों को माला पहनाकर उनके पैरों में अपना सिर रखकर ढोक लगाते हैं, तो कभी सड़क पर झाड़ू लगाने, शौचालय साफ करने, नाला साफ करने या किसी के पैर छूते देखे जाते हैं। बता दें कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले विधायकों में से एक हैं और वो कमलनाथ की कांग्रेस सरकार में भी मंत्री थे और भाजपा में शामिल होने के बाद शिवराज सरकार में भी उन्हें ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को सफाई का ऐसा भूत चढ़ा है कि वे जहां जाते हैं वहीं सफाई करने में जुट जाते हैं। इसके लिए न जगह देखते हैं न समय। सफाई के लिए मुहिम चलाना अच्छी बात है, लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करना भी काबिल-ए-तारीफ है। लेकिन एक मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए आपका कभी नाली में उतर जाना तो कभी स्टेशन के शौचालयों को साफ करना ये बात हजम नहीं होती है। अहम बात ये भी है कि जिस विभाग की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है क्या उसमें सारे काम पूरे हो चुके हैं, जो आप साफ-सफाई करने सड़कों पर उतर रहे हैं। इस पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या झाड़ू लगाने या नालियां साफ करने के लिए जनता ने आपको मंत्री बनाया था। अगर नहीं तो

सिस्टम में फाल्ट या ज्यादा करंट में हैं माननीय

प्रदेश सरकार का पूरा सिस्टम फाल्ट में है या माननीय ज्यादा करंट में हैं, यह सवाल इन दिनों प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका से लेकर जनता के मन में भी बना हुआ है। पोल पर मंत्रीजी का चढ़कर झाड़ बेल काटना, खटिया डालकर बिजली आने का इंतजार करना, विधायक का अंचल के सबसे बड़े अस्पताल में खराब एसी को ठीक कराने के लिए रात तक डेरा डालना, यह क्या है। ये सरकार के लिए भी सोचने का विषय है। नगर निगम, जिला प्रशासन, बिजली कंपनी या कोई दूसरा विभाग, बात सिर्फ बुनियादी सुविधाओं की है, जो जनता को चाहिए। इन सब के लिए ही माननीयों के अड़ने की नौबत आए तो सिस्टम पर सवाल उठना जाहिर सी बात है। जिस काम के लिए विभाग है, अफसर और उनका अमला है, उन्हें चिंता करना होगी। जनता के लिए सब है तो समय पर और सही क्यों नहीं मिलता। जिला सरकार के मुखिया को दुरुस्त सिस्टम तैयार करना होगा।

फिर ये जिसका काम है उसे करने दीजिए। वो नहीं करता तो ये उस विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं...! क्योंकि मंत्रीजी आपके घूमने, खाने, रहने का पैसा जनता के टैक्स के पैसों से जाता है। ये पैसा नाली साफ करवाने के लिए जनता नहीं चुकाती है।

मंत्रीजी को तो लगता है जैसे लोकप्रियता का भूत सवार हो गया है। ये वही मंत्री हैं जो नाली, शौचालय, सड़क तो साफ करते ही हैं, खुद बिना हेलमेट के गाड़ी चलाकर बाद में चालान कटवाते हैं। मंत्रीजी पूर्व में कलेक्टर और कमिश्नर का घेराव करने के लिए तरह-तरह के उपक्रम कर चुके हैं। अभी हाल ही में मंत्रीजी इंदौर में पेट्रोल की महंगाई पर लंबा-चौड़ा भाषण पेल गए, जो न जनता को अच्छा लगा, न उनकी सरकार को। अपने अजब-गजब कारनामों के कारण चर्चा में रहने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सलाह दी है कि अगर पेट्रोल-डीजल महंगा है तो साइकिल क्यों नहीं चलाते। इसके साथ उन्होंने तो मंत्रियों को भी साइकिल चलाने की सलाह दी है। मंत्री तोमर ने कहा- साइकल चलाओ। यह सिर्फ आम जनता नहीं हम सभी मंत्रियों के लिए ये भी कह रहा हूं। साइकिल चलाओ सेहत अच्छी रहेगी। छह गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाले मंत्रीजी दी आम जनता को साइकिल से चलने की नसीहत दी है।

यही नहीं चुनाव के समय जनता को माई-बाप कहने वाले नेता ओहदेदार होते ही जनता के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ताजा मामला राजधानी भोपाल में सामने आया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने परेशान अभिभावकों की समस्या का समाधान तो किया नहीं, उल्टा ये बोले कि मरना है तो मर जाओ। मप्र के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। पेरेंट्स ने आरोप लगाया है कि मंत्री उनके साथ असभ्यता से पेश आए और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ये पेरेंट्स निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे। पेरेंट्स का कहना है मंत्रीजी ने उनकी समस्या का समाधान तो किया नहीं, उल्टा ये बोले कि मरना है तो मर जाओ।

भोपाल में गत दिनों बड़ी संख्या में अभिभावक प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे थे। ये लोग निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत करने गए थे। पेरेंट्स का कहना है बातचीत के दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार अचानक गुस्से में आ गए। अभिभावकों पर आग बबूला होकर उन्होंने कहा कि आप सभी को जहां भी शिकायत करनी है शिकायत कर दीजिए। आप लोगों को कोई आंदोलन करना है तो आंदोलन कर लीजिए। आप लोगों को मरना है तो मर जाइए।

जनता के वोट पर मंत्री बनने वाले नेता ओहदेदार होते ही इस कदर बेलगाम हो रहे हैं कि उन पर नकेल नहीं कस पा रही है। भाजपा संगठन और संघ कई बार हिदायत दे चुका है कि मंत्री, विधायक और नेता जनता को भगवान मानकर काम करें, लेकिन सत्ता की कुर्सी मिलते ही मंत्री ऊल-जुलूल बोलने लगते हैं। अभी तक मप्र की राजनीति में दिग्विजय सिंह को अनियंत्रित टिप्पणी करने के लिए जाना जाता था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार में कई मंत्री बेलगाम बोल बोलने के लिए ख्यात होते जा रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में संपन्न प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सभी को नसीहत दी गई।

● अरविंद नारद

यशोधरा के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए मंत्री

कभी नाली, कभी बिजली के खंभे पर कलाबाजी दिखाने वाले मंत्रीजी की ऊर्जा उस समय डाउन हो गई, जब वे विभाग का प्रेजेंटेशन कैबिनेट में दे रहे थे। दरअसल, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने विभाग का प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उस समय वे असमंजस में दिख रहे थे। इस पर यशोधरा राजे सिंधिया ने उनसे कहा कि आप अपने प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए, इधर-उधर देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में तोमर यशोधरा राजे की तरफ देखने लगे तो वे नाराज हो गईं। तल्ख लहजे में उन्होंने तोमर से कहा-'मेरी तरफ देखकर क्यों अपने काम गिना रहे हो, क्या धमकी दे रहे हो।' बताते हैं कि तोमर जब प्रेजेंटेशन देते समय यशोधरा की तरफ देख रहे थे तो उनकी आवाज तेज थी। दोनों के बीच बहस बढ़ी तो मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए तोमर से कहा कि शांत रहकर अपनी बात रखिए। कैबिनेट के ठीक बाद ही बिजली महकमे का यह प्रेजेंटेशन था, जो दो घंटे चला। इसे तोमर और विभाग के प्रमुख संजय दुबे ने दिया। इस दौरान अन्य मंत्रियों ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान तोमर ने कहा कि किसानों को करोड़ों की सब्सिडी दे रहे हैं, इसके लिए राज्य सरकार राशि की व्यवस्था करे। इसमें कटौती कर सकते हैं। इसकी गुंजाइश है। इस पर यशोधरा ने कहा- ये सब तो ठीक है, लेकिन बिजली विभाग की इंटरनल वर्किंग (कार्यशैली), एफिसिएंसी (दक्षता) और समय पर काम करने, बिल देने और घाटा करने के बारे में कुछ नहीं है? सिर्फ खंभे पर चढ़ जाने से क्या कुछ होने वाला है? प्रद्युम्न बोले- हमें अपना प्रेजेंटेशन तो पूरा कर लेने दीजिए, बीच में मत बोलिए। आप क्यों टोक रही हैं। इसके बाद यशोधरा की तरफ देखकर प्रद्युम्न प्रेजेंटेशन देने लगे। यशोधरा ने कहा- ये तो ठीक नहीं है। प्रेजेंटेशन में विभाग की वर्किंग के बारे में कुछ नहीं है? प्रद्युम्न तेज आवाज में बोले- आप बैलेंस शीट देख लीजिए। एक साल में क्या सुधार हुआ है, वह भी भेज देता हूं। लेकिन, अभी आप शांत रहें। यशोधरा गुस्से में बोलीं- मेरी तरफ देखकर तेज आवाज में क्यों बोल रहे हो। जब मुख्यमंत्री बैठे हैं तो उनकी तरफ देखकर प्रेजेंटेशन दो। क्या धमकी देना चाहते हो। मेरी तरफ न देखें। दरअसल, प्रद्युम्न सिंह तोमर बिना तैयारी के प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में उपस्थित थे। उधर, यशोधराराजे प्रदेश में बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित थीं। वह चाहती थीं कि मंत्री इस विषय पर कुछ बताएं, लेकिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे।

'कुछ साल पहले तक मप्र की राजनीति में कद्दावर नेताओं में शुमार कैलाश विजयवर्गीय अब प्रदेश में अपनी नई भूमिका की तलाश में जुट गए हैं। अभी तक मालवा क्षेत्र में सीमित रहे विजयवर्गीय अब प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं।'

भाई को नई भूमिका की तलाश

बंगाल में भाजपा भले ही सत्ता तक नहीं पहुंच सकी हो, लेकिन विधानसभा सीट और मत प्रतिशत में भारी बढ़ोतरी हुई तथा वहां भाजपा की जमीन मजबूत हुई है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का भी बड़ा योगदान है। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद उनकी नई भूमिका को लेकर बंगाल से लेकर मप्र तक कयास का दौर जारी है। उन्हें राज्यसभा भेजने से लेकर राष्ट्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपने की चर्चा है। वहीं वे मप्र में अपने पांव जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं।

दरअसल, विजयवर्गीय को 2014 में तब प्रभारी बनाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में भेजा गया था, जब मप्र में उनकी राजनीतिक पकड़ तेजी से मजबूत हो रही थी। हरियाणा में भाजपा ने 2009 के 4 सीटों के आंकड़े से छलांग लगाते हुए 2014 में 44 सीटें हासिल कर सरकार बनाई। इस चुनाव में मत प्रतिशत भी 9 से बढ़कर 33.3 हो गया। इस जीत में शामिल विजयवर्गीय के चुनावी कौशल ने केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान खींचा और 2015 में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाते हुए बंगाल का प्रभारी बनाया गया। तब वहां भाजपा शून्य पर थी। संगठन भी बेहद कमजोर था। इस चुनौती को विजयवर्गीय ने अवसर माना और संगठन को मजबूत करते हुए भाजपा को जन-जन तक पहुंचाया, जिसके चलते 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 42 में से 18 सीटें जीतीं। लेकिन विधानसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं आने के कारण विजयवर्गीय अब मप्र में सक्रिय हो गए हैं।

कैलाश विजयवर्गीय की मप्र में वापसी की संभावना को लेकर सियासी हलचल की कई वजह हैं। बंगाल में सभी 292 विधानसभा क्षेत्रों तक कई बार पहुंचने के बीच भी उनका मप्र, विशेषकर मालवा से लगाव बरकरार रहा। उन्होंने बंगाल में संगठन का नेटवर्क वार्ड स्तर तक बनाया, लेकिन मप्र की सियासत से कभी दूर नहीं रहे। कोरोना का संकट काल हो या प्राकृतिक विपदा या कोई पारंपरिक आयोजन, सभी में विजयवर्गीय की मौजूदगी बनी रही। कोरोना संकट में उन्होंने अंबानी परिवार से लेकर कई उद्यमियों से निजी संपर्क के जरिए ऑक्सीजन और दवाओं आदि की व्यवस्था कराई। उन्होंने इंदौर में पहला निजी कोविड सेंटर स्थापित कराया। चूंकि वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के करीबी हैं और बंगाल में उन्होंने जमीन मजबूत की है तो उनका कद बढ़ना तय है। ऐसे में पार्टी उन्हें मप्र में मौका देती है तो सत्ता और संगठन में व्यापक पैमाने पर असर दिखाई देगा।

पश्चिम बंगाल चुनाव में अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन न होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय फिलहाल छटपटा रहे हैं। चुनाव के बाद उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं मिली है, इसलिए इन दिनों बे दिग्गज नेताओं से मिलकर सक्रियता दिखा रहे हैं। गत दिनों वे राजधानी भोपाल में थे। यहां पहले उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत से मिले। फिर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने जा पहुंचे। प्रदेश की सियासत में कैलाश का कद लगातार कम हुआ है। यही नहीं मालवा क्षेत्र में सीमित रहने वाले विजयवर्गीय ग्वालियर भी पहुंचे और वहां भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया से मुलाकात की। हालांकि वे पवैया के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। लेकिन इसे उनकी राजनीति का कदम माना जाता है। मौजूदा मंत्रिमंडल में भी कैलाश का कोई समर्थक मंत्री नहीं है। वे अपने कोटे से एक भी मंत्री नहीं बनवा सके। इंदौर से रमेश मेंदोला को मंत्री बनाने के प्रयास विफल रहे। इससे पूर्व पिछले कार्यकाल में भी वे किसी को मंत्री नहीं बनवा सके थे।

पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कैलाश ने कहा था कि वह मप्र से बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी मौजूदा छटपटाहट और गतिविधियां बताती हैं यह बस बयान ही था। कैलाश के लिए इंदौर में बेबसी भी बड़ी वजह है। वहां की सियासत और प्रशासनिक निर्णयों में उनकी बात नहीं सुनी जा रही। कोरोना पीक पर था, तब वे पश्चिम बंगाल चुनाव से लौटे, तो उन्होंने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बाजार खोलने की बात कही, लेकिन इसे बिल्कुल नहीं सुना गया। इससे पहले भी कई बार कैलाश ने इंदौर शहर की व्यवस्था के लिए कई बातें कही, लेकिन उन्हें अनदेखा किया गया। इस कारण कई बार ट्वीट करके कैलाश को नाराजगी दिखानी पड़ी, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ। मंत्री तुलसी सिलावट के भाजपा में आने के बाद इंदौर में नया गुट बन गया है। तुलसी से विवाद की स्थिति में कैलाश को ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी अदावत लेना होगी। सिलावट के इंदौर में मजबूत होने से कैलाश गृह क्षेत्र में ही घिर गए हैं। कैलाश दिग्गजों से मुलाकात कर अप्रत्यक्ष रूप से सियासी वजन बढ़ाने की जद्दोजहद कर रहे हैं।

मंसूबों पर फिरा पानी

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनती, तो कैलाश का कद बढ़ जाता। वहां लंबे समय से वे भाजपा को सत्ता में लाने लगे थे। शिकस्त के बाद उनकी उड़ान पर लगाम लग गई। ऐसे में प्रदेश की सियासत में भी उनकी आवाज अब अनसुनी रह जाती है। बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को अप्रत्याशित जीत मिली थी। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक काफी उत्साहित थे। उस वक्त भी लोगों ने मांग की थी कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाए। उस वक्त मप्र की राजनीति में इसकी खूब चर्चा थी कि केंद्र में कैलाश को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कैलाश के समर्थक अब दबी जुबान में इतना जरूर कहते हैं कि भाजपा तय करेगी, उन्हें आगे क्या करना है। कैलाश विजयवर्गीय मप्र की राजनीति से करीब 6 सालों से दूर हैं। हालांकि वे सियासी रूप से हस्तक्षेप रखते हैं लेकिन उतने सक्रिय नहीं हैं। अभी वह किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। प्रदेश में पहले से ही कई कद्दावर नेता पद की लालसा में बैठे हैं। अगर कैलाश मप्र की राजनीति में वापस लौटते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर चर्चा जोरों पर है।

● जितेंद्र तिवारी

आयुध कंपनियों का निगमीकरण शुरू

केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के अंतर्गत देशभर की 41 आयुध निर्माणियों को 7 कारपोरेट कंपनियां बनाकर उनके अधीन कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से शहर की चारों आयुध निर्माणियां भी प्रभावित होंगी। इस निर्णय को तीनों कर्मचारी महासंघों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करार दिया है। उन्होंने इसके विरोध में लंबी हड़ताल की चेतावनी के साथ-साथ न्यायालय की शरण लेने की बात कही है।

सरकार की नीति के तहत जो कंपनियां गठित होंगी उनमें सेना के लिए हथियारों का उत्पादन करने वाली जबलपुर की आयुध निर्माणी खमरिया (ओएफके), गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ), वीकल फैक्ट्री जबलपुर (वीएफजे) और ग्रे आयरन फाउंड्री (जीआईएफ) समाहित होंगी। जो 7 प्रस्तावित कंपनियां हैं, उनमें 4 के अधीन शहर की निर्माणियां होंगी। इसका असर 15 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों पर भी होगा। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। शहर की आयुध निर्माणियों का कई क्षेत्रों में बड़ा योगदान रहा है। इनका अपना इतिहास है। जीसीएफ की स्थापना अंग्रेजों ने 1904 में की थी। तो ओएफके भी अंग्रेजी हुकूमत के जरिए 1942 में अस्तित्व में आई। वीएफजे और और जीआईएफ जरूर आजादी के बाद शहर में आईं, लेकिन उनका योगदान भी कम नहीं है। निर्माणियों के साथ इन सभी का हजारों वर्गमीटर का इस्टेट एरिया भी है। निगम बनने से इनका स्वरूप ही बदल जाएगा।

सेना के लिए हथियार बनाने वाली जबलपुर की चारों आयुध कंपनियों को अब 4 कंपनियां चलाएंगी। अभी तक इन कंपनियों का संचालक रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माणी बोर्ड करता था। रक्षा मंत्रालय ने देश की 41 आयुध निर्माणियों को 7 भागों में विभक्त कर निगम में तब्दील करने का फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय के इस निर्णय से कर्मचारी संगठनों में आक्रोश है और उन्होंने क्रमित भूख हड़ताल का निर्णय लिया है। जबलपुर की चारों आयुध निर्माणियों में गन कैरिज फैक्ट्री और ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया का निर्माण तो अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था। वहीं जीआईएफ व वीएफजे देश की स्वतंत्रता के बाद यहां स्थापित हुई थीं। चारों फैक्ट्रियों का सेना के वाहन से लेकर गोला-बारूद और तोप आदि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब केंद्र सरकार की ओर से बनाई जाने वाली कंपनियों के अधीन इनका संचालन होगा। इसी को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा है।

सरकार ने कहा- होगा फायदा

उधर सरकार ने इस फैसले को निर्माणियों के लिए हितकर बताया। जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनमें कहा गया है कि सातों कंपनियां सरकारी होंगी। कर्मचारियों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। दावा किया जा रहा है कि निगमीकरण से उनकी क्षमता में इजाफा होगा। उत्पादन बढ़ेगा। सैन्य हथियारों की ज्यादा लागत का सवाल भी नहीं रहेगा। उन्हें नई तरह की सैन्य सामग्री बनाने का अवसर मिलेगा। यही नहीं इन निर्माणियों में बनने वाले हथियारों का उपयोग पहले की तरह देश की सेना करेगी। वहीं विदेशों में भी निर्यात के अवसर मिलेंगे। हालांकि इन लाभों को कर्मचारी महासंघ दिखावा बता रहे हैं।

कर्मचारियों का मानना है कि कंपनी बनने के बाद आयुध कंपनियों की स्थित खराब हो जाएगी।

गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ) देश की सबसे पुरानी आयुध निर्माणियों में शामिल है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। फैक्ट्री में तोप और सेना के वाहन का उत्पादन होता था। अभी दुनिया की सबसे बड़ी तोप धनुष तोप का उत्पादन हो रहा है। शारंग तोप सहित एलएफजी और मोर्टार का निर्माण भी यहीं हुआ था। फैक्ट्री में 3500 के लगभग अधिकारी-कर्मचारी हैं। आयुध निर्माणी खमरिया (ओएफके) की स्थापना 1942 में हुई थी। यहां तीनों सेनाओं के लिए बम और मिसाइल तैयार की जाती है। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यहां पर चलते हैं। इसमें अधिकतर विदेशी तकनीक पर आधारित हैं। अब उत्पादन स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यहां 6 हजार कर्मचारी-अधिकारी हैं। ग्रे आयरन फाउंड्री (जीआईएफ) देश की सबसे छोटी निर्माणियों में शामिल है। यहां पर ढलाई का काम होता है। सेना के लिए तैयार होने वाले हथियारों में उपयोगी कलपुर्जे यहां बनाए जाते हैं। सेना के लिए हैंड ग्रेनेड की बॉडी, वायुसेना के प्रमुख हथियार एरियल बम की बॉडी की ढलाई यहीं होती है। इससे पहले रेलवे के लिए भी निर्माणी काम करती थी। यहां 700 के लगभग कर्मचारी-अधिकारी हैं। वीकल फैक्ट्री जबलपुर (वीएफजे) जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान से लगी पाकिस्तानी सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए वाहनों का निर्माण करती है। फैक्ट्री में साधारण वाहनों के अलावा बुलेटप्रूफ, माइंस प्रूफ वाहनों का उत्पादन व्यापक पैमाने पर होता है। हाल ही में सैन्य वाहनों के साथ शारंग तोप का पूरा काम इसी निर्माणी में शुरू हुआ। यहां भी लगभग 3500 अधिकारी-कर्मचारी हैं।

चारों आयुध कंपनियों के निगमीकरण की प्रक्रिया शुरू होते ही कर्मचारी संगठनों में उबाल आ गया है। सरकार के निर्णय के खिलाफ तीनों महासंघ एआईडीइएफ, आईएनडीडब्ल्यूएफ व बीपीएमएस से संबद्ध लेबर यूनियन, सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक और कामगार यूनियन खमरिया के पदाधिकारियों ने गत दिनों एक बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तय की। आरोप लगाया कि 15 जून को चीफ लेबर कमिश्नर के साथ बैठक रद्द होने और फेडरेशन के बिना संज्ञान में लिए यह निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन (एआईडीइएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन पाठक ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह फैसला देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। 200 पुरानी अधोसंरचना को एक रात में स्वाहा करना गद्दारी है। इससे सभी 41 आयुध निर्माणियों के 70 हजार से ज्यादा कर्मचारियों का भविष्य संकट में आ जाएगा। उनका कहना है कि जबलपुर की अर्थव्यवस्था में इन निर्माणियों का बड़ा रोल है। युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा जरिया छिन जाएगा। उन्होंने बताया कि इस फैसले के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे।

● राकेश ग्रोवर

25 हजा
मुआवज
गैस पी

37 साल पहले यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में जो कहर बरपाया था, उसके जख्म आज भी हरे हैं। वे जख्म उस समय नासूर बन जाते हैं, जब पीड़ितों को मिलने वाली सहायता बंद हो जाती है।

विधवाओं की पेंशन पर ग्रहण

कोरोना संक्रमण जैसी वैश्विक आपदा के समय केंद्र व राज्य सरकार गरीब, किसान, श्रमिक वर्गों के लिए आर्थिक पैकेज की अनेक घोषणाएं कर रही है। परंतु इस महामारी में मप्र सरकार ने संवेदनहीनता का परिचय देते हुए गैस त्रासदी में दिवंगत हुए व्यक्तियों की निराश्रित विधवाओं को मिलने वाली प्रतिमाह एक हजार रुपए की पेंशन पिछले 18 माह से नहीं दी है। जिससे ये विधवाएं इस संकट काल में बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रही हैं। ऐसी विधवाओं की संख्या 5 हजार से अधिक है। महामारी से पहले तो ये विधवाएं सड़क पर उतरकर आंदोलन करती थीं, इससे सरकार पर दबाव बनता था। लेकिन कोरोना संक्रमण में सड़क पर आंदोलन बंद है।

दरअसल सामाजिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत राज्य शासन के भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की ओर से इन विधवा महिलाओं को एक हजार रुपए मासिक पेंशन दी जाती थी। यह पेंशन राशि केंद्र शासन द्वारा जून 2010 में गठित मंत्री समूह की अनुशंसाओं के आधार पर स्वीकृत की गई थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 30 करोड़ की राशि भोपाल कलेक्टर को उपलब्ध कराई थी। जिसमें 75 फीसदी अंशदान भारत सरकार का एवं 25 फीसदी राज्य सरकार का अंशदान है। यह पेंशन योजना मई 2011 से प्रारंभ की गई थी। इससे पहले इन विधवाओं को भरण-पोषण के लिए 750 रुपए प्रतिमाह शासन की ओर से दिया जाता था, लेकिन न्यायालय की तरफ से जब गैस त्रासदी प्रभावितों को मुआवजा देने का आदेश आया और सरकार को इन्हें मुआवजा देना पड़ा, तब सरकार ने इनको प्रतिमाह दिए जाने वाले 750 रुपए की राशि एकमुश्त काट ली। जब सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हुआ और प्रभावितों ने पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो सरकार ने विधवाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए पेंशन देने की घोषणा कर दी।

मई 2011 से यह राशि विधवाओं के बैंक खाते में आने लगी। अचानक बिना कोई कारण बताए सरकार ने वर्ष 2016 के अप्रैल माह से नवंबर 2017 तक इन पीड़ित विधवा महिलाओं का गुजारा पेंशन बंद कर दिया। काफी दबाव के बाद सरकार ने इसे दिसंबर 2017 माह से पुनः प्रारंभ किया, जो कोरोना महामारी से पहले तक जारी था। कोरोना संक्रमण जैसी वैश्विक आपदा के समय इनका सामाजिक सुरक्षा पेंशन पुनः बंद कर दिया गया, जो जून तक बंद है। इससे इन गरीब वृद्ध महिलाओं के सामने दो वक्त की रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

सामाजिक कार्यकर्ता बालकृष्ण नामदेव बताते हैं कि कोरोना महामारी के संकट के समय केंद्र व राज्य सरकार ने अन्य कमजोर वर्गों की तरह उनकी मदद करने के बजाय उनकी पेंशन ही रोक दी। अब इस उम्र में ये कहां जाएं! सरकार इन महिलाओं के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है! जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं गैस त्रासदी की बरसी पर दिसंबर 2020 में त्रासदी का दंश झेल रहीं 5 हजार विधवाओं को आजीवन पेंशन देने की घोषणा को दोहराया था।

सरकार की संवेदनहीनता का इसके अलावा भी उदाहरण है। पिछले साल लॉकडाउन के समय तीन माह तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक वृद्धों, विधवाओं, परित्यक्ता महिलाओं एवं विकलांगों को मात्र 600 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिली थी। सामाजिक न्याय विभाग के अनुसार वित्त विभाग द्वारा सामाजिक न्याय विभाग को हितग्राहियों की संख्या के अनुपात में राशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जिस कारण से बैंकों से पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सका था। जबकि उच्चतम न्यायालय का केंद्र व राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक माह की 5 तारीख के पूर्व वृद्धावस्था, विधवा पेंशन व विकलांग पेंशन की राशि बैंक खातों में हर हालत में जमा करा दी जानी चाहिए।

● **बृजेश साहू**

मुख्यमंत्री की घोषणा अधर में

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गैस पीड़ित विधवाओं को आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने 25 अगस्त, 2020 को रक्षाबंधन के दिन इन विधवा महिलाओं के आवास पर जाकर उनसे अपनी कलाई में राखी बंधवाई और बहनों को वचन दिया कि वे गैस पीड़ित विधवा कॉलोनी का नाम बदलकर जीवन ज्योति कॉलोनी करेंगे तथा यहां की सुविधाओं के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर कॉलोनी में बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करेंगे, जिससे यहां की विधवाएं सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगी। परंतु सुविधाएं तो दूर, उल्टे इनका मासिक पेंशन रोककर इन्हें नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर दिया। अब ये गैस पीड़ित लाचार महिलाएं आंसू बहा रही हैं। हालांकि पहला लॉकडाउन खत्म होते ही ये विधवाएं सड़क पर उतरी थीं। महिलाओं ने फरवरी 2021 में विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनका दिया हुआ वचन याद दिलाने के लिए खाली थाली और कटोरा लेकर मंत्रालय के गलियारों में भीख मांगी थी। इसका असर भी हुआ और आम बजट में वित्त मंत्री ने गैस पीड़ित विधवाओं के पेंशन के लिए अलग से राशि का ऐलान किया। लेकिन आधा जून बीत गया, पीड़ितों के खाते में फूटी कौड़ी भी नहीं आई। कोरोना संक्रमण के इस दौर में ये महिलाएं दो जून की रोटी के लिए परेशान हैं।

> मप्र और उप्र के बीच पाठा का जंगल डकैतों की उर्वरा भूमि के रूप में जाना जाता है। इसी जंगल में कभी ददुआ और ठोकिया का राज था। लेकिन इस समय गौरी यादव का डंका बज रहा है। गौरी यादव बहुत शातिर किस्म का डकैत है। वह जंगल से अधिक शहरी क्षेत्र में अपना समय बिताता है। समय-समय पर जंगल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है।

ददुआ-ठोकिया के बीहड़ में गौरी यादव का डंका

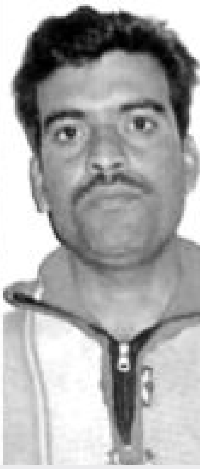

गैंग के पास अत्याधुनिक हथियार

गौरी गैंग में एक दर्जन सदस्य हैं। गैंग के सदस्यों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। इस गैंग के पास से एके-47, सेमी ऑटोमेटिक से लेकर राइफल, बंदूक तथा भारी मात्रा में कारतूस का जखीरा है। पुलिस भी जंगलों में कॉम्बिंग के समय बिना पूरी तैयारी के नहीं जाती। यही वजह भी है कि गौरी का गैंग अपने हथियारों के दम पर कई बार पुलिस से मुठभेड़ कर चुका है। चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल का कहना है कि डेढ़ लाख के ईनामी डकैत गौरी के खिलाफ अभियान जारी है। कई बार इसके मददगार व सदस्य पकड़े जा चुके हैं।

लंबे समय से अंडरग्राउंड चल रहे डकैत गौरी यादव ने एक दिन पहले चित्रकूट के जंगलों में पहुंचकर चौतरफा फायरिंग करके दहशत फैला दी है। उसने सरैया चौकी क्षेत्र अंतर्गत गड़ा कझार के जंगल में चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम में फायरिंग कर अपने लौटने की खबर दी। गौरी अपने गैंग के साथ पहुंचा। मजदूरों के साथ मारपीट कर फायरिंग की। पुलिस ने बहिलपुरवा थाना (चित्रकूट) के बिलहरी गांव के जिस गौरी को ददुआ और ठोकिया के खिलाफ खड़ा किया था, वह अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कई बार अंडरग्राउंड रहने के बाद 1.5 लाख का ईनामी गौरी फिर लौट आया है। एक वक्त था जब उप्र की **धर्मनगरी चित्रकूट** में शिवकुमार पटेल उर्फ ददुआ और अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया का आतंक था। साल 2008 में ददुआ को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, फिर कुछ ही दिन में ठोकिया भी मारा गया।

साल 2009 में खूंखार शंकर केवट के शागिर्द धनश्याम केवट को पुलिस ने मौत के घाट उतारा था। धनश्याम केवट का एनकाउंटर 52 घंटे चला, जो देश का सबसे बड़ा शूटआउट था। चित्रकूट के जंगल (बीहड़) में राज करने वाले डाकुओं को मारने के बाद अब गौरी उर्फ उदयभान यादव मुश्किलें खड़ी कर रहा है। साल 2001 से गौरी डकैती सीख रहा था। गौरी ने साल 2005 में अपना अलग गैंग बनाकर वारदात को अंजाम देना शुरू किया। ददुआ व ठोकिया की मौत के बाद साल 2009 में बांदा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन, दो साल बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। गौरी ने अभी तक कई वारदातों को अंजाम दिया है। 16 मई 2013 में बलिपुरवा गांव में दिल्ली से एक मामले की जांच करने आए दारोगा भगवान शर्मा की हत्या कर दी। 2015 में गौरी यादव ने बिलहरी निवासी लवलेश यादव का अपहरण कर हत्या कर दी। 2016 में लुड़वारा निवासी पप्पू के साथ दो लड़कों की गोली मारकर हत्या की। मई 2016 में गोपालगंज में बिलहरी गांव के तीन ग्रामीणों को बिजली के खंभे में बांधकर गोली मार दी। 2017 में अपने ही ग्राम पंचायत के अपने विरोधी को कुलुवा जंगल में जिंदा जलाया। 2018 में सतना-चित्रकूट मार्ग पर ठेकेदारों के मुंशी और मजदूरों के साथ मारपीट व रंगदारी मांगना। 16 मई 2020 को मप्र के मझगवां थाना क्षेत्र में चौकी लाल कोरी पुत्र बेला कोरी से रंगदारी मांगी। मार्च 2021 में तेंदूपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों की पिटाई का ठेकेदार से रंगदारी मांगी।

गौरी की पुलिस से कई मुठभेड़ हो चुकी है। 30 अक्टूबर 2015 में गौरी डकैत प्रचार-प्रसार कर रहा था, तभी बहिलपुरवा के जंगल में पुलिस से डकैत गौरी की आमने-सामने मुठभेड़ हुई। इस बीच 20 मिनट तक गोलियां बरसाई गई और गौरी पुलिस को चकमा देकर जंगल में गायब हो गया। इसके बाद 9 मई 2019 को गौरी और सतना पुलिस की आमने-सामने मुठभेड़ हुई थी उस समय तत्कालीन एसपी रियाज इकबाल भी मौजूद थे। इस बार डेढ़ घंटे गोली चलीं। इस बार गौरी यादव गैंग का 65 हजार का ईनामी डकैत भोला यादव को पुलिस ने मार गिराया। यह मुठभेड़ चित्रकूट जनपद सीमा से सटे बटोही के जंगल में हुई थी। फिर 30 मार्च 2021 को बहिलपुरवा थाना के जंगल में पुलिस और गौरी की आमने सामने मुठभेड़ हुई, जिसमें करीब 1 घंटा दोनों ओर से गोलियां चलीं। इसके बाद गौरीगंज के 30 हजार के ईनामी भालचंद्र पुत्र राम अवतार यादव को पुलिस ने मार गिराया।

दरोगा सहित तीन गांव वालों को गोलियों से भूनने के बाद साल 2016 में उप्र के डीजीपी जावेद अहमद ने गौरी पर एक लाख रुपए का ईनाम घोषित किया था। तक उसके खिलाफ चित्रकूट जनपद से सटी सीमा सतना मप्र में भी कई मुकदमे दर्ज थे। मप्र से भी गौरी पर 50 हजार का ईनाम घोषित किया। इसी साल गौरी यादव अपनी मां को ग्राम पंचायत का प्रधान बनवाया और मप्र मझगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत पडवनिया में अपने बहनोई को बंदूक की नोक पर सरपंच बनवाया। गौरी यादव के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बवाल, हत्या का प्रयास सहित उप्र और मप्र में करीब 140 केस दर्ज हैं।

डकैत गौरी यादव कई साल से बागी है। 5 लाख के ईनामी डकैत बबुली कोल के मारे जाने के बाद से वह अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन पंचायत चुनाव के पहले फिर से उसने वारदात शुरू कर दी। बीते माह ददरी में मजदूरों को पीटकर पीडब्लूडी का सड़क निर्माण रुकवा दिया और चेकडैम बनवा रहे वन विभाग कर्मियों को भी पीटा था। वन कर्मियों ने बहिलपुरवा थाना में मुकदमा दर्ज कराया। इन घटनाओं के बाद से पुलिस लगातार गैंग पर कार्रवाई की गई है। कुछ मददगार व सदस्यों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन सरगना हाथ नहीं लगा।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

> ‘नदियां मरेंगी तो समाज मर जाएगा। यह जानते हुए भी नदियों पर कब्जे की होड़ मची हुई है। सरकारी एवं सामाजिक स्तर पर गंभीरता से प्रयास नहीं होने के कारण मप्र की कई नदियों का अस्तित्व आज खतरे में है।’

नदियों पर कब्जों की होड़

श्योपुर प्राकृतिक रूप से समृद्ध होना जिलेवासियों के लिए गर्व की बात है। कल-कल बहती नदियों के लिए श्योपुर जिले की पहचान अब गुजरे जमाने की बात हो चली है। स्वार्थ की खातिर नदियों को नाला बना डाला है। ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों में सबसे ज्यादा श्योपुर में 28 नदियां हैं। कभी 12 महीने बहने वाली छोटी-बड़ी नदियां अब सिर्फ बारिश के सीजन में यौवन पर आती हैं और सर्दी खत्म होने से पहले ही सूख रही हैं। लेकिन पिछले दो दशक से तेजी से बढ़ती आबादी के साथ ही नदियों की भूमि पर अवैध कब्जे की होड़, प्रतिबंध के बावजूद नदियों से सिंचाई के लिए अंधाधुंध जलदोहन, अवैध उत्खनन के कारण बढ़ते जल प्रदूषण से प्रमुख नदियों में गर्मी से पहले ही पानी की धार टूट रही है।

इनमें छोटी-बड़ी 10 नदियों अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन नदियों का अस्तित्व सिर्फ राजस्व नक्शों में ही रह गया है। हकीकत में यह नदियां कहीं नाला, कहीं गड्ढ़े में सिमटी हुई हैं तो कहीं सूखकर मैदान बन गई हैं। चंबल और पार्वती नदी प्रदूषण की शिकार हैं। जबकि सीप, कूनो, क्वारी नदियां गिरते सीवरयुक्त गंदे नालों के कारण दुर्दशा की शिकार हैं। नदियों के संरक्षण की प्रशासनिक योजनाएं 12 साल में भी धरातल पर नहीं उतर पाईं। बजट के अभाव में नदियों के संरक्षण के लिए प्रशासन जनसहयोग के भरोसे हैं।

अहेली, कदवाल, अमराल, सरारी, पारम, दौनी, भादड़ी, ककरेंडी, दुआर, अहेली सहित जंगल से निकली कई सहायक बरसाती नदियां धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं। मानसून की विदाई के बाद सर्दी में ही सूखकर नाला बन जाती है। पिछले दो दशक से दोनों किनारों पर खेती के लिए अवैध कब्जों का दायरा हर साल बेलगाम बढ़ने के कारण नदियों का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। बरसाती नदी कंकरेडी का दम अतिक्रमण ने घोंट दिया। जिला मुख्यालय से 10 किमी दूर सोईंकलां किनारे पर खेती के लिए कब्जे होने के साथ ही बहाव क्षेत्र में एक ढाबा बनने से श्योपुर-सवाई माधोपुर हाईवे पर सोईंकलां की पुलिया के पास कंकरेडी नदी का सफर खत्म हो चुका है। बारिश का पानी रोकने के लिए जिस जगह स्टापडैम बनाया था, वहां न सिर्फ नदी के दायरे में खेत तैयार कर लिए, बल्कि पक्के भवन भी खड़े कर दिए। इसमें बना ढाबा पिछले दो साल से चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी किनारे खाली जमीन को बच्चों के खेल मैदान के लिए आवंटित करने की मांग प्रशासन से की थी, लेकिन अफसरों ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। नतीजा खेल मैदान व नदी की तलहटी तक जगह अतिक्रमणकारियों ने घेर ली। इसकी शिकायत लोगों ने कलेक्टर से की थी।

जिले की प्रमुख नदियां सीप, कूनो व क्वारी अतिक्रमण की चपेट में आने के साथ जल प्रदूषण से मैली हो गई है। शहर सहित सवा सौ गांव की जीवनरेखा सीप नदी अपने उद्‍गम स्थल कराहल के जंगल में पनवाड़ा से करीब 75 किमी लंबे दायरे में बहते हुए रामेश्वर धाम पर चंबल और बनास नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम का पवित्र संयोग बनाती है। सीप नदी की सबसे ज्यादा दुर्दशा श्योपुर शहर में सभी 18 गंदे नाले गिरने के कारण हैं। उधर गुना जिले से होकर कूनो अभयारण्य में प्रवेश करने वाली कूनो नदी का प्राकृतिक सौंदर्य अब सिर्फ बारिश के मौसम में ही पर्यटकों को लुभाता है। गर्मी से पहले ही यह नदी हर साल सूख जाती है। यही हाल विजयपुर सहित वनांचल के 55 गांव की निस्तारी जरूरतों की पूर्ति करने वाली क्वारी नदी का है।

● **नवीन रघुवंशी**

नदियों का बदल गया रंग

मप्र की तीन बड़ी नदियां। शिप्रा जो उज्जैन में मोक्षदायिनी बनी। चंबल लंबा सफर तय कर राजस्थान को सींचती है और मंदसौर की शिवना। प्रदूषण से अब ये नदियां रंग बदलने लगी हैं। शिप्रा में लगातार इंदौर से बहकर आ रही कान्ह का केमिकलयुक्त पानी मिल जाता है। सिंहस्थ से लेकर अन्य विशेष मौकों पर स्नान के लिए इसमें नर्मदा का पानी मिलाना पड़ रहा है। लगातार गटर और केमिकल वाला पानी मिलने, सफाई नहीं होने के कारण अब इसका पानी हरा होने लगा है। ऐसे ही नागदा में बसे केमिकल वाले उद्योगों के कारण बार-बार चंबल की स्थिति बिगड़ती है। कुछ उद्योग और केमिकल सप्लायर टैंकर इसमें अपना एसिड डाल देते हैं। नतीजा यह हुआ कि चंबल का पानी कुछ जगह काला हो गया है। कई जगह चंबल के पत्थर सफेद होने लगे हैं। तीसरी नदी है मंदसौर की शिवना। पशुपतिनाथ मंदिर के पास से गुजरती इस नदी का पानी अकसर लाल हो जाता है।

कागजों पर रोपे गए 2,500 करोड़ के पौधे

भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में गत दिनों जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मप्र की शिवराज सरकार के विकास और पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के भ्रष्टाचार का उल्लेख कर रहे थे, उसी दौरान प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर पार्टी के युवा नेता भारतीय वन सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हवाला देकर पिछले 5 साल के दौरान पौधारोपण में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे थे। जिसमें यह बताया गया कि मप्र में किस तरह अफसरों ने कागजों पर पौधारोपण कर 2500 करोड़ रुपए की चपत लगाई है।

दरअसल, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जब ऑक्सीजन की आवश्यकता बड़ी तो लोगों को पेड़ों का महत्व समझ में आया। सरकार ने दावा किया प्रदेश में पौधारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज पौधारोपण कर रहे हैं। लेकिन पर्यावरण बचाने और जंगल को सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे सरकारी पौधारोपण की पोल एफएसआई की नई रिपोर्ट में खुल गई है। विभाग ने पांच साल में 2,500 करोड़ खर्चा कर करीब 38.26 करोड़ पौधे प्रदेश के वन क्षेत्र में लगाने का दावा किया है लेकिन एफएसआई की नई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 100 वर्ग किलोमीटर जंगल कम हो गया है।

भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आंकलन के बाद यह तथ्य सामने आया है कि पौधे लगाने से हरियाली बढ़ जाए, यह जरूरी नहीं। साल 2015 से 2020 तक 6 राज्यों ने 7,620 करोड़ रुपए खर्च कर 137 करोड़ पौधे लगाए, लेकिन हरियाली यानी ग्रीन कवर सिर्फ चार राज्यों में ही बढ़ा। ये राज्य हैं- महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। जबकि राजस्थान और मप्र में हरियाली का स्तर घटा है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इन सभी राज्यों में वन क्षेत्र बढ़ा है। देश में वृक्षों की संख्या 3,518 करोड़ थी। यानी प्रति वर्ग किमी में 11,109 पेड़ हैं। इस तरह प्रति व्यक्ति के हिसाब से देश में मात्र 28 पेड़ ही हैं। अच्छी बात यह है कि इन 6 राज्यों ने पौधों के पेड़ बनने के उपाय लागू कर दिए हैं, जिससे आने वाले समय में यहां वन क्षेत्र बढ़ सकता है।

छत्तीसगढ़ ने पिछले 5 साल में 9.66 करोड़ पौधे लगाए। यहां 63.57 वर्ग किमी फॉरेस्ट कवर बढ़ा है जबकि राजस्थान में 2255.21 वर्ग किमी में 1.5 करोड़ पौधे लगाने के बावजूद वनों के बाहर ग्रीन कवर 152 वर्ग किमी घटा है। मप्र में 1 जनवरी 2015 से 5 फरवरी 2019 तक की अवधि में 12 हजार 785 हैक्टेयर वन भूमि को दूसरे कामों के उपयोग के लिए दे दी गई। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 के मुकाबले 2019 में मप्र का वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर 1,469 वर्ग किमी बढ़ गया। इस समय मप्र के कुल क्षेत्रफल का 25 फीसदी फॉरेस्ट कवर है। महाराष्ट्र में ग्रीन कवर 95.56 वर्ग किमी बढ़ा है।

राज्यों में 5 साल में रोपे गए पौधे

	राज्य	पौधे लगे	कुल खर्च किए	हरियाली बढ़ी/घटी
●	छत्तीसगढ़	9.67 करोड	701 करोड़	63.57 वर्ग किमी
●	झारखंड	14.5 करोड़	135 करोड़	11. 21 वर्ग किमी
●	महाराष्ट्र	61.85 करोड़	3,450 करोड़	95.56 वर्ग किमी
●	बिहार	11.34 करोड	819.11 लाख	120 वर्ग किमी
●	मप्र	38.26 करोड़	2,500 करोड़	100 वर्ग किमी
●	राजस्थान	1.46 करोड़	15.30 लाख	7.152 वर्ग किमी

मप्र में सरकार के वन विभाग और भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों में भारी अंतर आ रहा है जिससे साफ होता है कि सरकार पर्यावरण बचाने के लिए कितना गंभीर है। वन विभाग के मुताबिक मप्र में 2014-15 से 2019-20 तक करीब 38 करोड़ 26 लाख पौधे लगाए गए। इस पर कुल 2500 करोड़ की राशि खर्चा हुई लेकिन एफएसआई की ताजा रिपोर्ट कहती है कि इन 6 सालों में प्रदेश में 100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वन क्षेत्र कम हुआ है। इतना ही नहीं 1 जनवरी 2015 से 5 फरवरी 2019 तक 12 हजार 785 हैक्टेयर वन भूमि दूसरे कामों के लिए दे दी गई। एक बात राहत की है कि रिपोर्ट में 2005 के मुकाबले 2019 में प्रदेश में 1469 वर्ग किमी ग्रीन कवर बढ़ने की बात भी कही गई हैं।

प्रदेश में फिलहाल कुल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत इलाका फॉरेस्ट कवर है। यदि वन भूमि के कम होने पर नजर डाले तो सबसे अधिक हरदा में 51 फीसदी क्षेत्र घटा है। जबकि पन्ना में सबसे अधिक 57 फीसदी वनक्षेत्र बढ़ा भी है। वहीं भोपाल में 25 फीसदी कमी आई हैं। जबकि वन प्रशासन वन भूमि के घटने की पट्टे देना एक बड़ी बजह बताता है। कुल मिलाकर प्रदेश में 100 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कम हुआ है। जबकि इस साल 2021-22 के वर्षाकाल में वन्य क्षेत्र में 4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन कोरोना संकट के चलते यह काम अधर में है। महाराष्ट्र में प्लांटेशन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (पीएमआईएस) लागू किया गया है। इसके तहत पौधा लगाने से लेकर उसके पेड़ के रूप में खड़े होने तक हर स्टेप की डिजिटल जानकारी रखी जाती है। इस सिस्टम को कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया-2020 अवॉर्ड तथा डिजिटल फॉरेस्ट गर्वनेंस के लिए अर्थकेअर अवॉर्ड मिला है। केंद्र सरकार के एग्रो फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट ने भी इसकी सराहना की है। हरियाणा और झारखंड ने भी इस योजना को अपने राज्य में लागू करने को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। मप्र में बिगड़े वनों को सुधारने के लिए 9,483 ग्राम वन समितियां बनी हुई हैं। राज्य सरकार पौधरोपण के बाद उन्हें बचाने में इनकी मदद लेती है, साथ ही पौधे भी लगवाती है। इसकी एवज में उन्हें पूरा वनोपज मिलता है। पिछले वित्तीय वर्ष में ही 7.31 करोड़ रुपए के बांस, बल्ली और जलाऊ लकड़ियां उन्हें दी गईं। इस सिस्टम के चलते ही राज्य में वनक्षेत्र का दायरा बढ़ा है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

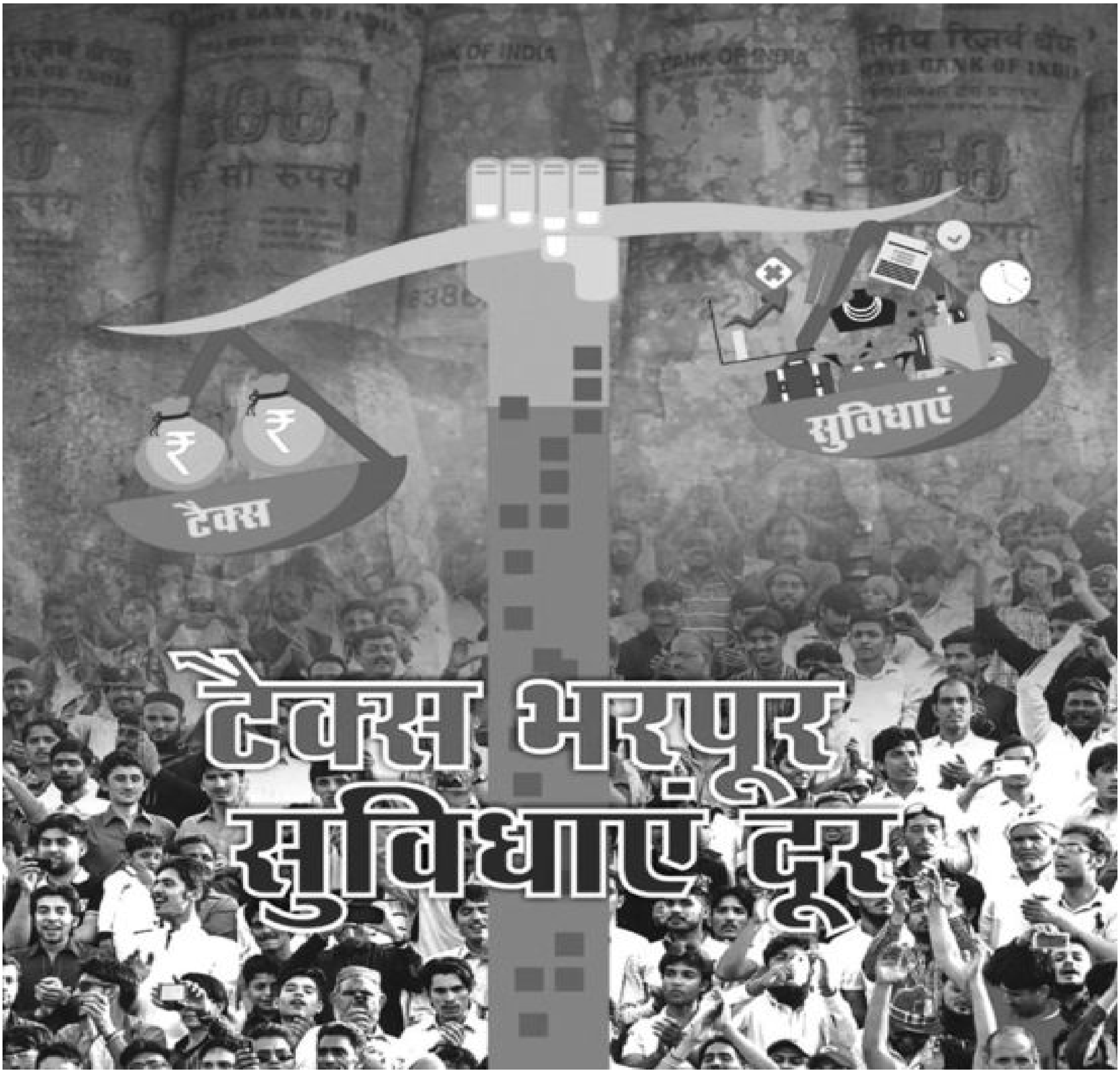

टैक्स भरपूर सुविधाएं दूर

25 जून को अपनी जन्मभूमि कानपुर देहात में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जबसे कहा है कि देश के विकास के लिए टैक्स जरूरी है और मैं भी पौने तीन लाख रुपया टैक्स देता हूं। तबसे देश में यह बहस चल पड़ी है कि देश में कितने लोग टैक्स देते हैं और क्या उस टैक्स के बदले उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। अगर देखा जाए तो देश में हर व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर टैक्स दे रहा है। इसके बावजूद स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों का अभाव है।

● राजेंद्र आगाल

भारत में टैक्स व्यवस्था की जड़ें काफी पुरानी हैं। टैक्स अथवा कर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ 'मनुस्मृति' और चाणक्यरचित 'अर्थशास्त्र' में भी मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख है कि कर प्रणाली का अंतिम उद्देश्य अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण होना चाहिए। लोक-कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य भी यही है। वर्तमान समय में हर व्यक्ति टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है। लेकिन बुनियादी सुविधाएं भी लोगों से आज दूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनता टैक्स ज्यादा देती है और बदले में सरकारें सुविधाएं कम देती हैं? सरकारें कहती हैं कि सड़क चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए तो टैक्स भरकर राष्ट्रनिर्माण करो। लेकिन सैलरी और सैलरी पर कटने वाले टैक्स की चिंता तो महामहिम यानी देश के राष्ट्रपति तक कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी की क्या स्थिति होगी इसका आंकलन सहज लगाया जा सकता है।

> *कहने को सब जानते हैं, कहने में कोई बुराई नहीं है। राष्ट्रपति देश का सबसे ज्यादा सलैरी लेने वाला कर्मचारी है, और वो टैक्स भी देता है। हम टैक्स भी देते हैं पौने तीन लाख रुपए महीना। लेकिन कोई कहेगा कि आपको तो पांच लाख रुपए मिलता है, उसी की सब चर्चा करते हैं। उसमें से हर महीने पौने तीन लाख निकल जाता है। तो बचा कितना? और जो बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और दूसरों को मिलता है। जो टीचर्स बैठे हुए हैं, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। इस बात का उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि जो टैक्स देते हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है।* **- रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति**

चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहते हों, पर आपको स्थानीय सरकार को टैक्स का भुगतान करना होता है। भारत में सरकार को टैक्स से औसतन 24 लाख 23 हजार करोड़ रुपए की कमाई होती है। सरकार इस रकम को विकास योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं आदि पर खर्च करती है। लेकिन उसके बाद भी लोगों को मूलभत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसकी असली वजह यह है कि देश में प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स भरने वालों की संख्या काफी कम है। इस कारण भारत में उतना टैक्स संग्रह नहीं हो पाता है जितने की जरूरत है। दरअसल, भारत की कराधान प्रणाली में कई समस्याएं हैं। सबसे पहले तो देश में टैक्स देते ही बहुत कम लोग हैं। 130 करोड़ की आबादी में लगभग 1.5 करोड़ लोग अपनी आय पर कर देते हैं, यानी मुश्किल से आबादी का एक प्रतिशत। करदाताओं के लिए कराधान प्रणाली भी लंबे समय से काफी जटिल रही है। आयकर रिटर्न भरने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सहारा लेना देश में आम है। उसके ऊपर से कर भरने के और कर से छूट प्राप्त करने के प्रावधान इतने सारे हैं कि आम लोगों का दिमाग चक्कर खा जाता है। सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध आयकर विभाग को भी आम लोगों की कल्पना में डर पैदा करने वाले एक विभाग के रूप में देखा जाता है। आयकर विभाग सिर्फ छापे ही मारता है और अगर आप उसकी नजर में आ गए तो वो निश्चित ही आपका धन हथिया लेगा, लोग ऐसा मान कर चलते हैं।

सुविधाओं से भरपूर महामहिम को टैक्स की चिंता

देश में टैक्स के बोझ तले दबी जनता की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महामहिम रामनाथ कोविंद को अपने वेतन से टैक्स कटने की चिंता है। सबसे ज्यादा वेतन देश के राष्ट्रपति को मिलता है। कानपुर पहुंचे राष्ट्रपति ने कहा था कि हमें 5 लाख मिलता है तो पौने 3 लाख टैक्स कट जाता है, हमसे ज्यादा बचत तो टीचर की होती है। तो बताइए बचा कितना? और जितना बचा उससे कहीं ज्यादा तो हमारे अधिकारी और अन्य दूसरे लोगों को मिलता है। यहां जो टीचर्स बैठे हुए हैं उन्हें तो सबसे ज्यादा मिलता है। महामहिम के टैक्स की चिंता पर लोग भ्रमित हैं। क्योंकि महामहिम को वेतन के अलावा अन्य भत्ते भी मिलते हैं जिनमें मुफ्त चिकित्सा, आवास और उपचार सुविधा (जीवनभर) शामिल हैं। इसके अलावा भारत सरकार हर साल उनके अन्य खर्चों जैसे आवास, स्टाफ, खाने-पीने और अतिथियों की मेजाबनी पर करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च करती है। राष्ट्रपति के जीवनसाथी को भी हर महीने 30,000 रुपए सेक्रेटेरियल असिस्टेंस के तौर पर मिलता है। उनको हर महीने 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलता है। एक फर्निश्ड रेंट फ्री बंगला, दो फ्री लैंडलाइन और एक मोबाइल फोन, स्टाफ खर्च के लिए हर साल 60,000 रुपए, रेल या विमान से यात्रा फ्री। एक आदमी को साथ भी ले जा सकते हैं। अब इतनी सुविधाएं और टैक्स फ्री महामहिम को यह सब बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। महामहिम ने ऐसा क्यों बोला ये तो वही जानें, लेकिन ये बहस छिड़ गई है कि देश में एक आम आदमी की क्या स्थिति होगी।

हर गली-मोहल्ले में करोड़पति

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार देश में 1.46 करोड़ लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सम्मेलन में कहा था कि 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में डेढ़ करोड़ लोग टैक्स देते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने कहा कि भारत में केवल 1.46 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। इन 1.46 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोगों ने जानकारी दी है कि उनकी सालाना इनकम 5 से 10 लाख रुपए के बीच है। वहीं, केवल 46 लाख लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि उनकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए से अधिक है।

वित्त वर्ष में 5.78 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके वित्त वर्ष 2018-19 में अपनी इनकम के बारे जानकारी दी है। इनमें से 1.03 करोड़ लोगों ने बताया है कि उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, जबकि 3.29 करोड़ लोगों ने अपनी सालाना इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच होने की जानकारी दी है। कुल 5.78 करोड़ लोगों में से केवल 4.32 करोड़ लोगों ने अपनी सालाना इनकम 5 लाख रुपए या इससे कम होने की जानकारी दी है। चूंकि, पिछले साल के बजट में सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई वाले लोगों को टैक्स में छूट दी गई थी, ऐसे में 4.32 करोड़ लोगों पर वित्त वर्ष 2020 के लिए कोई टैक्स देयता नहीं बनती है। केवल, 3.16 लाख लोगों ने ही कहा है कि उनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए से अधिक है। सीबीडीटी द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2020 के लिए सालाना 5 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाले लोगों की कुल संख्या 8,600 है। सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने वाले डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील समेत अन्य प्रोफेनल्स लोगों की संख्या 2,200 है। इनमें उनके रेंट, ब्याज और कैपिटल गेन्स समेत होने वाली अन्य कमाई शामिल नहीं है। यानी देश में गली-मोहल्ले में करोड़पति हैं, लेकिन टैक्स देने वालों की संख्या उसके अनुपात में कम है। ऐसे में देश में आवश्यक सुविधाओं के लिए अप्रत्यक्ष कर का सहारा लिया जा रहा है, जिससे देश में महंगाई बढ़ रही

मप्र में मुख्यमंत्री व मंत्रियों का टैक्स जमा करती है सरकार

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने वेतन से आयकर चुकाते हैं। उन्हें लगभग 5 लाख रुपए वेतन मिलता है और इसमें से वे पौने तीन लाख रुपए के कर का भुगतान करते हैं। वहीं, मप्र में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष से लेकर राज्यमंत्री तक का आयकर सरकार चुकाती है। इसके लिए कानूनी प्रावधान है और बजट का इंतजाम भी किया गया है। इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग भी उठती रही है पर कभी आमराय नहीं बनी। यही वजह है कि यह व्यवस्था अब तक चली आ रही है। मप्र में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष और राज्यमंत्री का आयकर चुकाने के लिए वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 लागू है। इसमें प्रावधान है कि मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव को मिलने वाले वेतन-भत्ते पर आयकर सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए बजट में प्रतिवर्ष प्रावधान किया जाता है। कमलनाथ सरकार के समय शिवराज सरकार के मंत्रियों का आयकर जमा करने का प्रस्ताव आया था, जिस पर मंत्रालय के मुख्य लेखाधिकारी को राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे। तब इस व्यवस्था को बंद करने की मांग भी उठी थी पर बात आगे नहीं बढ़ी। सामान्य प्रशासन विभाग की लेखा शाखा के अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक तीन माह में प्रस्ताव आता है और कटौती की राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। वहीं, विधानसभा के अपर सचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपाध्यक्ष को मिलने वाले वेतन-भत्ते पर जो आयकर बनता है, उसका भुगतान शासन करता है। विधानसभा के लिए आवंटित बजट में से यह राशि उपलब्ध करा दी जाती है। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष और राज्यमंत्री का आयकर जमा करने के लिए बजट में एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कर योग्य आय का आंकलन करने के बाद संबंधित व्यक्ति के वेतन से आयकर की कटौती हो जाती है। यह राशि विभाग द्वारा उन्हें लौटाई जाती है। देश में कराधान की ऐसी ही व्यवस्था का असर यह हो रहा है कि लोगों में टैक्स देने की प्रवृति बन नहीं पा रही है। जिससे महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है।

टैक्स से आया पैसा कैसे खर्च करती है सरकार?

सैलरी आने के बाद आप जिस तरह अपने खर्च प्लान करते हैं। उसी तरह सरकार भी पैसा खर्च करती है। लेकिन फर्क दोनों में बस इतना होता है कि सरकार का खर्च करने का तरीका तमाम नियम और कायदे-कानून के तहत होता है। इस बार के बजट में सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा था। पहले बात कमाई की करते हैं। सरकार की कमाई दो तरीकों से होती है- टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स लगाकर सरकार जो राशि वसूल करती है उसे टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। यह रेवेन्यू टैक्स पेयर्स, कॉर्पोरेशन और तरह-तरह की सर्विस के जरिए आता है। टैक्स से होने वाली कमाई के अलावा सरकार रिसीप्ट के जरिए भी राजस्व वसूल करती है। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के डिविडेंड के रूप में होती है। इन स्त्रोतों के अलावा सरकार पब्लिक सेक्टर के विनिवेश के जरिए भी राजस्व हासिल करती है। अब खर्चे की बात की जाए तो सरकार अपना खर्चा दो हिस्सों में बांटती है- प्लान्ड एक्सपेंडिचर (योजनागत व्यय) और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर (गैरयोजनागत व्यय)। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट विभिन्न मंत्रालयों और योजना आयोग द्वारा मिलकर बनाया जाता है। वहीं, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो इनमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ब्याज की अदायगी, सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, राज्य सरकारों को अनुदान, विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान पर खर्च होता है। तो वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर रक्षा, पब्लिक इंटरप्राइजेज, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले कर्ज पर खर्च होता है।

है और उसका भार आज जनता पर सर्वाधिक पड़ रहा है।

टैक्सपेयर्स की संख्या में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार की कोशिश रही है कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए। इसके लिए आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया को लगातार आसान बनाया जा रहा है। इस बार भी लोगों से कहा जा रहा है कि आप भी घर बैठे आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग लगातार आगाह कर रहा है कि आईटीआर फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें। दरअसल, भारत में नौकरी, कारोबार या पेशे से आमदनी वाले हर व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स चुकाना जरूरी है। इसके लिए शर्त यह है कि आपकी आमदनी टैक्स छूट की आम सीमा 2.5 लाख रुपए से अधिक हो। 20 साल से अधिक उम्र के आयकर दाताओं की तुलना करें तो केवल 1.6 फीसदी लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। आयकर विभाग के पिछले 5 साल के आंकड़ों के मुताबिक टैक्स देने वालों में 57 प्रतिशज की आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है। वहीं, टैक्स देने वाले लोगों में केवल एक फीसदी की सालाना कमाई 50 लाख रुपए से अधिक है। यानी 130 करोड़ की आबादी में करीब डेढ़ लाख लोगों की आमदनी सालाना 50 लाख रुपए से अधिक है। वहीं टैक्स देने वालों में 18 फीसदी लोगों की कमाई 2.5 से 5 लाख के बीच है। 5 से 10 लाख सालाना कमाई करने वाले लोगों की संख्या 17 फीसदी है। वहीं 10 से 50 लाख की सालाना कमाई वाले महज 7 फीसदी लोग हैं। वर्ष 2015-16 में देश में पैन कार्ड होल्डर्स की संख्या 30 करोड़ थी, जो अगस्त-2020 में बढ़कर करीब 51 करोड़ हो गई। देश में साल दर साल टैक्स भरने वालों की

संख्या में इजाफा हो रहा है। लेकिन सरकारी खजाना फिर भी खाली रहता है।

टैक्स भरो...सुविधा नहीं मिलेगी

देश में सरकार की भी प्रवृति रही है कि टैक्स भरो और सुविधा की चिंता मत करो। इस कारण लोग टैक्स भरने से बचने के लिए रास्ते निकालते रहते हैं। अर्थव्यवस्था का सामान्य सिद्धांत कहता है कि जब लोगों के हाथ में पैसा अधिक और उत्पादन कम होता है तब महंगाई बढ़ती है। आसान भाषा में समझा जाए तो यह कि जब एक अनार के सौ बीमार हों यानी एक सामान को खरीदने के लिए 100 लोगों के हाथ में ठीक-ठाक पैसा होता है तो दुकानदार कीमत बढ़ा देता है। यह अर्थव्यवस्था का सामान्य सिद्धांत है। इससे एक हद तक फायदा भी होता है तो अर्थव्यवस्था के जानकार यह भी कहते हैं कि थोड़ी बहुत महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। इससे उत्पादन करने वाले कारोबारियों को अधिक कीमत मिलने की वजह से प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए आरबीआई ने सारा गुणा भाग लगाकर यह तय किया है कि भारत में महंगाई की दर 6 फीसदी से अधिक नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो हुआ है वह अर्थव्यवस्था के सामान्य सिद्धांत से बिल्कुल उलट है। इतना उलट कि अर्थव्यवस्था का सारा गणित फेल हो गया है।

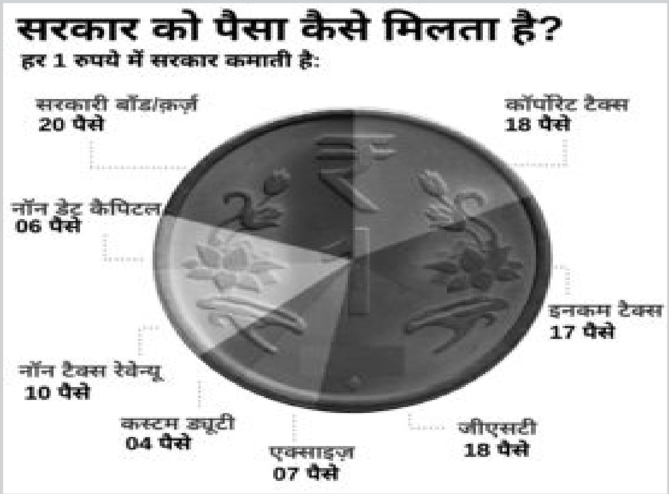

महंगाई तब भी छप्पर फाड़ कर बढ़ रही है जब माइनस 7.3 फीसदी की दर से पिछले 40 सालों में पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था उल्टे पांव चल रही है। आर्थिक गतिविधियों में तकरीबन 10 फीसदी के आसपास का निवेश घटा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक निवेश को लेकर इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई। मई 2021 में भारत में बेरोजगारी की दर 11.9 फीसदी के आसपास हो गई। इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज भारत में आजादी के बाद से लेकर अब तक कभी नहीं देखी। आंकड़ों में देखा जाए तो तकरीबन 5 से 8 करोड़ लोग मौजूदा समय में बिना काम के जिंदगी जी रहे हैं। यानी लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। लोग पहले से अधिक गरीब हो रहे हैं। उत्पादन के सभी साधन रुके हुए हैं। पहले से मौजूद माल को खरीदने वाले बाजार में खरीददार नहीं हैं। लेकिन खाने-पीने की सारी चीजें महंगी हो गई हैं। दाल, अंडा, फल, तेल, मसाला, आलू, प्याज, टमाटर, दूध सब महंगा हो चुका है। यानी आम आदमी की खाने-पीने की सारी चीजें तकरीबन महंगी हो गई हैं।

तकनीकी भाषा में कहें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रिटेल महंगाई 6 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर मई में 6.3 प्रतिशत रही। यह अप्रैल में 4.23 प्रतिशत पर थी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मुताबिक थोक महंगाई दर मई में 12.94 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह मई 2020 में -3.37 प्रतिशत रही थी। अब आप पूछेंगे आखिरकार यह अजूबा कैसे घट रहा है? ऐसी स्थिति में महंगाई कैसे बढ़ रही है? इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। लेकिन एक कारण जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता जिस पर अर्थव्यवस्था के सभी जानकारों से लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम तक सबकी सहमति है, उस कारण का नाम है, पेट्रोल-डीजल यानी ईंधन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होना। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों की बहस का हिस्सा महज पेट्रोल और डीजल की महंगाई ही होती है। लोग अर्थव्यवस्था की चक्रीय गति को नहीं भांप पाते हैं। नहीं समझ पाते हैं कि जब वह अपनी मोटरसाइकिल के लिए 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का भुगतान कर रहे होते हैं तो इसका असर उन सभी सामानों और सेवाओं पर पड़ता

हर दूसरा कमाने वाला कर्जदार

देश की कुल 40 करोड़ कामकाजी आबादी में से आधी आबादी कर्जदार है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश की कुल 40 करोड़ कामकाजी आबादी के करीब आधे लोग कर्जदार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 तक भारत की कुल कामकाजी आबादी 40.07 करोड़ थी, जबकि रिटेल लोन बाजार में 20 करोड़ लोगों ने किसी न किसी रूप में कर्ज लिया है। रिपोर्ट की मानें तो इन 20 करोड़ लोगों ने कम से कम एक लोन लिया हुआ है या उनके पास क्रेडिट कार्ड है। दरअसल पिछले एक दशक में बैंकों ने खुदरा लोन को प्राथमिकता दी, जिससे लोन लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। लेकिन कोरोना महामारी के बाद खुदरा लोन में बढ़ोतरी को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। सीआईसी के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 18-33 वर्ष की आयु के 40 करोड़ लोगों के बीच कर्ज बाजार की बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं, इस सेक्शन में लोन का प्रसार सिर्फ आठ फीसदी है। हालांकि कर्जदारों की लिस्ट में महिलाएं कम हैं।

है, जिन सामानों और सेवाओं से पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में महंगाई दर 12 फीसदी से भी अधिक बढ़ी है। इसका मिलाजुला असर यह पड़ा है कि विनिर्माण क्षेत्र में महंगाई दर 11 फीसदी के आसपास बढ़ी है। बस के किराया से लेकर दूध, फल-सब्जी सब पर इसका असर पड़ा है। परिवहन का खर्च बढ़ने की वजह से हर तरह के उद्योग धंधे के उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हुई है। यानी यह समय डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नहीं है। जिसके बारे में अर्थव्यवस्था के जानकारों का कहना होता है कि इससे अर्थव्यवस्था फायदेमंद होती है। बल्कि यह समय कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का है। जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक खराब होता है। बीते एक साल में महंगाई के कारण आय और खर्च की क्षमता घटने से देश की 97 फीसदी आबादी 'गरीब' हो गई है। गरीबी का मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाना नहीं होता है बल्कि गरीबी रिलेटिव टर्म यानी तुलनात्मक तौर पर मापी जाती है। कहने का मतलब यह है कि भारत में तकरीबन 97 फीसदी लोगों की आय पहले से कम हुई है। जो आय के जिस स्तर पर है, उसकी गरीबी उतनी ही मारक है।

कॉरपोरेट पर मेहरबानी

कम टैक्स वसूली के पीछे सबसे बड़ा कारण भारत की जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था को मिला कोरोना का साथ तो है ही। लेकिन दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि धीरे-धीरे सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की वसूली बहुत कम कर दी है, और वह भी तब जब कॉरपोरेट्स महामारी के दौर में भयंकर कमाई कर रहे हैं। साल 2020 में 100 बिलेनियर की संपत्ति में हुए इजाफे को अगर सबसे गरीब 10 फीसदी लोगों में बांट दिया जाए तो हर एक व्यक्ति को तकरीबन 1 लाख मिल सकता है। इस तरह की प्रवृत्ति वाले समाज में जहां पर अमीर कॉरपोरेट्स अमीर हुए जा रहे हैं, वहां पर कॉरपोरेट को खुली छूट दी गई है। साल 2018 में कॉरपोरेट को रियायत के तौर पर तकरीबन 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए की छूट दी गई। एक अध्ययन के मुताबिक साल 2010 में केंद्र सरकार के प्रति 100 रुपए के राजस्व में कंपनियों से 40 रुपए और आम लोगों से 60 रुपए आते थे। 2020 में कंपनियां केवल 25 रुपए दे रही हैं और आम लोग दे रहे हैं 75 रुपए।

कहने का मतलब यह है कि भारतीय राज्य की कमाई का बड़ा सोर्स आम लोग हैं न कि कॉरपोरेट। एक समय के लिए अगर भारतीय राज्य को एक कंपनी मान लिया जाए तो कंपनी में आम लोगों का पैसा ज्यादा लग रहा है, धनिक लोगों का पैसा कम, लेकिन मुनाफा धनिक लोगों का ज्यादा हो रहा है। हद से ज्यादा टैक्स लगाने की वजह से सबसे बड़ा परिणाम तो यह मिला है कि महंगाई छप्पर फाड़कर बढ़ रही है। कंज्यूमर प्राइस और होलसेल प्राइस इंडेक्स के जारी आंकड़े इसी के बारे में बताते हैं। लेकिन यह भी महज आंकड़े हैं।

महंगाई का सही अंदाजा इनसे नहीं लगता। क्योंकि यह सालभर में होने वाले इजाफे को ही बता पाते हैं। सारे विश्लेषक महंगाई के लिए पेट्रोल की कीमतों में टैक्स को लेकर हो रहे इजाफे को दोषी बताते हैं। बीते 7 साल में पेट्रोल-डीजल से टैक्स संग्रह 700 फीसदी बढ़ा है। इसका मतलब है कि पिछले 7 साल के पहले की कीमत से तुलना करें तो आज महंगाई बहुत अधिक होगी। महंगाई की भी सबसे अधिक मार गरीब लोगों को झेलने पड़ती है। उनको जो देश की 80 फीसदी आबादी का हिस्सा है और जिनकी कमाई 20 हजार महीने से कम है।

ऐसे में सबसे अधिक टैक्स भी यही वर्ग भुगतान कर रहा है। इसलिए चौराहे पर खड़ा होकर कोई यह सवाल पूछे कि आखिरकार सरकार हमारे टैक्स का पैसा कहां खर्च कर रही है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। असली राष्ट्रवाद तो यही है। अगर सरकार का कहना है कि वह इलाज पर खर्च कर रही है तो भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं की व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? लोक कल्याण की नीतियां धरातल पर क्यों नहीं उतरती? आम लोग और सरकार के बीच जनकल्याण को लेकर फासला बढ़ता क्यों जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब हमारे आसपास मौजूद है कि सब कुछ लचर है। न रोजगार मिल रहा है, न कमाई हो रही है, न जीने लायक जीवन स्तर बन रहा है और फिर भी सरकार टैक्स पर टैक्स लगा रही है। आम लोग टैक्स का भुगतान कर रहे हैं और सरकार उलट कर कह रही है कि वह आम लोगों पर पैसा खर्च कर रही है तो इसे कैसे सही माना जाए?

क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स

डायरेक्ट मतलब सीधे। यूं जिस टैक्स में टैक्स देने वाले और टैक्स लेने वाले के बीच में कोई न हो, वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। इस डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। इनकम टैक्स यानी हमारी कमाई पर लगने वाला टैक्स। हम सालभर में जितने पैसे कमाते हैं, सरकार उस पर सीधे टैक्स लेती है। यही इनकम टैक्स है, जो सीधे सरकार के खाते में जाता है। कंपनियां जो पैसे कमाती हैं, उसका एक हिस्सा सरकार को देती हैं। ये होता है कॉरपोरेट टैक्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये टैक्स करदाता (टैक्स देने वाला) द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है। भारत में इस प्रकार के टैक्स के सबसे अच्छे उदाहरण इनकम टैक्स और वैल्थ टैक्स हैं। सरकार की नजर में, डायरेक्ट टैक्स से कुल टैक्स इनकम का अनुमान लगाना आसान होता है क्योंकि यह करदाताओं की इनकम से सीधा संबंध रखता है। वहीं जिस टैक्स में टैक्स देने वाले और टैक्स लेने वाले के बीच में कई अन्य लोग हों वो टैक्स कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक उदाहरण देखिए- अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान के मूल्य के साथ उठा टैक्स भी चुकाते हैं। लेकिन पहले वो दुकानदार को जाता है, फिर वो सप्लायर को जाता है, फिर वो उस कंपनी को जाता है, जिसने सामान बनाया है। फिर जाकर कंपनी सरकार को टैक्स देती है। यूं समझ में आता है कि सामान और सर्विस पर लगने वाला टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्यूं है। वहीं आपको जो सैलरी मिलती है, उस पर जो आप इनकम टैक्स देते हैं वो सीधे सरकार को देते हैं। मने 'डायरेक्ट' सरकार को देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को अलग तरीके से जमा किया जाता है और ये टैक्स सामान और सेवाओं के उपयोग पर आधारित होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स का भुगतान सामान-सेवाओं के उपभोक्ता सीधे सरकार को नहीं करते हैं। सरकार सामान-सेवा के विक्रेता (बेचने वाले) से इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त करती है। विक्रेता बदले में सामान-सेवा के खरीदार से टैक्स लेता है। इन-डायरेक्ट टैक्स के सामान्य उदाहरणों में सेल्स टैक्स, जीएसटी, वैट, आदि शामिल हैं।

ब्रांड मोदी चमकाने की कवायद

जम्मू-कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक की पहल देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है, जाहिर है होने वाले असर की संभावना को भी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म किया जाना भाजपा का चुनावी वादा रहा। चुनाव जीतकर 2019 में मोदी सरकार ने कामकाज संभालते ही संसद के रास्ते चुनावी वादे को हकीकत में बदल दिया और अब ये बैठक उससे आगे की शुरुआत है। बैठक की अहमियत सिर्फ केंद्र और कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भविष्य की घरेलू राजनीति, चुनावी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुटे विपक्ष के नेता भी ये सब अंदर तक महसूस कर रहे होंगे, इस बात से वे भी शायद ही इनकार करें।

जब दिल्ली में बैठक को लेकर काफी हलचल रही, कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में धारा 370 हटाए जाने को लेकर कहा कि उस एक घटना से दुनियाभर में भारत की छवि धूमिल हुई, बातचीत के बाद बाहर आए नेताओं के चेहरे देखने के बाद तो विचार बदल ही गए होंगे, राजनीतिक मजबूरी मन की बात साझा करने से भले ही रोक ले। समझने वाली बात ये है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यधारा के किसी भी नेता ने बातचीत से दूरी नहीं बनाई है और खुले मन से मीटिंग में हिस्सा लिया है। स्टैंड अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन ये भी कम है क्या कि केंद्र सरकार को हद से बढ़कर चेतावनी देने वाले अब्दुल्ला और मुफ्ती दोनों ही बातचीत की मेज पर बैठे भी और अपनी ख्वाहिशें भी शेयर की।

बातचीत भले ही पहले चुनाव या स्टेटहुड के बीच अभी थोड़ी उलझी हुई लगती हो, लेकिन अहम बात तो संवाद की शुरुआत है। मोदी सरकार का कहना है कि पहले चुनाव कराने की कोशिश होगी, फिर जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार किया जाएगा। कश्मीरी नेता पहले स्टेटहुड और उसके बाद चुनाव चाहते हैं। हो सकता है ऐसा कश्मीरी नेताओं के विश्वास में आई कमी की वजह से भी हो, लेकिन ऑप्शन तो उनके पास है नहीं। आगे की राह जैसे भी तय की जाने वाली हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ये पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सकारात्मक छाप छोड़ेगी ही। साथ ही, पाकिस्तान की भारत विरोधी कोशिशों को भी अपनेआप न्यूट्रलाइज भी करेगी।

बाकी चीजों के अलावा, ब्रांड मोदी पर भी असर तो होगा ही। दिल्ली चुनाव में भाजपा के दोबारा फिसड्डी साबित होने पर सवाल खड़े होने लगे तो संघ के मुखपत्र के जरिए सलाहियत आई कि स्थानीय स्तर पर नेताओं की पौध खड़ी की जानी चाहिए, न कि हर चुनाव में जीत के लिए मोदी-शाह के भरोसे रहना ठीक है। बिहार चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटने लगी थी और कोविड-19 के चलते अमित शाह को भी आइसोलेट होना पड़ा तो प्रधानमंत्री मोदी अकेले ही मोर्चे पर डटे रहे। नतीजा भी सामने आया, लेकिन बिहार से बंगाल पहुंचते-पहुंचते फिर सब चौपट हो गया।

अब अगले साल होने वाले उप्र और अन्य विधानसभाओं के चुनाव को लेकर देखें तो बंगाल में हार के बाद भाजपा के लिए अकेले ब्रांड मोदी के भरोसे रहना मुश्किल हो रहा था। जम्मू-कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी और कश्मीरी नेताओं की बैठक के बाद भाजपा चुनावी मैदान में उतरने से पहले काफी राहत महसूस कर ही रही होगी। जम्मू-कश्मीर पर 8 क्षेत्रीय दलों के 14 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की साढ़े तीन घंटे चली मीटिंग से माहौल थोड़ा खुशनुमा तो हुआ ही है, वैसे भी कश्मीरी नेताओं के लिए ये खुश होने के गालिब ख्याल से ज्यादा तो कुछ है भी नहीं।

उप्र विधानसभा चुनाव से पहले ब्रांड मोदी की वैल्यू बढ़ाना भाजपा के लिए बहुत जरूर हो गया था। खासकर बंगाल चुनाव की शिकस्त के बाद और उप्र में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले। जम्मू-कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजा पहल के बाद ये काम काफी आसान हुआ लगता है। आने वाले चुनावों में जम्मू-कश्मीर की चर्चा तो होनी ही थी, लेकिन अब कई तरीके से हो सकेगी। ये तो पक्का सुनने को मिलेगा कि भाजपा को लोगों ने वोट नहीं दिए तो उप्र में भी कश्मीर जैसी हालत हो जाएगी। ये लाइन बड़ी ही अजीब है, लेकिन राजनीति में कई बार कहा कुछ और जाता है और उसके मतलब बड़े ही अलग निकाले जाते हैं। ये कोई थोड़े ही पूछ पाता है कि क्या मौजूदा कश्मीर जैसी हालत हो जाएगी या फिर अगस्त, 2019 से पहले वाली, लेकिन संदेश यही जाता है कि पाकिस्तान परस्त आतंकवाद फैलने लगेगा। जैसे कहा तो सिर्फ यही जाता है कि अगर 'कब्रिस्तान बनता है तो श्मशान' भी बनना चाहिए या ईद पर बिजली रहती है तो दिवाली पर भी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसी बातें बड़े आराम से मंजिल तक का सफर तय कर लेती हैं।

● **कुमार विनोद**

विरोधियों को घेरना आसान होगा

जम्मू-कश्मीर पर बातचीत क्या आगे पीछे भी हो सकती थी? अगर ऐसा हो सकता था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक सर्वदलीय बैठक बुलाने की वजह क्या रही होगी? कश्मीरी नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ये बैठक 24 जून, 2021 को हुई। ध्यान दें तो मालूम होता है कि देश कांग्रेस सरकार के दौरान लागू हुई इमरजेंसी की पूर्व संध्या पर था। देश में आपातकाल 25 जून, 1975 को लागू किया गया था, और उसकी अपनी अलग कहानी है। इमरजेंसी लागू करने से चार महीने पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के साथ कश्मीर समझौता किया था, 24 फरवरी, 1975 को। शेख अब्दुल्ला, नेशनल कांफ्रेंस और गुपकार गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला के पिता थे। तब शेख अब्दुल्ला केंद्र में सत्ताधारी कांग्रेस की बदौलत मुख्यमंत्री बने थे और राजनीति भी उसी के भरोसे चलती रही। अब भी हालत यही है कि फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती की बची खुची राजनीति के जिंदा रखने के लिए केंद्र में सत्ताधारी भाजपा के ही सपोर्ट की जरूरत आ पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी और कश्मीरी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद चर्चा तो इंदिरा गांधी की भी हो रही है, लेकिन कश्मीर को लेकर नहीं बल्कि इमरजेंसी को लेकर। चाहें तो इसे भी आप एक तरीके से कांग्रेस मुक्त अभियान का हिस्सा ही समझ सकते हैं।

विपक्षी एकजुटता किसके खिलाफ?

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष में एकजुटता का प्रयास शुरू हो गया है। हाल ही में विपक्षी एकजुटता की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें यह सवाल खड़ा हो गया है कि यह एकजुटता किसके खिलाफ है।

विपक्षी एकजुटता के नाम पर हो रही ताजा जमघट अलग तो है। मानना पड़ेगा। मानना इसलिए नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं, बल्कि, इसलिए क्योंकि हर चीज बड़ी ही सावधानी के साथ होती नजर आ रही है। कहने की जरूरत नहीं जब भी ऐसी कोई सियासी कवायद होती है, निशाने पर सत्ता पक्ष और उसका नेता होता है। इस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही टारगेट पर हैं, समझना कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये विपक्षी लामबंदी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही हो रही हो, जैसी गतिविधियां चल रही हैं, निशाने पर कांग्रेस नेतृत्व, राहुल गांधी ही कहना बेहतर होगा, है भी और ये समझना भी कोई कठिन चीज नहीं है।

राष्ट्र मंच के बैनर तले अब तक जो नाम सामने आए हैं और सक्रिय नजर आ रहे हैं, वे हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी नेता शरद पवार, यशवंत सिन्हा और प्रशांत किशोर। अब इन गतिविधियों पर 2 लोगों की तरफ से सफाई भी पेश की जा चुकी है, एक तो माजिद मेमन और दूसरे प्रशांत किशोर का बयान भी कुछ-कुछ वैसा ही लगता है। दिल्ली में **विपक्ष के चर्चित** जमावड़े को लेकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सब किसी के खिलाफ नहीं है, न प्रधानमंत्री मोदी के और न ही कांग्रेस नेतृत्व के।

प्रशांत किशोर का बयान तो बड़ा ही विरोधाभासी है, खासकर उनके हालिया इंटरव्यू के जरिए उनकी रणनीति समझने के बाद। प्रशांत किशोर का कहना है कि मोदी के खिलाफ कोई तीसरा या चौथा मोर्चा खड़ा नहीं हो सकता और माजिद मेमन का भी बयान उसी रणनीति का हिस्सा जैसा लगता है। दिल्ली में मीटिंग को लेकर ऐसे समझाते हैं जैसे शरद पवार ने तो बस जगह मुहैया कराई थी और चाय-नाश्ते का इंतजाम भर किया था। मानते हैं कि नेता लोग जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन इतना भी क्या? असल बात तो ये है कि ताजा और तेज हो चली विपक्षी गतिविधियों के हर इनकार में इकरार की गंध आती है और हर सफाई किसी रहस्यमय रणनीति के संकेत देती है।

दिल्ली में हुई विपक्षी नेताओं की चर्चित मुलाकात को लेकर तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा मीडिया से मुखातिब हुए और एक जानकारी देकर चलते बने। सवाल पूछे जाते रहे लेकिन अनसुना करके निकल गए। जाते-जाते बता गए कि मीटिंग को लेकर माजिद मेमन, पवन वर्मा और घनश्याम तिवारी पूरी जानकारी देंगे।

एनसीपी नेता माजिद मेमन ने डिस्क्लेमर के साथ ही जानकारी देनी शुरू की। बोले, मीडिया में कहा जा रहा है कि राष्ट्र मंच की बैठक शरद पवार ने भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने के लिए बुलाई है, ये पूरी तरह गलत है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मीटिंग शरद पवार के निवास पर जरूर हुई, लेकिन मीटिंग उन्होंने नहीं बुलाई। लगे हाथ, माजिद मेमन ने दूसरी गलतफहमी भी दूर करने की कोशिश की, ये बैठक न तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चे बंदी है और न ही इसमें कांग्रेस को अलग-थलग रखा गया है।

फिर नाम लेकर गिनाए भी कि कांग्रेस के नेताओं को भी वो खुद बुलावा भेजे थे। बारी-बारी नाम भी बताए, मैंने खुद विवेक तनखा, मनीष तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन इनमें से कोई भी नेता इस समय दिल्ली में नहीं है। इसलिए कांग्रेस मीटिंग में नहीं आ सकी। गजब! क्या बुलावे की लिस्ट बनाई है, चुन-चुन कर उन नेताओं को ही बुलाया जो या तो कांग्रेस नेतृत्व को मौके-बेमौके जैसे-तैसे बर्दाश्त करने लायक सलाहियत देते रहते हैं या सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखे जाने पर हस्ताक्षर करते हैं या फिर चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस की हार पर सवालिया टिप्पणी किया करते हैं। कपिल सिब्बल और विवेक तनखा तो गुलाम नबी आजाद के साथ जम्मू-कश्मीर की जमीन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के सुर में सुर मिला चुके हैं। और उसमें भी बुलाने के बावजूद नहीं पहुंचे। मीटिंग के लिए जम्मू-कश्मीर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन विपक्ष की बैठक के लिए किसी ने भी दिल्ली लौटने की जहमत नहीं उठाई, न मनीष तिवारी, राष्ट्र मंच को जिनके दिमाग की उपज बताई जाती है और न शत्रुघ्न सिन्हा, जो राष्ट्र मंच की स्थापना के समय भी मौजूद रहे।

यशवंत सिन्हा को माजिद मेमन भी राष्ट्र मंच का नेता बता रहे हैं, लेकिन मनीष तिवारी और पूर्व राजनयिक केसी सिंह ने मिलकर राष्ट्र मंच

भाजपा जितनी कमजोर, दीदी का उतना फायदा

ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ही एक पैर से बंगाल और दो पैरों से दिल्ली जीतने की घोषणा कर दी थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक से तृणमूल कांग्रेस का करार 2026 तक के लिए बढ़ाए जाने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। चुनावी नतीजों के बाद कई मौकों पर दीदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। इससे एक बात तो साफ कही जा सकती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी विपक्ष का एक मजबूत चेहरा बनने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकुल रॉय को राज्यसभा भेजकर अभी से दिल्ली की राजनीति के समीकरणों को साधने की कोशिशें तेज कर दी जाएंगी। ऐसी रूम पॉलिटिक्स के लिए मशहूर मुकुल रॉय ने भाजपा में शामिल होने के बाद पश्चिम बंगाल के पंचायत, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसे साबित भी किया है। मुकुल रॉय अपने दम पर और ममता प्रेम से भाजपा के जितने नेताओं और विधायकों की तृणमूल कांग्रेस में वापसी होगी, भगवा दल को उतना ही नुकसान होगा।

विपक्ष एकजुट होगा या तीसरा मोर्चा बनेगा

तीसरा मोर्चा अब तक कभी भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाया है, और ऐसा न हो पाने की भी खास वजह रही है। देखा जाए तो हर बार आम चुनाव से पहले शुरू और खत्म हो जाने वाले प्रयासों के पीछे एक ही फैक्टर नजर आता है। अब अगर सवाल ये है कि क्या आगे भी तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं किया जा सकता? जवाब हां या ना में नहीं हो सकता क्योंकि ये कई चीजों पर निर्भर करता है। अब तक ये इसलिए संभव नहीं हो पाता है क्योंकि जिस किसी ने भी इसकी पहल की, उसकी एक ही महत्वाकांक्षा रही, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की। आखिरी बार ऐसी खुलेआम कोशिश मुलायम सिंह यादव की तरफ से हुई थी। लेकिन अगर ऐसे लोग तीसरे मोर्चे की तैयारी करें जिनका मकसद खुद प्रधानमंत्री बनना न हो तो संभावना बढ़ जाती है। 2019 के आम चुनाव के दौरान ऐसे दो नाम सामने आए थे, एक शरद पवार, और दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा। अगर तीसरे मोर्चे की कोशिश शरद पवार और प्रशांत किशोर मिलकर करते हैं तो स्थिति कुछ और हो सकती है।

की परिकल्पना की थी, और तब साथ में यशवंत सिन्हा, पवन वर्मा, दिनेश त्रिवेदी ने 2017 के आखिर में इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की।

2019 के आम चुनाव से करीब सालभर पहले जनवरी, 2018 में राष्ट्र मंच का औपचारिक तौर पर गठन हुआ। तब कांग्रेस की तरफ से रेणुका चौधरी भी शामिल हुई थीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी मौके पर मौजूद थे। तब पवन वर्मा जेडीयू में और दिनेश त्रिवेदी टीएमसी में हुआ करते थे। पवन वर्मा को भी प्रशांत किशोर के साथ ही नीतीश कुमार ने जेडीयू से बाहर कर दिया था। तब भी यशवंत सिन्हा ने कहा था कि राष्ट्र मंच गैर राजनीतिक एक्शन ग्रुप होगा, राष्ट्र मंच किसी पार्टी विशेष के खिलाफ तो नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों को हाइलाइट करने की कोशिश जरूर करेगा। ये तभी की बात है जब यशवंत सिन्हा मोदी विरोधी की आवाज बुलंद किए हुए थे। राष्ट्र मंच की दिल्ली में हुई ताजा बैठक में नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और आरएलडी नेता जयंत चौधरी के अलावा गीतकार जावेद अख्तर सहित कई बुद्धिजीवियों और पत्रकारों की शिरकत बताई जा रही है। राष्ट्र मंच के होस्ट शरद पवार को लेकर माजिद मेमन की ही तरह प्रशांत किशोर का भी बयान लग रहा है। प्रशांत किशोर ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मकसद से खड़ा करने की कोशिश वाले किसी भी विपक्षी मोर्चे में अपने रोल से इनकार किया है।

पश्चिम बंगाल चुनाव के वक्त से ही प्रशांत किशोर क्लब हाउस चैट हो या कोई इंटरव्यू हमेशा ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ ही करते देखे जाते हैं। अमित शाह से तुलना के सवाल पर भी खुद को अदना सा बच्चा बताते हैं, लेकिन मौका मिलते ही ये याद दिलाना भी नहीं भूलते कि तीन बार तो चुनावी शिकस्त दे चुके अब क्या बाकी है। जब राहुल गांधी को लेकर मोदी से जुड़ा सवाल होता है तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि दोनों नेताओं में कोई तुलना ही नहीं है। लोकप्रियता के मामले, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था कि ममता बनर्जी भी मोदी की तरह लोकप्रिय हैं, लेकिन ये बताना भी नहीं भूले कि भाजपा 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे की संभावना को लेकर भी प्रशांत किशोर करीब-करीब वैसी ही बातें कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में वे कहते हैं, मैं तीसरे या चौथे मोर्चे में विश्वास नहीं करता कि ये मोर्चा भाजपा को चैलेंज कर सकता है।

तीसरे मोर्चे को प्रशांत किशोर पुराना मॉडल और मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से मिसफिट मानते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर और शरद पवार की दो हफ्ते के भीतर तीसरी मुलाकात भी हो चुकी है। आखिर शरद पवार को प्रशांत किशोर इतना तेजी से क्यों समझना चाहते हैं? एनसीपी नेता शरद पवार के साथ लंबी मुलाकात को लेकर प्रशांत किशोर ने यही समझाने की कोशिश की थी कि दोनों ने कभी साथ मिलकर काम नहीं किया है। इसलिए एक-दूसरे को समझने के लिए मिले थे, लेकिन मुलाकातें इतनी जल्दी-जल्दी और ज्यादा हो रही हैं कि ये बातें बहानेबाजी लगती हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स में बहानेबाजी लगने वाली बातें, दरअसल, एक राजनीतिक बयान होती हैं। प्रशांत किशोर भी, दरअसल, अपने राजनीतिक बयान ही जारी कर रहे हैं। वैसे भी पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद तो वो बोल ही दिए थे कि आगे से वो इलेक्शन कैंपेन का काम नहीं करेंगे। फिर खबर आई कि तृणमूल कांग्रेस ने प्रशांत किशोर की कंपनी आई-पैक का कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक बढ़ा दिया है। मतलब, ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए समझने वाली बात ये है कि इसी पीरियड में 2024 के आम चुनाव भी होंगे।

ध्यान खींचने वाला वाकया है कि महज एक पखवाड़े के भीतर प्रशांत किशोर, शरद पवार से तीन बार मिल चुके हैं, आखिर एक-दूसरे को कितना जल्दी समझना है कि ताबड़तोड़ मुलाकातें करनी पड़ रही हैं। शरद पवार का राजनीतिक अनुभव और विपक्षी दलों के बीच होस्ट बनने की ये क्षमता ही है जो ममता बनर्जी के नाम पर प्रशांत किशोर को भी आकर्षित करती होगी। विपक्षी गठबंधन की ये कोशिश भी आम चुनाव के दौरान यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी की पहल के हिसाब से आगे बढ़ती नजर आ रही है, जिसमें क्षेत्रीय दलों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का फॉर्मूला पहले ही खोजा जा चुका है, लेकिन वो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। ममता बनर्जी को वो नुस्खा शुरू से ही कारगर लगता है, लेकिन राहुल गांधी पेंच फंसा देते हैं। हो सकता है पहले विपक्ष को कॉमन एजेंडे के साथ एकजुट कर लेने के बाद कांग्रेस से डील करने का विचार हो। जब कांग्रेस को छोड़ कर सारे क्षेत्रीय नेता एकजुट हो जाएंगे उसके बाद कांग्रेस के सामने व्यापक हित में बात मान लेने की मजबूरी देखने को मिल सकती है और फिलहाल ऐसी ही रणनीति पर ये सब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। मुश्किल ये है कि बड़े नेता या प्रमुख चेहरे या तो चुप हैं या राजनीतिक बयानों से गुमराह कर रहे हैं, लेकिन मिशन में शामिल छोटे नेता वे सारी बातें बता दे रहे हैं जिसका शक हो रहा है, ये तो साफ है कि ममता बनर्जी को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन शरद पवार या प्रशांत किशोर की असली भूमिका अभी सामने आना बाकी है।

● रजनीकांत पारे

चाल, चरित्र और चेहरा वाली भाजपा इस समय आंतरिक कलह से जूझ रही है। कुछ साल पहले तक एक रिमोट से चलने वाली पार्टी का कंट्रोल सिस्टम अनकंट्रोल हो गया है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि राज्यों में मुख्यमंत्रियों के विरोध में आवाजें उठने लगी हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सामने आना पड़ा है और उसने स्थिति को हैंडल करने के लिए जमावट शुरु की है। दरअसल, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस समय लड़खड़ा रहा है। कमजोर विपक्ष के कारण भाजपा इस स्थिति में भी सुदृढ़ है।

कंट्रोल सिस्टम अनकंट्रोल

आखिर भाजपा में हो क्या रहा है? क्यों अनुशासित मानी जाने वाली पार्टी अचानक राज्यों में विभाजित दिखती है? क्यों भाजपा की कमांड और कंट्रोल की प्रणाली ध्वस्त होती दिख रही है? भाजपा के संकटमोचकों को कैसे देश के अलग-अलग हिस्सों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। भूपेंद्र यादव के गुजरात के दो दौरे, बीएल संतोष के उप्र, कर्नाटक, गोवा और त्रिपुरा के दौरे और अरुण सिंह का तीन दिनों का बेंगलुरू प्रवास। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा में संकट के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा। राज्यों में भाजपा के इस संकट के चार छोर हैं। इनमें सबसे ऊपर है पार्टी के क्षेत्रीय क्षत्रपों की दावेदारी जो अपने राजनीतिक अस्तित्व के खातिर आलाकमान के कहे पर चलने से इनकार करते हैं।

येदियुरप्पा और राजे इसी श्रेणी में हैं, जो अपने राजनीतिक उत्तराधिकारियों के लिए जगह बनाने के आलाकमान के इशारों पर ध्यान नहीं देते। दूसरी समस्या पार्टी आलाकमान के करीबी वरिष्ठ भाजपा नेताओं की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं की है जो सोचते हैं कि उनका समय आ गया है। उदाहरण के लिए गुजरात में सीआर पाटिल तथा मप्र में नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय। तीसरी श्रेणी राजनीतिक दलबदलुओं की है जो सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, कि जिसके लिए उन्होंने अपनी वफादारी बदली थी। 2017 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सुदीप रॉय बर्मन त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बिप्लब देब को चुनौती दे रहे हैं। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, कांग्रेस से आयातित नेता हैं। एएच विश्वनाथ, जिन्हें लगता है कि येदियुरप्पा में सरकार चलाने लायक 'जोश' या 'ताकत' नहीं है, जनता दल (सेक्युलर) से भाजपा में आए हैं। संकट का चौथा पहलू उन लोगों की घर वापसी का है जो बेहतर पुरस्कार या सुरक्षा की उम्मीद में भाजपा में शामिल हो गए थे, यानि पश्चिम बंगाल के मुकुल रॉय और राजीव बनर्जी जैसे नेता। इन चारों श्रेणियों के अवज्ञाकारियों के कारण राज्यों में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनती दिख रही है।

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ऐसा अभी क्यों हो रहा है, खासकर ये देखते हुए कि महामारी प्रबंधन को लेकर संभवत: खराब हुई छवि के बावजूद मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी-शाह के दौर से पहले भाजपा में अंदरूनी कलह नहीं थी। लेकिन आज ये जिस स्तर पर है उसे देखकर हैरानी होती है, खासकर मोदी के पहले कार्यकाल में अंदरूनी कलह की अभाव से तुलना करने पर। क्या ऐसा इसलिए है कि लोकप्रिय क्षेत्रीय क्षत्रप या अन्य नेता भी विधानसभा चुनावों में हार और खराब प्रदर्शन से गलत सबक ले रहे हैं कि मोदी अपने दम पर उन्हें चुनाव नहीं जिता सकते, भले ही राष्ट्रीय स्तर पर खुद उनके लिए कोई चुनौती नहीं हो? इसलिए उन्हें अपना हित खुद देखना होगा! क्या ऐसा इसलिए है कि सत्ता, न कि वैचारिक विश्वास, भाजपा में उनकी राजनीति को परिभाषित करती है? इसलिए जब तक वे सत्ता

भाजपा नेताओं में भरोसे का अभाव

भाजपा में इन दिनों भरोसे का अभाव दिख रहा है। उप्र में कोविड आपदा के कुप्रबंधन को लेकर पार्टी सांसदों और विधायकों के हमलों का निशाना बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगता है कि सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ को तोड़ने की कोशिशों को फिलहाल नाकाम कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्त सहयोगी एके शर्मा को उप्र भाजपा का 17वां उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया जो कि राजनीति के लिए नौकरी छोड़ने वाले ताकतवर पूर्व आईएएस अधिकारी के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं कही जाएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ के लिए ये शायद एक लंबे आंतरिक संघर्ष की शुरुआत भर हो।

कायम रखने या प्राप्त करने के मामले में पार्टी के लिए प्रासंगिक हैं, तब तक सौदेबाजी के साधन के रूप में असंतोष या विद्रोह जायज है। या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पार्टी नेतृत्व को कमजोर पाते हैं, खासकर महामारी में शासन का कमजोर पक्ष उजागर होने के बाद? इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर भारत के सबसे लोकप्रिय नेता और सर्वाधिक कुशल राजनीतिक रणनीतिकारों में से एक मोदी और शाह के नेतृत्व वाली पार्टी राज्यों में अंतर्कलह में घिरी दिखती है तो केंद्रीय नेतृत्व इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

पिछले 7 साल में पहली बार हो रहा है कि भाजपा के मुख्यमंत्री दबाव में हैं। भाजपा शासित राज्यों में पार्टी के अंदर राजनीति हो रही है। जहां भाजपा का शासन नहीं है, जैसे राजस्थान या महाराष्ट्र वहां भी पार्टी के अंदर राजनीति तेज हो गई है। इसका भी एक कारण वही है, जो ऊपर बताया गया है। 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है या कम से कम दिख रहा है कि भाजपा के आला नेता दबाव में हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैकफुट पर हैं। कोरोना प्रबंधन, आर्थिक, बंगाल की हार आदि ऐसे मसले हैं, जिन पर पार्टी के अंदर चर्चा शुरू हो गई है। इससे केंद्रीय कमान कमजोर हुई है और आलाकमान के इकबाल पर भी सवाल उठा है। तभी प्रदेश में नेता अंदरखाने की तिकड़मी राजनीति में जुट गए हैं। भाजपा के मुख्यमंत्रियों या प्रदेश नेताओं पर दूसरा कारण यह है कि चुनावी तैयारियां चल रही हैं और मौजूदा हालात को देखते हुए पार्टी परेशान है।

इस लिहाज से उप्र सबसे अहम राज्य है। वहां अगले साल फरवरी-मार्च में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले हुए पंचायत चुनावों और विधानपरिषद् के चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। कोरोना प्रबंधन की वजह से सरकार की छवि बिगड़ी है तो सामाजिक समीकरण भी बिखरा हुआ दिख रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी को दिल्ली से लखनऊ भेजे जाने से भी सत्ता समीकरण बिगड़ा है। प्रदेश के संगठन महामंत्री और एक उपमुख्यमंत्री ने खुले तौर पर अलग मोर्चा खोला है। इससे भी मुख्यमंत्री पर दबाव बढ़ा है और प्रदेश संगठन में बिखराव दिख रहा है। इस बीच यह चर्चा चल ही रही है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 7 साल में यह पहली बार हुआ है कि भाजपा के किसी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बात चर्चा में आई है। यह अपने आप में अनहोनी बात है और इसका कई राज्यों में असर दिख रहा है।

राजस्थान में भाजपा के नेताओं ने खुलकर कहा है कि वसुंधरा राजे के बगैर भाजपा सत्ता में नहीं आ पाएगी। बिहार में चिराग पासवान के प्रति भाजपा नेताओं के प्रेम को जानते हुए भी नीतीश कुमार ने चिराग की पार्टी तुड़वा दी और 5 सांसदों को अलग करा दिया। उधर, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के समर्थक विधायकों ने एक के बाद एक बैठकें करके आलाकमान को बता दिया कि येदियुरप्पा को हटाना संभव नहीं है। जानकार सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक के कई विधायकों ने दिल्ली का दौरा किया और दिल्ली से लौटकर येदियुरप्पा के खिलाफ बयान दिए। कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान की शह पर उनके ऊपर दबाव बनाया गया लेकिन वे किसी दबाव में नहीं आए। पार्टी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बेंगलुरू में तीन दिन बैठे और विधायकों से एक-एक कर बात की।

मुख्यमंत्रियों पर दबाव की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह को हटाने से हुई थी। पहली बार हुआ था कि विधायकों के दबाव में भाजपा आलाकमान को अपने चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा था। इससे यह मैसेज गया कि आलाकमान चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों न हों उनको झुकाया जा सकता है। इसके बाद इस तरह के अभियान कई जगह शुरू हो गए। उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी दबाव में हैं और सुदूर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब भी दबाव में हैं। प्रदेश के एक दर्जन विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। बताया जा रहा है कि भाजपा छोड़ कर तृणमूल कांग्रेस में लौटे मुकुल रॉय ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर वहां भाजपा विधायकों में बगावत की स्थिति पैदा कर दी है। दो साल बाद होने वाले चुनाव तक बिप्लब देब को रखें या बदलें की दुविधा में पार्टी ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पूर्वोत्तर का मामला देखने वाले सचिव को अगरतला भेजा है।

● इन्द्र कुमार

बेवजह बनाया जा रहा दबाव

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बेवजह दबाव बनाने का प्रयास चल रहा है। ध्यान रहे कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर भाजपा की सरकार बनवाने के समय नरोत्तम मिश्रा भी काफी सक्रिय थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। अब नरोत्तम मिश्रा के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, पार्टी के संगठन महामंत्री सुहास भगत आदि के भी किसी न किसी राजनीति में शामिल होने की खबर है। दबाव की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री से मिलने के साथ-साथ मप्र के दो बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और थावरचंद गहलोत से भी मिले। सो, मप्र में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी दबाव में हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को प्रदेश की राजनीति से निकाला जाए। अगर वे केंद्र में मंत्री बन जाते हैं तो सरमा का काम आसान हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी दबाव में हैं लेकिन वे पार्टी की अंदरूनी राजनीति की वजह से नहीं हैं, बल्कि किसान आंदोलन की वजह से परेशान हैं।

पुराने जख्म हुए हरे...

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का कांग्रेसी नारा वाकई लुभावना था। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन के साथ नक्सल समस्या से मुक्ति के लिए बातचीत की राह खोलने का वादा भी लोगों को इस कदर भाया था कि आदिवासी मतदाताओं ने इलाके की 12 में से 11 विधानसभा सीटें सौंप दीं। लेकिन ढाई बरस पूरे कर चुकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के सामने 'सिलगेर गोलीकांड' मुंह बाए खड़ा है तो 'झीरमघाटी हमले की जांच', 'पेसा कानून' जैसे पुराने मुद्दे फिर सड़कों पर हलचल पैदा कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने 2018 में मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद कहा था, 'नक्सल समस्या से बंदूक के बल पर नहीं निपटा जा सकता। ठोस समाधान तक पहुंचने के लिए प्रभावित लोगों, खासकर आदिवासियों से बातचीत करनी चाहिए।' लेकिन 17 मई को सुकमा जिले के सिलगेर में हुई घटना सरकार की अलग ही छवि पेश कर रही है। उस दिन सुकमा जिले के सिलगेर सीआरपीएफ कैंप का विरोध कर रहे करीब 3,000 लोगों पर पुलिस के गोली चलाने से तीन लोग मौके पर मारे गए और एक घायल गर्भवती महिला ने बाद में अपने घर पर दम तोड़ा। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पुलिस का कहना है कि मारे गए लोग नक्सली थे, जबकि ग्रामीण, मानवाधिकार कार्यकर्ता और आदिवासी संगठन उन्हें आम नागरिक बता रहे हैं।

दरअसल, यह टकराव गत 12 मई को सीआरपीएफ की 153वीं बटालियन के कैंप स्थापित किए जाने के बाद शुरू हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सहमति के बगैर ऐसे कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षाबल के जवान जंगल में वनोपज बटोरने के लिए आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, उन्हें रोकते-टोकते हैं और परेशान करते हैं। हालांकि सीआरपीएफ और पुलिस का कहना है कि वह केवल माओवादियों को खदेड़ने के लिए कैंप लगा रही है। घटना के लगभग एक महीने बाद मुख्यमंत्री ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार भी यह चाहती है कि तथ्य सामने आएं और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन पर कार्रवाई में कोई कोताही नहीं होगी।' इस घटना के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि इससे पहले प्रदेश की भाजपा सरकार के दौरान वह कथित फर्जी मुठभेड़ों में आदिवासियों की हत्या का मामला उठाती रही थी।

बस्तर अंचल में सक्रिय मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील बेला भाटिया कहती हैं, 'कांग्रेस ने सत्ता में आते ही बस्तर के लोहंडीगुड़ा में टाटा स्टील प्लांट के लिए करीब 10 साल पहले किसानों से ली गई जमीनें उन्हें वापस दिलाने का फैसला किया। इससे लगने लगा था कि सरकार अपना चुनावी वादा पूरा कर रही है। लेकिन उसके बाद लगातार फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं जारी हैं। पेसा कानून, राजनीतिक वार्ता जैसे मसलों पर बात करने के लिए भी सरकार राजी नहीं है। अब लगता है कि कुछ भी नहीं बदला।' बेला भाटिया बस इतना फर्क देखती हैं कि पहले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को कठोरतापूर्वक रोका-टोका जाता था, अब वही काम चालाकी से किया जाता है।

पूर्व विधायक और आदिवासी महासभा के महासचिव मनीष कुंजाम कहते हैं, 'सरकार अपने वादे के उलट काम कर रही है। पेसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने से भी पीछे हट गई है। लगातार नए कैंप खोले जाने लगे हैं। नक्सल मामलों पर भाजपा जिस लीक पर चल रही थी, ठीक उसी नक्शेकदम पर भूपेश सरकार भी चल रही है।' कांग्रेस सरकार इसका खंडन करती है। सरकार का कहना है कि वह आदिवासियों का विकास चाहती है और नक्सल समस्या को भी हमेशा के लिए समाप्त करने पर जोर दे रही है। पार्टी प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी कहते हैं, 'भाजपा की सरकार आदिवासियों को दुश्मन समझती थी। रमन सरकार उद्योगपतियों के हितों को बढ़ाने में लगी थी। मौजूदा कांग्रेस सरकार के लिए आदिवासियों और बस्तर का सुख और शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है।'

राज्य सरकार भले ही यह दावा करती रही है कि राज्य में अब नक्सली बैकफुट पर हैं, मगर वारदात की शक्ल में सच्चाई कुछ और नजर आती है। इसी साल 3 अप्रैल को बीजापुर के तर्रेम थाना क्षेत्र में सुरक्षा बल और नक्सलियों की मुठभेड़ में 24 जवान शहीद हो गए थे। लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा की कुल 263 वारदात दर्ज की गईं। इनमें सुरक्षा बल के 22 और 55 आम नागरिक मारे गए, जबकि 79 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया गया है। वहीं साल 2020 में छत्तीसगढ़ में 315 नक्सली घटनाएं दर्ज हुईं। इनमें 36 जवान शहीद हुए। 75 आम नागरिक मारे गए और 44 नक्सलियों के मारे जाने का दावा भी किया गया है। बस्तर संभाग में 4 मार्च 2021 से 3 अप्रैल तक यानी लगभग एक महीने के भीतर नक्सलियों ने 31 हत्याओं को अंजाम दिया है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

> “ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद ऐसा नासूर बना हुआ है, जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार नक्सलवाद को खत्म करने जो भी कदम उठाती है, वह विवादों में फंस जाता है। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है। ”

झीरम पर झोलझाल

जब भी नक्सल मामले की चर्चा होती है तब कांग्रेस खुद को सबसे ज्यादा पीड़ित बताने से पीछे नहीं हटती। दरअसल, बस्तर की झीरम घाटी में 25 मई 2013 को माओवादियों के हमले में राज्य में कांग्रेस पार्टी की पहली पंक्ति के अधिकांश बड़े नेता सहित 29 लोग मारे गए थे। कांग्रेस पार्टी तब से घटना की जांच की मांग करती रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में ही झीरम घाटी कांड की एसआईटी जांच का फैसला किया था लेकिन ढाई साल बाद भी जांच उलझी हुई है। रवींद्र चौबे सारा ठीकरा केंद्र पर फोड़ते हैं। उनका कहना है कि झीरम घाटी की जांच पर केंद्र क्यों आपत्ति करता है, यह समझ से परे है। हम तो सीबीआई जांच की भी मांग कर चुके हैं लेकिन एनआईए की जांच भी अधूरी है।

महाराष्ट्र की राजनीति में अजब-गजब खिचड़ी पक रही है। आघाड़ी सरकार में शामिल पार्टियों में से शिवसेना और एनसीपी इन दिनों भाजपा के साथ नजदीकी बढ़ाते दिख रही हैं। शिवसेना का तो भाजपा से लगाव अभी भी है।

किसे चुनेगी भाजपा ?

कोरोना महामारी की दूसरी लहर में वैक्सीन, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता पर महाविकास आघाड़ी सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ भरपूर हमला बोला। लेकिन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नरम रहे। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना नहीं साधा गया। कोरोना से निपटने के लिए मोदी ने उद्धव सरकार की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम भले राजनीतिक रूप से साथ नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता टूट चुका है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, अगर मैं प्रधानमंत्री से अलग से मिलता हूं तो इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे का ये बयान सुशांत सिंह राजपूत, सचिन वाजे, अनिल देशमुख जैसे मामलों पर घिरी महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलों के बीच एक अवसर टटोलने की कवायद कही जा सकती है।

दरअसल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार की कथित मुलाकात के बाद भी राज्य में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। एमवीए सरकार के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके गुट के नेता भाजपा के साथ जाने के बड़े पक्षधर माने जाते हैं। अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनवा भी दी थी, लेकिन शरद पवार के दबाव में आकर जल्द ही घर वापसी कर ली थी। भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगियों में से एक रही शिवसेना को अच्छी तरह से पता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार का रिमोट शरद पवार के हाथों में है।

कोरोना महामारी की वजह से शिवसेना की प्रदेश और भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर छवि को बड़ा नुकसान हुआ है। यह नुकसान लंबे समय तक रहने वाला है और इसकी भरपाई शिवसेना और भाजपा के एक साथ आने से ही हो सकती है। मराठा आरक्षण जैसे मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर इसे राज्य सरकार के अधीन बताते हुए गेंद को फिर से महाराष्ट्र सरकार के पाले में डाल दिया है। वहीं, भाजपा को हालिया विधानसभा चुनावों से कोई खास लाभ नहीं मिला है। यह भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। इसी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक में यह तय किया गया है कि राज्यों के चुनाव में प्रदेश के ही नेताओं को ही चेहरा बनाया जाएगा। अगर इस फॉर्मूले पर भरोसा किया जाए, तो संभावनाएं बढ़ जाती है कि आने वाले समय में ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री वाले फॉर्मूले पर भाजपा तैयार हो सकती है।

उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और भाजपा का टॉप लीडर बता दिया। इन सबके बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने महाराष्ट्र को लेकर चल रही अटकलों पर कहा कि हमारी सरकार 5 साल पूरे करेगी। इसके साथ ही पवार ने इमरजेंसी के दौरान बालासाहब ठाकरे का इंदिरा गांधी को दिया वादा भी याद दिलाकर शिवसेना को वादाखिलाफी से बचने का संदेश भी दे दिया। मोदी-उद्धव की मुलाकात के बाद शिवसेना और भाजपा के बीच पैदा हुई खाई को पाटे जाने की संभावना बढ़ गई है। संकेत दिए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा और शिवसेना के बीच बढ़ी कड़वाहट को खत्म करने के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहने के बाद भी शिवसेना ने हिंदुत्व की राजनीति से समझौता नहीं किया है। इसी वजह से शरद पवार के बयान के मायने बढ़ जाते हैं। दरअसल, शरद पवार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार बिना किसी दिक्कत के अपना कार्यकाल पूरा करे। एमवीए सरकार में रहते हुए 5 साल तक शिवसेना का मुख्यमंत्री रह सकता है, लेकिन इस गठबंधन में कांग्रेस के होने से इसके टूटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में शिवसेना के पास भाजपा के रूप में एक स्थायी हल सामने तैयार खड़ा है। वहीं, एनसीपी को शायद ही भाजपा के साथ गठबंधन करने से कोई गुरेज होगा। शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में राहत मिलने पर एनसीपी आसानी से भाजपा को समर्थन देने को तैयार हो सकती है। इस गठबंधन से भाजपा के लिए हर चुनाव से पहले मुसीबत खड़ी करने वाली शिवसेना को सबक सिखाया जा सकता है।

● **बिन्दु माथुर**

भाजपा के सामने बड़ी चुनौती

महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में से एक को चुनना भाजपा के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। एनसीपी के साथ गठबंधन का विरोध आरएसएस भी करता रहा है। एनसीपी का समर्थन लेने पर भाजपा की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हो सकता है। बीते 7 सालों से केंद्र की मोदी सरकार पर कोई भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। अगर भाजपा एनसीपी के साथ गठबंधन करने की सोचती है, तो उसे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। वहीं, भाजपा के साथ जाने पर शिवसेना मुख्यमंत्री पद पर आधे-आधे कार्यकाल की मांग से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन, भाजपा इस फॉर्मूले पर तैयार होती तो, पहले ही सत्ता में आ चुकी होती। मोदी-ठाकरे की मुलाकात में इस बात पर चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन शायद ही इसका कोई हल निकला होगा। महाराष्ट्र में भाजपा के समान ही हिंदुत्व और मराठा स्वाभिमान के एजेंडे वाली शिवसेना के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। एनसीपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने से शिवसेना भी कटघरे में खड़ी होती दिखाई देती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते सवाल उद्धव ठाकरे पर भी उठेंगे। वहीं, 2014 में शिवसेना से अलग रहते हुए चुनाव में जाने पर भाजपा के खाते में 122 विधानसभा सीटें आई थीं। यह बहुमत के आंकड़े से 23 सीटें ही कम थीं। हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले मराठा आरक्षण, हिंदुत्व और कोरोना से उपजी अव्यवस्थाओं को आधार बनाकर भाजपा के पास सत्ता में वापसी का मौका हो। हालांकि, यह पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। महाराष्ट्र में फिलहाल भाजपा शिवसेना के और कमजोर होने का इंतजार कर रही है।

पायलट की उड़ान

> सत्तारूढ़ कांग्रेस में गेहलोत बनाम पायलट की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पायलट जब भी उड़ान भरते हैं, सरकार डगमगाने लगती है। उधर, भाजपा आस लगाए बैठी है कि कब पायलट उसके एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे।

कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की दिशाहीनता

कांग्रेस की वर्तमान मुश्किलों की असल जड़ शीर्ष नेतृत्व की दिशाहीनता और निर्णायक फैसले लेने में उदसीनता है। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद से परिस्थितियां और बिगड़ चुकी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में शामिल होना इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। पंजाब और राजस्थान में शीर्ष नेतृत्व के लचर रवैये से हालात बिगड़ते चले गए। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व समय रहते गुटबाजी को खत्म कर देता, तो पार्टी को शायद ही इन मुश्किलों से दो-चार होना पड़ता। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल लंबे समय से गुटबाजी का शिकार हो रहे हैं। हालांकि, उनके भाजपा में जाने की संभावना काफी क्षीण नजर आती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हाल ही में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पत्र लिखकर ताउते तूफान में क्षतिग्रस्त हुए 235 से ज्यादा मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए सरकारी अनुदान देने की मांग की है।

अपनी लगातार अनदेखी से नाराज सचिन पायलट पिछले कई दिनों से दिल्ली में इस कोशिश में लगे थे कि राहुल और प्रियंका गांधी उनका दर्द सुन लें। राहुल-प्रियंका के पास सचिन से मुलाकात के लिए वक्त नहीं था। सचिन बगैर मुलाकात जयपुर रवाना हो गए। कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को स्पष्ट संदेश भेज दिया है कि राजस्थान के बॉस अशोक गहलोत ही रहेंगे। हाईकमान ने इससे पहले सचिन को कांग्रेस महासचिव पद ऑफर किया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। मंत्रियों के 9 पद खाली हैं। सचिन चाहते हैं कि उनके 7 समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाए। सचिन की इस चाह पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं। जिस तरह राहुल गांधी से सचिन के करीबी संबंध हैं ठीक वैसे राजेश पायलट के राजीव गांधी से संबंध थे।

सचिन पायलट साल भर से नाराज हैं। कांग्रेस हाईकमान तो अपने नाराज युवा नेताओं के कंधे पर भरोसे का हाथ भी नहीं रख पा रही है। जिस पार्टी के लिए युवा नेता रात-दिन एक कर देते हैं उस पार्टी में अगर उनकी बात भी नहीं सुनी जाए तो फिर वह उन पार्टियों की तरफ क्यों न देखें जो उनके लिए पलक पांवड़े बिछाए हुए है। सिंधिया और जितिन के बाद सचिन नाराज हैं तो राहुल-प्रियंका के पास वक्त नहीं है उनसे बात करने का। सवाल यह है कि कांग्रेस नेतृत्व के पास जब भरोसे लायक युवा टीम ही नहीं होगी तो फिर वह किसके भरोसे सत्ता में वापसी का ख्वाब देख पाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर गए तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि अच्छा हुआ चले गए। जितिन गए तो कांग्रेस के ही कुछ नेता बोले कि वह अपनी सीट तक नहीं जीत पाए तो किस काम के थे। अब सचिन की नाराजगी को कम करने की कोई कोशिश नजर नहीं आती। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के बीच खिंची तलवारों को म्यान में रखवाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने कुछ कोशिश की भी लेकिन वह कोशिश भी किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। हालात तो यही बताते हैं कि अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव में कांग्रेस को वापसी के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। अगले साल पंजाब में भी चुनाव है। पंजाब में सिद्धू खुश नहीं हैं और उप्र में जितिन की शक्ल में एक झटका लगा है। राजस्थान के हालात बहुत बेहतर नहीं हैं। सचिन ने फिलहाल भाजपा में नहीं जाने की बात कही थी लेकिन 6 दिन मुलाकात के लिए उसका इंतजार जो हाईकमान होने के साथ दोस्त भी हो।

सचिन पायलट बगैर मुलाकात जयपुर लौट आए। जयपुर में अब कोई खिचड़ी पक जाए तो कांग्रेस एक और राज्य से अपना हाथ धो सकती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश पर सबसे ज्यादा समय तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस अगर अपने उन नेताओं को भी संभाल पाने में सक्षम नहीं है जिन्हें दोस्तों की शक्ल में देखा जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने मौजूदा हालात के आगे आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया है।

बीते साल राजस्थान में भी मप्र जैसे हालात बन गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बगावत कर दी थी। कांग्रेस सरकार गिरने के आसार बनने लगे, तो शीर्ष नेतृत्व ने नींद से जागते हुए स्थिति को संभालने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा और अहमद पटेल को भेजकर सरकार बचा ली। लेकिन, सरकार बचाने के लिए सचिन पायलट से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। बीते कुछ दिनों से राजस्थान में एक बार फिर से बगावत की सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने यहां 'डैमेज कंट्रोल' की कोशिशें शुरू कर दी है, लेकिन यह उतना आसान नजर नहीं आता हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाल-फिलहाल समझौता करा देने पर कांग्रेस के लिए मुश्किल कुछ ही समय के लिए टलती नजर आ रही है। पायलट और गहलोत के बीच लड़ाई सरकार में पद या मंत्रियों से कहीं आगे जा चुकी है। दरअसल, मप्र की ही तरह राजस्थान में भी कांग्रेस ने 'युवा नेतृत्व' की जगह सोनिया गांधी के 'करीबियों' पर भरोसा जताया।

राजस्थान में पहले ही दिन से सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पद के लिए मोर्चा खोल दिया था। लेकिन, शीर्ष नेतृत्व के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की है। पायलट पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अशोक गहलोत के नीचे काम नहीं करेंगे। इसके बहुत सीधे मायने हैं कि सचिन पायलट चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जाए। पायलट इससे कम पर मानने को तैयार नहीं होंगे। वहीं, अगर इसे अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए टाल भी दिया जाता है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह अशोक गहलोत के भी दोबारा मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ने पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सचिन पायलट अपने खेमे के विधायकों के साथ ही गहलोत खेमे के नाराज विधायकों को भी साधने की कोशिश में लगे हैं। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि राजस्थान कांग्रेस में किसी भी समय बगावत भड़क सकती है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

> लाख विरोध के बाद भी संघ ने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया है और उन्हें हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में आगे करके उप्र में फ्रीहैंड दे दिया है। दरअसल, संघ आगामी समय में योगी को बड़ी जिम्मेदारी देने की रणनीति पर काम कर रहा है।

योगी के आगे सब बेदम!

2017 के उप्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही उप्र का मुखिया कौन होगा, के कयास लगाए जाने लगे।

2014 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के बहुतायत राज्यों में भाजपा ने कमाल का प्रदर्शन किया था। दरअसल, तकरीबन हर विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाता था। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए उप्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव भाजपा के लिए सिरदर्द से कम नहीं होने वाला था। मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का दावा सबसे मजबूत था। संगठन की कमान संभालने वाले केशव प्रसाद मौर्य को इस जीत श्रेय दिया जा रहा था। लेकिन, पार्टी आलाकमान ने मनोज सिन्हा के नाम पर मुहर लगा दी थी। इन सबके बीच अचानक से एक नाम सामने आया योगी आदित्यनाथ। उसके बाद जो कुछ हुआ, वो सबके सामने है।

मुख्यमंत्री पद के हाथ से निकलने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के साथ योगी आदित्यनाथ की अदावत समय-समय पर सामने आती रही है। बीते दो महीनों में भाजपा और संघ के बीच बैठकों का दौर, भाजपा के नेताओं व संघ के पदाधिकारियों का लखनऊ दौरा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठकों ने पार्टी के अंदर असंतोष और असहमतियों को सामने ला दिया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तो जैसे इसी मौके की ताक में थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि 2022 में नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। जिसके बाद भाजपा और संघ ने लंच डिप्लोमेसी के जरिए इस विरोध को खत्म करने का बीड़ा उठाया। पार्टी और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ ने केशव मौर्य के घर पहुंचकर भोजन किया। जिसके बाद मौर्य की ओर से कहा गया कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ थे, हैं और रहेंगे।

इस बात को मानने से शायद ही इनकार किया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का पद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की वजह से नहीं, बल्कि संघ की इच्छा से मिला था। उप्र की रगों में अंदर तक बसी जाति और धर्म की सियासत को खत्म करने के लिए **संघ ने योगी** आदित्यनाथ के नाम का प्रयोग किया था। यही वजह रही कि मनोज सिन्हा का नाम फाइनल होने के बाद योगी को बुलावा भेजा गया। दरअसल, अपनी स्थापना के समय से ही संघ पूरे देश में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हिंदुत्व के आगे जाति को एक गौड़ मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के रूप में संघ के हाथ एक ऐसा चेहरा लगा है, जो जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। उप्र में योगी आदित्यनाथ ने अपने कौशल से इसे काफी हद तक पूरा कर दिखा भी दिया है। विपक्ष के जातिवादी होने के आरोपों को छोड़ दिया जाए, तो सूबे के मुखिया पर किसी जाति विशेष से लगाव के आरोप शायद ही लगे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि संघ योगी आदित्यनाथ को भविष्य में मिलने वाली बड़ी भूमिका के लिए तराशने में लगा हुआ है।

सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इस पूरी भागादौड़ी में योगी आदित्यनाथ ने सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत तक अपनी बात पहुंचा दी थी। योगी ने संघ को स्पष्ट कर दिया था कि वह कैबिनेट विस्तार जैसे फैसलों पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का हस्तक्षेप मंजूर नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ के हवाले से कहा गया कि प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल में केंद्र के हर फैसले का पालन किया गया है। सरकारी कामकाज से लेकर नियुक्तियों में भी केंद्र का दखल बना रहा है। वहीं, अगर अरविंद शर्मा को गृह मंत्रालय दे दिया जाएगा, तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी शक्तियां ही क्या रह जाएगी? केंद्र सरकार के भारी दबाव के बीच उन्होंने इस्तीफा सौंपने की बात भी कह डाली थी। जिस पर संघ तैयार नहीं हुआ और भाजपा नेतृत्व को इस मामले पर पीछे हटने की सलाह दी। जिस तरह योगी को मुख्यमंत्री बनने के लिए संघ का वरदहस्त मिला था, इस मामले पर भी संघ की ओर से छूट दे दी गई।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

रणनीति के तहत विरोध को दी गई हवा

2022 के उप्र विधानसभा चुनाव से पहले केशव के द्वार पर योगी ने पहुंचकर उनकी नाराजगी दूर कर दी है। एकजुटता के जिस संदेश का भाजपा और संघ को इंतजार था, वो भी सबके सामने आ चुका है। लेकिन, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम भूमिका संघ की रही है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिल्ली तलब किए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ शांत ही नजर आए। माना जा रहा है कि उप्र में आए इस सियासी भूचाल को हवा देने का काम संघ की ओर से ही किया गया था। योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाने और उनसे असहमति रखने वालों को सामने लाने के लिए यह पूरा घटनाक्रम एक फिल्मी पटकथा की तरह लिखा गया। कहा जा रहा है कि उप्र विधानसभा चुनाव 2022 से पहले संघ की ओर से साफ निर्देश था कि सभी समीकरणों को दुरुस्त कर लिया जाए। इसमें संगठन के अंदरुनी समीकरण भी शामिल थे। इसी के तहत योगी आदित्यनाथ पर अरविंद शर्मा को कैबिनेट में शामिल करने का दबाव बनाया गया। भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष और प्रभारी राधामोहन सिंह के जरिए इस दबाव को और बढ़ाया गया। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की तीन दिवसीय लखनऊ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश का दौरा करने चले गए। जिसके बाद उप्र में मुख्यमंत्री का चेहरा तक बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया।

‘चिराग’ तो बुझना ही था!

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान की डिक्शनरी से सुकून नाम का शब्द गायब हो गया था। पहले एलजेपी के 208 से ज्यादा नेता, फिर पार्टी का एकलौता विधायक और अब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में 5 सांसदों ने बगावत कर चिराग पासवान को पार्टी में अकेला छोड़ दिया है। बिहार में एलजेपी के खिलाफ ‘ऑपरेशन क्लीन’ के पीछे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा अहम वजह है। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव ने कभी कहा था कि नीतीश के पेट में दांत हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति को देखकर ‘पेट में दांत’ वाली कहावत सही साबित होती लगती है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से दुश्मनी निभाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के खिलाफ खुले तौर पर **बगावत करने वाले** एलजेपी सांसद चिराग पासवान के लिए अब एनडीए की राह भी खत्म हो चुकी है। कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार के ‘तूफान’ की चपेट में आने के बाद ‘चिराग’ का जलना मुश्किल ही था। बिहार विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही चिराग पासवान ने एनडीए में ज्यादा सीटों की मांग कर दी। जिस पर न तो नीतीश कुमार राजी थे और न ही भाजपा। सीटों की मांग से शुरू हुआ बवाल चुनाव आने तक एलजेपी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाने तक आ चुका था। इस दौरान चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साधा। चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 135 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया था। इसमें से भी चिराग ने उन सीटों पर ही ज्यादातर उम्मीदवार उतारे थे, जो एनडीए में रहने से जेडीयू के खाते में आई थीं। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था। उन्होंने तो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता दिया था। वहीं, चिराग ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जेल तक भिजवाने की बात कह दी थी।

बिहार के सियासी गलियारों में विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी और भाजपा के बीच डील होने की चर्चाएं भी बहुत आम रही थीं। जेडीयू के कई नेताओं ने तो विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और एलजेपी के गठबंधन के चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। वहीं, एलजेपी ने एनडीए से बाहर होने के बाद भाजपा के कई बागी नेताओं को चुन-चुनकर जेडीयू के खाते में गई सीटों पर उतारा था। चिराग पासवान की ये रणनीति जेडीयू को बहुत भारी पड़ी थी। नीतीश कुमार ने खुद माना था कि इस वजह से उन्हें करीब 36 विधानसभा सीटों का नुकसान हुआ। जिसकी वजह से एनडीए में जेडीयू की भूमिका छोटे भाई की हो गई थी। कहा जा रहा था कि भाजपा ने बिहार में जेडीयू के पर कतरने के लिए एलजेपी के साथ मिलकर यह रणनीति अपनाई थी।

चिराग के पास नहीं बचा है कोई रास्ता

एलजेपी में इस टूट के बाद चिराग पासवान के पास शायद ही कोई विकल्प बचा है। एलजेपी के टूट जाने का मतलब होता कि पासवान वोट बैंक बिखर जाता। आखिर उसी की बदौलत ही तो भाजपा ने बिहार में चिराग पासवान की मदद से अपना प्रभाव बढ़ाया है। आगे की बात और है, लेकिन अभी तक तो नीतीश कुमार नाम के ही मुख्यमंत्री लगते हैं क्योंकि भाजपा से पूछे बगैर बहुत सारे फैसले लेने की उनको छूट नहीं है। वर्चस्व की इस लड़ाई में आखिर चिराग पासवान कहां खड़े हैं? बेशक लोजपा का एकमात्र विधायक पार्टी छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी का हो चुका है। चिराग पासवान सभी सांसदों को निकालकर सिर्फ अकेले सांसद बनकर रह गए हैं, लेकिन रामविलास पासवान जो कोर वोट बैंक छोड़ गए हैं वो अब भी चिराग पासवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और आगे भी वो वोट बैंक ही उनकी ताकत बना रहने वाला है। चिराग पासवान सत्ता की राजनीति में भले ही हाशिये पर जा पहुंचे हों, कम से कम अभी तो ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन चुनावी राजनीति में अब भी उनकी अहमियत पहले की ही तरह बरकरार है और सबसे बड़ी वजह यही है कि भाजपा भी कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है।

‘बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे।’ राज्य में राष्ट्रीय जनता दल के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनी भाजपा ने यही बात कही थी। एनडीए विधानमंडल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने भी कह दिया था कि वे मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन भाजपा के आग्रह पर पद स्वीकार कर रहे हैं। नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने भाजपा की रणनीति को भांप लिया है। यही वजह है कि एलजेपी के खिलाफ ‘ऑपरेशन क्लीन’ चलाने के साथ ही वह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खुद को हर तरह से मजबूत करने में लगे हुए हैं। कुछ महीने पहले ही नीतीश कुमार ने अपने सियासी दुश्मन उपेंद्र कुशवाहा को गले लगाकर बिहार की राजनीति में ‘लव-कुश’ समीकरण (कुर्मी और कुशवाहा का जातिगत समीकरण) के सहारे अपना वोटबैंक बढ़ाने का दांव चल दिया है। कहा जाता है कि बिहार की करीब 30 विधानसभा सीटों पर लव-कुश समीकरण अपना सीधा प्रभाव रखता है।

राजनीति के मौसम विज्ञानी कहे जाने वाले दिवंगत नेता रामविलास पासवान की विरासत को संभालने में नाकाम रहे चिराग पासवान ने पार्टी के नेताओं की राय को किनारे रखते हुए अलग रुख अपनाया। चुनाव में बुरी तरह हार के बाद एलजेपी के 208 छोटे-बड़े नेताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया। फिर मटिहानी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह ने भी जेडीयू की राह पकड़ ली। वहीं, पशुपति कुमार पारस के 6 में से 5 विधायकों के साथ बगावत करने के हालिया घटनाक्रम के पीछे भी नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की भूमिका होने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल, बगावत के बाद पशुपति पारस सीधे ललन सिंह से मिलने गए थे। वहीं, एलजेपी की एमएलसी सुशांत सिंह राजपूत की भाभी और मंत्री नीरज सिंह बबलू की पत्नी नूतन सिंह पहले ही भाजपा में शामिल हो चुकी हैं।

● **विनोद बक्सरी**

इजरायल से बड़ी उम्मीद

इजरायल को मिली सामारिक बढ़त पर असर

संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका से एफ-35 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है, लेकिन एक संधि से बंधे होने के कारण इजरायल की सहमति के बिना यह संभव नहीं है। दरअसल, 1973 में अमेरिका ने इजरायल को मध्यपूर्व के बाकी देशों के मुकाबले सबसे उन्नत रक्षा साजोसामान देने का समझौता किया था, जिसे वह आज तक निभा रहा है। अगर वह संयुक्त अरब अमीरात को एफ-35 की बिक्री करता है तो इजरायल को मिली सामारिक बढ़त पर असर पड़ेगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि किसी और मुस्लिम देश की सामरिक ताकत में इजाफा हो। वह भली-भांति जानता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे ये मुस्लिम देश कब दुश्मन खेमे में चले जाएंगे, कोई नहीं जानता। इतिहास गवाह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गतिशीलता अजीबोगरीब मोड़ लेती रही है। तुर्की इसका सबसे ताजा उदाहरण है। जरूरत के सीमेंट से बंधे भारत और इजरायल के संबंध पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दौर में खूब परवान चढ़े। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों नेताओं की केमिस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चर्चा का विषय रही। खासकर संयुक्त राष्ट्र में यरुशलम और गाजा पट्टी को लेकर हुए वोटिंग के दौरान भारत ने गैरहाजिर रहकर इजरायल के साथ रिश्तों को नई मजबूती दी। भारत ने पूर्वी यरुशलम को फिलस्तीन की राजधानी की मान्यता देने से भी इनकार किया है।

इजरायल में 13वें प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका है। लेकिन 120 सीटों वाली संसद में केवल एक वोट से विश्वासमत हासिल करने वाली इस सरकार की स्थिरता को लेकर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि इसमें शामिल आठों राजनीतिक पार्टियां सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के नाम पर एकजुट हुई हैं। इनमें दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी और वामपंथी पार्टियों के अलावा पहली बार अरब मुसलमानों की एक पार्टी भी शामिल है। यही वजह है कि नई सरकार बनने के बाद से ही पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसे गिराने को लेकर काफी आश्वस्त दिख रहे हैं, लेकिन वहां के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भारत को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दोनों देशों के संबंध ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां ऐसी घटनाएं उसे प्रभावित नहीं कर सकती हैं।

इजरायल ने भारत के साथ गर्मजोशी भरा रिश्ता बनाए रखने की इच्छा जताते हुए इसे नई ऊंचाई देने का संकल्प व्यक्त किया है। दोनों देशों के रिश्तों में स्थिरता की ठोस वजहें हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान और चीन हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। खासकर पाकिस्तान का रवैया काबिलेगौर है। बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने वाले सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे ताकतवर देश संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पर इजरायल को लेकर पाकिस्तान के कट्टर दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आया है। वह अब भी फिलस्तीन के समर्थन में खड़ा है, क्योंकि वह उसे कश्मीर के साथ जोड़कर देखता है।

इजरायली कानून के मुताबिक 18 साल की उम्र में सेना की कमांडो यूनिट में भर्ती होने वाले नाफ्ताली बेनेट 6 साल तक स्पेशल फोर्सेस में अफसर रहे। अनिवार्य सैन्य सेवा के बाद उन्होंने एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी की स्थापना की और न्यूयार्क चले गए। बहुत कम समय में उन्होंने अपनी कंपनी को एक मुकाम पर पहुंचाया और 33 साल की उम्र में उसे 14.5 करोड़ डॉलर में बेचकर इजरायल लौटे। वर्ष 2006 में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ जुड़कर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। जब नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने तो बेनेट को अपना चीफ आफ स्टाफ नियुक्त किया, लेकिन यह रिश्ता बहुत दिन तक नहीं चला। इसके बाद वे दक्षिणपंथी होम पार्टी में शामिल हुए और जल्दी ही शीर्ष तक का सफर तय किया। वर्ष 2013 में उनकी पार्टी को 13 सीटें मिली थीं। नापसंदगी के बावजूद नेतन्याहू ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल किया। अब वह 49 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन चुके हैं। धुर दक्षिणपंथी होने के साथ ही उन्हें व्यावहारिक राजनेता माना जाता है। वे फिलस्तीन को स्वतंत्रता दिए जाने के खिलाफ हैं। बेनेट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए नए हैं। इसलिए उन्हें भारत सहित अन्य देशों के नेताओं के साथ रिश्ते कायम करने में समय लगेगा। भारत और इजरायल हाल के वर्षों में काफी करीब आए। बहरहाल, तुर्की की विदेशी नीति में बदलाव के कारण भी भारत और इजरायल हाल के वर्षों में काफी करीब आए हैं। नाटो का सदस्य होने के कारण तुर्की के अमेरिका और उसके फलस्वरूप इजरायल के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। उसे अमेरिका से उन्नत सैन्य साजो-सामान भी मिले, लेकिन हाल के वर्षों में तुर्की के राष्ट्रपति तैयप आदरेगान के रुख में नाटकीय बदलाव आया है और वह अब सऊदी अरब की जगह मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने का सपना पाल रहे हैं। इस अभियान में पाकिस्तान उसके साथ है। भारत विरोध पर टिके पाकिस्तान को सऊदी अरब से झटके पर झटका लगने के बाद अब तुर्की में एकमात्र उम्मीद नजर आ रही है।

इजरायल के नजरिए से देखा जाए तो सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाने के उसके अभियान में भारत अहम कड़ी साबित हो सकता है। परंपरागत रूप से भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तो यह नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। खाड़ी के देशों को भी इजरायल से रिश्ते सामान्य करने के लिए भारत की जरूरत है। खाड़ी देश इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। कट्टर छवि से बाहर निकलकर उदारवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही, अपनी सुरक्षा को लेकर भी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, लेकिन इस काम में इजरायल सबसे बड़ा रोड़ा है।

● **राजेश बोरकर**

रूस और अमेरिका के बीच के तनाव से भारत को सामरिक और आर्थिक तौर पर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अमेरिका और रूस के तनाव को जेनेवा शिखर सम्मेलन ने समाप्त तो नहीं किया है पर रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलने की प्रक्रिया तेज अवश्य हुई।

सुलह की राह पर अमेरिका-रूस

बीते दिनों जेनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 3 घंटे चली शिखर बैठक ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए, जिनसे यह संकेत मिला कि दोनों देश अपने मतभेद खत्म करने को तैयार हैं। अब दोनों देश एक-दूसरे के राजनयिकों को अपनी-अपनी राजधानियों में लौटने देंगे। उक्त बैठक में दोनों राष्ट्रपतियों के बीच यूक्रेन के नाटो में लौटने पर सार्थक चर्चा हुई। साइबर हमले पर संयुक्त प्रयास की सहमति बनी। इसके साथ ही परमाणु स्थिरता को लेकर चर्चा जारी रखने पर भी सहमति बनी। वहीं मानवाधिकार सहित कई मामलों पर असहमति भी रही। रूसी विपक्षी नेता एलेक्स नवेलनी के बारे में चर्चा तो हुई, लेकिन दोनों के बीच इस पर मतैक्य नहीं रहा। अपनी प्रेस कांफ्रेंस की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन की तारीफ की। उन्हें एक अनुभवी राजनेता बताया और कहा कि बाइडन डोनाल्ड ट्रंप से काफी अलग हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत बेहद रचनात्मक रही और उन्हें नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई शत्रुता की भावना थी। राष्ट्रपति बाइडन ने भी अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि बैठक रचनात्मक रही। उनके मुताबिक वह आशान्वित हैं कि रूस-अमेरिका संबंध वापस पटरी पर लौटेंगे। हालांकि दोनों विश्व नेताओं ने न ही भोज सत्र में हिस्सा लिया और न ही संयुक्त प्रेस वार्ता की। इससे दोनों वैश्विक शक्तियों के बीच चल रहे तनाव का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

शिखर बैठक में तनाव के बावजूद दोनों नेताओं में काफी सकारात्मकता थी। यह सच है कि रूस और अमेरिका के बीच पिछले एक दशक से काफी तनाव चल रहा है, लेकिन इस बैठक ने इस तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। अमेरिका अभी भी वैश्विक महाशक्ति है और रूस भी अपनी कमजोर आर्थिक शक्ति के बावजूद सामरिक तौर पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति है। पिछले एक दशक से अमेरिका-रूस तनाव ने वैश्विक राजनीति को काफी प्रभावित किया है। इसका परोक्ष फायदा चीन को मिला है। पश्चिम की ओर से चौतरफा हमले से घिर चुके पुतिन ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ही चीन से हाथ मिलाया है। हालांकि पुतिन को पता है कि रूस और चीन के बीच दीर्घकालीन दोस्ती संभव नहीं है। रूसी सामरिक विशेषज्ञ रूसी प्रशासन को चेतावनी दे चुके हैं कि सुदूर पूर्व रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति अभी भी जारी है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक करोड़ से कम जनसंख्या है, जबकि इससे लगते चीनी क्षेत्रों में 15 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। इस क्षेत्र को लेकर चीन का ऐतिहासिक दावा रहा है। हालांकि वर्ष 2005 में चीन ने रूस के साथ इस क्षेत्र में सीमा समझौता कर लिया था।

राष्ट्रपति पुतिन पिछले दो दशकों से अपने विभिन्न रूपों में रूस पर शासन कर रहे हैं। तमाम आंतरिक और बाहरी विरोधों के बाद भी उनका शासन इसलिए चल रहा है, क्योंकि वह रूस की विशाल भौगोलिक एकता को अक्षुण्ण रखने में सफल रहे हैं। वह चीन के संभावित विस्तारवाद से साइबेरिया के विशाल भू-भाग पर उभर रहे खतरे को महसूस कर रहे हैं। रूस चीन के अधीनस्थ नहीं रह सकता, जैसा कि परिदृश्य तेजी से उभर रहा है। वैश्विक राजनीति में पुतिन रूस की नंबर दो की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। वह ऐसा मानते हैं कि रूस की भौगोलिक एकता को बनाए रखने और वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका को निभाने के लिए रूस को वैश्विक राजनीति में नंबर दो पर होना ही चाहिए। जेनेवा शिखर सम्मेलन रूस को इस स्थिति की ओर लौटाने का एक कदम है। पिछले कई वर्षों में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा बढ़ा है और रूस चीन के अधीनस्थ की भूमिका में दिखने लगा है। ऐसा न तो रूस के हित में है और न ही अमेरिका के हित में है।

चीन का लगातार आर्थिक और सामरिक तौर पर उभरना अमेरिका के वैश्विक शक्ति के स्वरूप के लिए खतरा है, जिसे अमेरिका बखूबी समझता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी पृष्ठभूमि से रूस की नब्ज टटोलने के लिए जेनेवा शिखर सम्मेलन किया। जहां बाइडन चाहेंगे कि रूस से संबंध सुधारकर वह अपना सारा ध्यान चीन से निपटने पर लगाएं, वहीं चीन किसी भी तरह नहीं चाहेगा कि रूस और अमेरिका का वर्तमान गतिरोध समाप्त हो। ज्ञात हो कि एशिया-प्रशांत नीति ओबामा प्रशासन के साथ ही प्रारंभ हुई थी, जिसमें बाइडन उपराष्ट्रपति थे। अब इस नीति को बाइडन प्रशासन ने मजबूत करने का संकल्प लिया है। क्वाड के संकल्प को मार्च 2021 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन कर राष्ट्रपति बाइडन ने गंभीरता से आगे बढ़ाया है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके सदस्य हैं। इसकी सदस्यता का विस्तार भी प्रस्तावित है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

भारत के लिए जेनेवा शिखर सम्मेलन काफी सकारात्मक

भारत के लिए जेनेवा शिखर सम्मेलन काफी सकारात्मक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल कूटनीति के कारण आज अमेरिका और रूस दोनों भारत के करीबी मित्र हैं। रूस और अमेरिका के बीच के तनाव से भारत को सामरिक और आर्थिक तौर पर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अमेरिका और रूस के तनाव को जेनेवा शिखर सम्मेलन ने समाप्त तो नहीं किया है, पर रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलने की प्रक्रिया को तेज अवश्य किया है। जाहिर है कि इससे चीन पर रूस की बढ़ती निर्भरता तेजी से कम होगी। रूस के भारत के साथ संबंधों में और मधुरता आएगी और चीन की वैश्विक राजनीति में बढ़ती धमक पर भी लगाम लगेगी। जेनेवा शिखर सम्मेलन विश्व-शांति के साथ-साथ भारत के लिए भी अच्छी खबर लेकर आया है। इससे भारत के समक्ष वह दुविधा की स्थिति दूर होगी, जो अक्सर दोनों देशों को लेकर उत्पन्न हो जाती है।

ब्याही लड़कियों का क्या?

आज मैंने पकड़ौआ शादी की 20 घटनाओं की हेडलाइन देखी। हर घटना को लड़कों को हिसाब से लिखा गया है। किसी भी घटना में इस बात का जिक्र नहीं है कि उस लड़की का क्या होगा। आखिर उस लड़की की शादी भी तो जबरन ही कराई जाती है। तो फिर क्यों उस लड़की की गलती ना होते हुए भी उसे दोषी मानकर उसका तिरस्कार किया जाता है। वैसे भी शादी चाहें पकड़ौआ हो या अरेंज मैरिज, जब बात लड़की की शादी की होती है तो सारी चीजें माता-पिता और घरवाले ही तय करते हैं। एक तरह से यह ब्लाइंड मैरिज होती है। यानी शादी के बाद अगर पति अच्छा निकल गया तो समझो आपकी लॉटरी निकल गई, वरना जिंदगी जाए भाड़ में। इसके बाद ना तो घरवालों को मतलब होता है ना ही ससुराल वालों को, बस शादी के नाम का ठप्पा लगाना जरूरी है। इन जबरन बनाई गई जोड़ियों में सबने लड़कों को बेचारा बनाया, लेकिन उस लड़की का जिक्र किसी ने नहीं किया। जैसे मान लिया गया है कि लड़कियों के साथ तो यही होता है इसमें नया क्या है। लड़कियों के मामले में इस बात को मान लिया गया है कि उनकी शादी में उनकी मर्जी मायने नहीं रखती, इसमें पूछना क्या है।

एक लड़की अपनी शादी को लेकर क्या-क्या सपने देखती है। उसके कितने अरमान होते हैं। माना कि उसके सपनों के राजकुमार हकीकत में नहीं होते लेकिन लड़की क्या कोई गाय-भैंस है जिसे किसी के भी खूंटे से अचानक से बांध दिया जाए, भले उसकी मर्जी हो या ना हो। लड़कियां भी इसी को अपनी किस्मत समझ लेती हैं। असल में हमारे समाज में किसी परंपरा को तोड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे कहने को तो दहेज गैरकानूनी है लेकिन डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट दहेज देना तो पड़ता ही है। इसी तरह है पकड़ौआ विवाह, कहने के लिए इस पर कबका बैन लगा दिया गया है कि लेकिन आज भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पकड़ौआ शादी पहले के जमाने से चली आ रही है। जिसमें कुछ दबंग लोगों का गिरोह, लड़के को पकड़कर जबरन उसकी शादी करवा देते हैं। लड़कियों को इस तरह की शादी करने के लिए उन पर जबरदस्ती की जाती है। यानी दोनों लोगों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ होती है लेकिन लोगों को दया के पात्र बस लड़के लगते हैं लड़कियां नहीं। कई लोग तो ऐसी शादियों के लिए लड़कियों को ही दोषी मानते हैं, कि इसकी वजह से ही यह सब हुआ है।

कुछ साल पहले इसी विषय पर भाग्यविधाता नाम का सीरियल, फिल्म 'अंतरद्वंद' और जबरिया जोड़ी आई थी। दरअसल, 80 के दशक में उत्तर बिहार में खासतौर पर बेगूसराय में पकड़ौआ विवाह के मामले खूब सामने आए थे। भाग्यविधाता में दिखाया गया कि कुछ सालों बाद सब ठीक हो जाता है और वह लड़का जबरन पत्नी बनाई लड़की को अपना लेता है, लेकिन यहां तक का उसका सफर काफी पीड़ादायी होता है। वहीं जबरिया जोड़ी में पकड़ौआ शादी का महिमा मंडन किया गया है। यानी बताया गया है कि ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है, लेकिन अंत में बात लड़के के दया के ऊपर आकर अटक जाती है। यानी लड़की की जिंदगी का फैसला उस लड़के के हाथ में होता है जिसे हम खबरों में दया का पात्र बताते हैं, लड़की का पक्ष किसी को क्यों नहीं दिखता। परिवार वाले तो लड़की की जैसे-तैसे शादी कराके छुटकारा चाहते हैं लेकिन उसके फ्यूचर का क्या होगा इस बारे में कोई नहीं सोचता। ऐसा लगता है कि सबकुछ लड़कियों के भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। अगर पति दया करके जबरन पत्नी बनाई गई लड़की को अपनाले, तब तो ठीक है वरना उसकी जिंदगी है वो जाने, वह जीए चाहे मरे लेकिन जबरन के बनाए गए ससुराल में दया का पात्र बनकर किसी कोने में पड़ी रहे। जहां उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब पकड़ौआ शादी में पति ने कई सालों तक पत्नी को अपनाया ही नहीं। अगर अपना भी लिया तो इस शादी के कड़वे यादों से उबर नहीं पाया। लड़की बस सांसे लेती है, उसे कोई पारिवारिक सुख नहीं मिलता। ससुराल वाले भी बहू के रूप में बस कर्मपूर्ति करते हैं। इन सब के बीच अगर पति ने अपना भी लिया तो वह हर वक्त इसी गिल्ट में जीती है कि वह किस तरह अचानक पति पर बोझ बन गई।

आंकड़ें की बात करें तो बिहार राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, जनवरी और नवंबर 2020 के बीच राज्य में 7,194 पकड़ौआ शादी के मामले, 2019 में 10,925 मामले, 2018 में 10,310 केस और 2017 में 8,972 जबरिया शादी के मामले दर्ज किए गए। वहीं आपराधिक गिरोह के डर के कारण बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ ही नहीं पाते हैं। ये गिरोह जबरन शादियां कराने के लिए लड़की के घरवालों से पैसे लेता है, लेकिन उनको यह रकम देने में हर्ज नहीं होता क्योंकि यह दहेज के पैसे से बहुत कम होता है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

लड़की के पक्ष में सहानुभूति क्यों न हो?

असल में जिन जगहों पर ऐसी शादियों के मामले आते हैं, वहां दहेज की खूब परंपरा है। एक तरह से पकड़ौआ शादी को दहेज के खिलाफ एक निदान के रूप में माना गया। ऐसे विवाह के लिए अक्सर योग्य कुंवारे लड़कों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाती है फिर उन्हें अगवा कर उन लड़कियों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके परिवार के लोग दहेज नहीं दे सकते। लड़कियों के पिता खुद लड़कियों पर जबरदस्ती करने के लिए दबाव बनाते हैं कि वे पकड़ौआ शादी करें। भले गलती पिता की होती है क्योंकि शादी के बाद उनकी जिम्मेदारी तो खत्म हो जाती है, लेकिन सोचिए अगर वह लड़का दूसरी शादी कर ले तो? भोगना लड़की को पड़ता है। इस तरह की शादियों की एंडिंग हमेशा हैपी नहीं होती। कुल मिलाकर यहां लड़के की कृपा पर ही लड़की की जीत होती है। असल में इस तरह की शादियों के पीछे मजबूरी की वजह है दहेज, लड़कियों की अशिक्षा और जातिवाद। दहेज के खिलाफ सामाजिक परिवर्तन के लिए गैरकानूनी ही सही, लेकिन लोगों ने ये तरीका अपना लिया। मगर सोचिए इस सारी कहानी में असली पीड़ित कौन है...लड़का या लड़की?

हरहु नाथ मम संकट भारी

श्रीरामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। उत्तर भारत में रामायण के रूप में कई लोगों द्वारा प्रतिदिन पढ़ा जाता है। श्री रामचरितमानस में इस ग्रंथ के नायक को एक महाशक्ति के रूप में दर्शाया गया है जबकि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में श्रीराम को एक मानव के रूप में दिखाया गया है। तुलसी के प्रभु राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं।

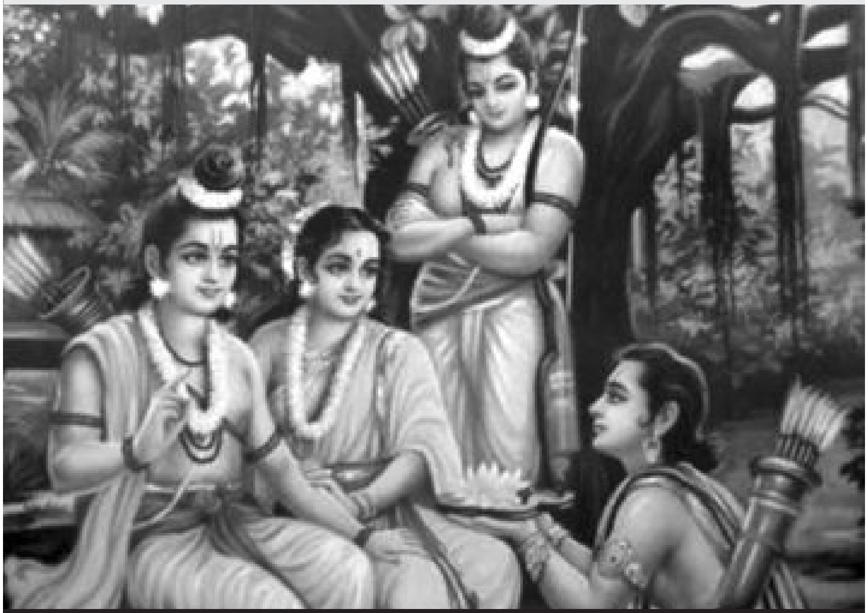

सनातन धर्म से जुड़े प्रत्येक ग्रंथ आदि में मानव जीवन से संबंधित ऐसी बातों का विवरण किया गया है, जिसे अपनाने वाले व्यक्ति का जीवन तो बेहतर होता ही है साथ और भी कई समस्याओं से निजात मिलती है। तो आप अब तक इतना तो समझ ही गए होंगे कि हम आपको धार्मिक शास्त्रों वर्णित कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं।

तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बताने वाले हैं हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से श्री रामचरितमानस में उल्लेखित ऐसे दोहों के बारे में जिनके जाप से आपको अपने जीवन की तमाम समस्याओं से निजात मिल सकती है।

कहा जाता है रामचरितमानस के दोहे न केवल श्रीराम के जीवन के बारे में बताते हैं बल्कि इनका मंत्र आदि के तौर पर उच्चारण भी किया जाता है। इतना ही नहीं इन दोहों के जप से व्यक्ति की एक प्रकार की नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि श्री रामचरितमानस के कुछ ऐसे दोहे और चौपाईयों के बारे में जिनका महत्व अपने आप में अधिक है।

जिस व्यक्ति को अपने जीवन में रोजगार न मिल रहा हो, उसके श्री रामचरितमानस के इस दोहे का जप करना चाहिए।

बिस्व भरण पोषण कर जोई,
ताकर नाम भरत अस होई।

कुछ लोगों को अपने जीवन में अचानक से कई तरह की विपत्तियों का सामना करना पड़ता, जिसका निवारण कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे में इस दोहे का मंत्र के रूप में उच्चारण करना चाहिए।

जपहि नामु जन आरत भारी,
मिटाई कुसंकट होई सुखारी।

जिन छात्रों को अपने शिक्षा में मनचाही सफलता न मिल रही हो, उन्हें उच्च विद्या प्राप्ति के लिए निम्न दोहे का जपना चाहिए।

गुरु गृह पढ़न गए रघुराई,
अलप काल विद्या सबआई।

अविवाहित युवक-युवतियों को अच्छे वर-वधु पाने की इच्छा को साकार करने के लिए इस दोहे को निरंतर मंत्र की तरह जपना चाहिए।

सुनु सिय सत्य असीस हमारी,
पूजहि मनकामना तुम्हारी।

बहुत से बीमारियों ने घेर रखा हो तो ऐसे में रोगों के नाश के लिए व इनसे छुटकारा पाने के लिए इसका जप करें।

दैहिक, दैविक, भौतिक तापा,
राम राज नहीं काहूंहि व्यापा।

जीवन में आने वाले तमाम संकटों से मुक्ति के लिए तथा ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए निम्न दोनों दोहों का जप करना चाहिए।

दीन दयाल विरदु सम्भारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी।
कामिहि नारी पियारी जिमी,
लोभी प्रिय जिमि दाम।
तेहि रघुनाथ निरंतर,
प्रिय लागहु मोहि राम।

श्री रामचरित मानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। उत्तर भारत में रामायण के रूप में कई लोगों द्वारा प्रतिदिन पढ़ा जाता है। श्री रामचरितमानस में इस ग्रंथ के नायक को एक महाशक्ति के रूप में दर्शाया गया है जबकि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में श्रीराम को एक मानव के रूप में दिखाया गया है। तुलसी के प्रभु राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इस ग्रंथ में रामायण को अच्छी तरह से चौपाईयों के माध्यम से बताया गया है किस तरह राम का जीवन रहा, कैसे महापुरुष बने। इसीलिए रामचरित मानस की हर एक चौपाई का मंत्र सिद्ध है जिन्हें सच्चे मन से पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपके अशुभ दिन चल रहे हैं। जिसके कारण आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इन मंत्रों के प्रभाव से आपके घर समृद्धि बनी रहेगी। यह मंत्र सिर्फ सुख के लिए ही नहीं है बल्कि बारिश न होने पर, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हो या फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए हो। इन मंत्रों का मनन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जानिए रामायण के इन चैपाई मंत्रों के बारें में जिससे आपको रामायण कामधेनु की तरह मनोवांछित फल देती है।

रामचरित मानस में कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जिनका विपत्तियों तथा संकट से बचाव और ऋद्धि-सिद्ध के लिए मंत्रोच्चारण के साथ पाठ किया जाता है। इन चौपाइयों को मंत्र की तरह विधि विधान पूर्वक 108 बार हवन की सामग्री से सिद्ध किया जाता है। हवन चंदन के बुरादे, जौ, चावल, शुद्ध केसर, शुद्ध घी, तिल, शक्कर, अगर, तगर, कपूर नागर मोथा, पंचमेवा आदि के साथ निष्ठापूर्वक मंत्रोच्चार के साथ करें। इन चौपाई मंत्र को अधिक समझनें के लिए तुलसी दर्शन कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवै रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। रामचरितमानस में भगवान श्रीराम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को यह भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए सांसारिक व्यवहार करते हुए नाम का भजन करें ताकि हमारा जीवन सुखमय हो।

● ओम

विश्वास

कचरा बीनने वाले का बेटा विश्वास, जब अपने पिता को काम करते देखता, तो वह भी उनकी सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ा देता। पिता की बीमारी ने उसकी डॉक्टर बनने की इच्छा को और मजबूत कर दिया था।

लेकिन जब वह सुनता कि बिना कोचिंग कुछ नहीं हो सकता। तब कुछ समय के लिए उसका खुद पर से विश्वास डोल जाता। एक क्षण बाद ठहर! फिर आगे बढ़ जाता। उसके विद्यालय के एक अध्यापक उसका मार्गदर्शन समय-समय पर करते रहते थे। जिससे उसका मनोबल हमेशा बना रहता था।

ऐसा चलते-चलते परीक्षा का समय भी आ गया। परीक्षा देकर जब वह बाहर निकला, तब जो आवाज उसके कानों में पड़ी, उससे उसके होश फाख्ता हो गए। बच्चे आपस में बात करते नजर आए मुझे एक प्रश्न नहीं आया- मुझे दो- मुझे तीन।

मुझे तो पूरे पन्द्रह प्रश्न! यह सोचकर विश्वास का ग्राफ आरंभ पर पहुंच गया था। निराश हो विश्वास, जाकर पिता का हाथ बंटाने में लग जाता है।

एक दिन अचानक विद्यालय के अध्यापक को अपने घर के दरवाजे पर मिठाई के साथ देख वह हस्तप्रध! रह जाता है...

‘गुरु जी आप!’

‘शाबाश! बेटे तुमने परीक्षा पास कर ली।’ मिठाई खिलाते हुए।

आज विश्वास का अपने ऊपर विश्वास सौ प्रतिशत दौड़ लगा रहा था और वह आसमां तले उड़ने को बेकरार था।

– नूतन गर्ग

हम पत्ते

हम पत्ते, पतझड़ तक जीवन,
फिर मिट्टी हो जाएगा तन।
मेरे बचपन में बसंत ने,
पिता सरिस है मुझको पाला।
डाली ने मां बनकर मुझको,
प्यार दिया है भार सम्हाला ।
कलियों से अठखेली भी की,
जब किशोरवय था मेरा तन।
हम पत्ते, पतझड़...
मैंने सूरज की गर्मी को,
मरकत जैसे तन पे झेला।
तपती हुई गर्म पछुआ से
मैंने हाथ मिलाकर खेला।
मैंने तरुवर की चोटी से
देखा गर्मी में तपता वन।
हम पत्ते, पतझड़...
सावन की पुरवाई आई,
अंक पाश शीतलता लाई।
मन ही मन हम सब हरषाये,
करके बूंदो की अगुवाई।
मेघों ने चमकाया धो कर,
तन मेरा, जब आया सावन।
हम पत्ते, पतझड़...
जाड़ो की वो कारी रातें,
शीतलहर तन को तड़पाती।
कफन सरिस कुहरे की चादर,
धूप दूर तक नजर न आती।
मलिन हो गए पीले पड़कर,
शाखाओं से छूटा दामन।
हम पत्ते, पतझड़...

–डॉ. दिवाकर दत्त त्रिपाठी

संतान

अरे पुतवा! तू अभी तक यहीं खाट पर बैठा है।

गांव की सारी पंचायत, छोटे-बड़े सभी पौधे लगाने के लिए जमा हो गए हैं। ‘सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं चल-चल जल्दी उठ।’

‘सरपंच जी ने मुझे भेजा है तुझे बुलाने को।’ – मक्खन दादा ने कहा।

पुतवा कुछ देर खामोश रहा मानो डूबते सूरज-सी उदासी उसके अंतर में समा गई हो।

‘मैं क्या करूंगा आकर! आपको तो पता है न कि मेरा जवान बेटा नहीं रहा। शहर बस गया था हमारे लिए चार पैसे कमाने को, पर अकेला था, उसे वक्त पर सही इलाज न मिल सका! लोग कालाबाजारी करते रहे और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही।

मुझे नहीं लगाना कोई पौधा-वौधा मेरा तो संसार ही उजड़ गया...(पुतवा का गला रुंध गया वह आगे कुछ न कह सका)

‘देख पुतवा, हम तेरा दर्द समझते हैं। हम तेरा बेटा तो वापिस नहीं ला सकते, पर क्या तू चाहेगा कि महामारी ने जिन बेकसूर मासूमों को दुष्ट लोगों के कुकर्मों की वजह से लपेट लिया है। वो कहावत हैं न – ‘आटे के साथ घुन भी पिस जाता है।’ हम एक पौधा लगाकर अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो प्रकृति का क्रोध कम कर सकेंगे, शायद ये महामारी सिमट जाए।

अच्छी कोशिशें कभी जाया नहीं होतीं। अगर तू अपने बेटे के नाम से एक पौधा लगाएगा तो ये समझना कि तूने कितनों को जीवन दिया है।

यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी तेरी अपने बेटे को। मक्खन दादा ने पुतवा के कांधे पर हाथ रखकर कहा।

पुतवा- ‘हां! दादा (गंभीर सोच के साथ उठता है।)

वो एक पौधा नहीं मेरी वो संतान होगा जो सभी को सांसें देगा बिना भेदभाव के।

चलो चलता हूं।’

– भावना अरोड़ा ‘मिलन’

फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि अगर कोई भारतीय ठान ले तो वह किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत में कोई दूसरा मिल्खा अभी तक नहीं मिल सका है।

...यूं ही नहीं कोई मिल्खा हो जाता है!

फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत के पूर्व धावक मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपने जीवन काल में ही किवदंती बन चुके मिल्खा सिंह के निधन पर हर कोई दुखी है। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने प्रिय खिलाड़ी को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने स्टेटस और स्टोरी में उनके चित्र लगाए, जो आम भारतीयों में उनके सम्मान और लोकप्रियता को दर्शाता है।

सन् 1932 में पाकिस्तान में जन्मे मिल्खा सिंह भारत की आजादी के समय विभाजन के बाद अपने परिवार को दंगों में खोने के बाद किसी तरह बचते-बचाते भारत आए। बाद में वे सन् 1951 भारतीय सेना में भर्ती हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेना में खिलाड़ियों को मिलने वाली अतिरिक्त खुराक के लालच में मिल्खा सिंह ने लंबी दूरी की दौड़ में हिस्सा लेने का फैसला किया। इसके बाद तो मिल्खा सिंह ऐसा दौड़े कि कुछ वर्षों में भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए।

हम भारतीयों के लोकमानस में वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध खेल क्रिकेट के नायक सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन और धोनी के अतिरिक्त अन्य खेलों में कुछ ही ऐसे नाम है, जैसे हॉकी के मेजर ध्यानचंद, कुश्ती के दारा सिंह और दौड़ में मिल्खा सिंह जो एकसमान रूप से हम भारतीयों के लोक मानस में सर्वोच्च स्थान पर रच बस चुके हैं। इन सबकी कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऐसे हस्तांतरित हुई जैसे हम अपने पौराणिक या धार्मिक नायकों और योद्धाओं को याद रखते हैं।

यह समझना भी अपने आप में रोचक है कि लोग अपने बच्चों को इन सबकी कहानियां इसी रूप में सुनाते रहे मानों यह सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि लोक के सामान्य जीवन और आचरण में मानक भी रहे हों। मिल्खा सिंह की छवि भी ऐसे ही नायक के रूप में ख्यात रही है। व्यवहार की सरलता और देश के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करने का जज्बा ही मिलकर किसी सामान्य इंसान को मिल्खा सिंह बनाती है।

हमें यह भी याद रखना होगा कि मिल्खा सिंह ने जो कुछ भी सीखा बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के दौड़ के मैदान में ही सीखा। एक बार आप इनकी उपलब्धियों को इस तथ्य के साथ देखें फिर समझ जाएंगे कि क्यों कोई यूं हीं मिल्खा सिंह नहीं बन जाता। मिल्खा सिंह प्रथम भारतीय धावक हैं जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों के साथ-साथ कॉमनवेल्थ खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता हुआ था।

सन् 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। टोक्यो में ही 200 मीटर की वह प्रसिद्ध दौड़ हुई जिसमें मिल्खा सिंह ने अपनी हंसी उड़ाने वाले पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक जो कि उस समय एशिया के सर्वश्रेष्ठ धावक थे, उनको बहुत बारीक अंतर से हराकर उनकी एशियाई सर्वश्रेष्ठता को ध्वस्त कर दिया। इसी प्रकार सन् 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर और 400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था।

1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इस दौड़ को खत्म करने के बाद मिल्खा सिंह मैदान में ही बेहोश हो गए। इसी दौड़ के बाद विजयलक्ष्मी पंडित ने जब मिल्खा सिंह से यह कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू ने इस जीत पर बधाई के साथ उनसे कुछ भी चीज मांग लेने का प्रस्ताव भेजा है तो जवाब में मिल्खा सिंह ने अपने सरल व्यवहार के अनुरूप तमाम वैभव या सुख की लालसा को दरकिनार करने हुए विजय लक्ष्मी पंडित से कहा कि जिस दिन वह भारत वापस आए उस दिन देशभर में अवकाश कर दिया जाए।

ओलंपिक में 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ 45.73 सेकेंड में पूरी की थी, वे जर्मनी के एथलीट से सेकेंड के मात्र सौवें हिस्से से पिछड़ गए थे। हालांकि ओलंपिक में मिल्खा सिंह के नाम कोई पदक नहीं है लेकिन उन्होंने जितने भी दौड़ या पदक जीते हैं उतना उनकी महानता के बखान के लिए पर्याप्त है।

लोकमानस में सम्मान के साथ जगह बनाना और जिंदगी भर उस पर काबिज रहना विरले लोगों को नसीब होता है। क्रिकेट के भगवान भारत रत्न सचिन तेंडुलकर यूं ही नहीं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह कहते हैं कि 'आपके निधन से हर भारतीय के मन में खालीपन घर कर गया है। लेकिन आप आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे।'

● आशीष नेमा

अमरीश पुरी की आदत थी कि वो वीडियो-ऑडियो इंटरव्यू नहीं देते थे। कई मौकों पर उनकी फुटेज दिखती भी है तो वो शूटिंग के दौरान की है। अखबारों या मैगजीन को इंटरव्यू देते वक्त भी वो अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं करने देते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि लोग उनकी आवाज को ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में ही सुनें। इंटरव्यू लेने वाले से वो साफ कह देते थे कि प्लीज, अपना रिकॉर्डर बंद कर लीजिए। जब मैगजीन से उन्हें इंटरव्यू के लिए फोन आता था, तो वो कहते थे कि अगर कवर स्टोरी में जगह मिलेगी तभी इंटरव्यू दूंगा।

मुंहमांगी फीस नहीं मिलने पर फिल्म छोड़ देते थे अमरीश पुरी

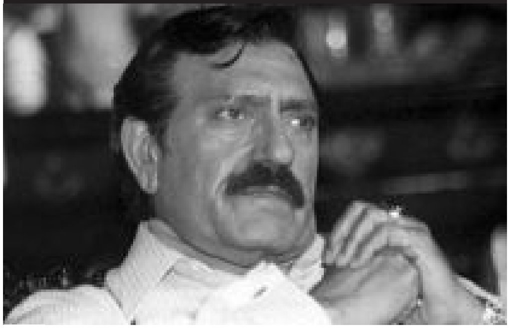

निगेटिव रोल से शुरुआत करने वाले अमरीश पुरी ने 90 के दशक में पॉजिटिव के किरदार निभाने शुरू किए थे। उनका कद काफी बढ़ चुका था और कई बार ऐसा भी होता था कि मुंहमांगी फीस न मिलने पर वो फिल्म छोड़ दिया करते थे। एनएन सिप्पी की एक फिल्म उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें मांग के मुताबिक 80 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे थे।

अमरीश ने साफ कहा था- पैसे नहीं तो फिल्म नहीं

अमरीश ने इंटरव्यू में कहा, जो मेरा हक है, वो मुझे मिलना चाहिए। मैं एक्टिंग के साथ कोई समझौता नहीं करता। तो फिल्म के लिए कम पैसा स्वीकार क्यों करूं। लोग मेरी एक्टिंग देखने आते हैं। प्रोड्यूसर्स को पैसा मिलता है, क्योंकि मैं फिल्म में होता हूं। तो क्या प्रोड्यूसर्स से मेरा चार्ज करना गलत है? जहां तक सिप्पी की फिल्म की बात है तो वह मैंने बहुत पहले साइन की थी। वादा था कि साल के अंत में फिल्म शुरू होगी। लेकिन तीन साल बीत चुके हैं। मार्केट का भाव बढ़ गया है। अगर वो मुझे उतना पैसा नहीं दे सकते तो मैं उनकी फिल्म नहीं कर सकता। मशहूर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में बताया था, एक बार हमारे एक दोस्त और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। पत्नी सरवाइव कर गई, लेकिन दोस्त और उसका बेटा क्रिटिकल थे। हॉस्पिटल में उनके लिए रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ी, जो कि अमरीश का ग्रुप भी था। हमारे उस दोस्त से उनका कोई परिचय नहीं था। बावजूद इसके वो अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर्स से बोले, मैं ब्लड देना चाहता हूं, जितनी जरूरत हो ले लीजिए। दुर्भाग्य से दोस्त और उसका बेटा बचे नहीं। लेकिन बिना किसी के कहे अमरीश का ब्लड देना मुझे आज भी याद है। श्याम बेनेगल के मुताबिक सत्यदेव दुबे के थिएटर ग्रुप में वो अमरीश से पहली बार मिले थे। तब अमरीश लाइफ इंश्योरेंस एजेंट भी थे और मोटरसाइकिल से इधर-उधर घूमा करते थे।

बैंक की नौकरी छोड़कर रीमा लागू ने रखा था इंडस्ट्री में कदम

मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, रंगीला, जय किशन, कल हो ना हो और कुछ-कुछ होता है जैसी कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में नजर आ चुकी रीमा लागू ने मां का रोल निभाते हुए अपनी बेहतरीन अदाकारी से एक अलग पहचान बनाई थी। रीमा लागू नाम से पहचान हासिल करने वालीं एक्ट्रेस का असली नाम नयन भदभदे था। एक्ट्रेस का जन्म 21 जून 1958 में मराठी स्टेज एक्ट्रेस के घर हुआ था। मां से प्रेरित होकर रीमा भी बचपन में ही कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार नजर आई हैं। एक्ट्रेस ने अपने सीनियर एक्टिंग कैरियर की शुरुआत मराठी स्टेज परफॉर्मर बनकर की थी। धीरे-धीरे एक्ट्रेस कई टीवी शोज का हिस्सा बनने लगी। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद रीमा लागू की 1979 में बैंक में नौकरी लग गई। एक्ट्रेस 10 सालों तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कर्मचारी रही थीं। बाद में एक्टिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए एक्ट्रेस ने हमेशा के लिए अपनी नौकरी को अलविदा कह दिया। रीमा लागू पहली बार साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म कयामत से कयामत तक में जूही चावला की मां बनी थीं। इसके बाद उनका कैरियर बनता चला गया और वे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम बन गईं।

फिल्म बूम फ्लॉप हुई तो कर्ज चुकाने में बिक गया था जैकी श्रॉफ का घर

आयशा श्रॉफ ने फिल्म बनाई थी बूम, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद जैकी श्रॉफ और उनके परिवार पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। अब जैकी ने इस नुकसान के बाद हुए असर को शेयर किया है। जैकी को उस वक्त अपना घर बेचना पड़ा था और कर्ज चुकाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ी थी।

बूम साल 2003 में रिलीज हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, पद्मा लक्ष्मी, मधु सप्रे, जीनत अमान और कटरीना कैफ भी थीं। जैकी से पहले टाइगर भी इस फिल्म के फ्लॉप होने से हुए नुकसान के बारे में बता चुके हैं। अब जैकी ने भी 18 साल पुरानी परेशानी के बारे में बताया है। जैकी ने एक इंटरव्यू में कहा-मुझे पता था कि हमने कुछ करने की कोशिश की और हमने कुछ खो दिया। अगर मुझे इसके लिए भुगतान करना पड़ा था, तो मैंने भुगतान किया भी। जितना हो सकता था उतना काम किया और सभी का पैसा चुकाया ताकि मेरे परिवार का नाम क्लीयर हो जाए। जून 2020 में टाइगर ने उस वक्त को याद करते हुए कहा था-मुझे याद है कि कैसे हमारा फर्नीचर एक-एक करके बेचा गया था।

'मैं कहना यह चाहता हूं कि मैंने तो तुम्हें यहां भेजते हुए तुम्हारी किस्मत में मौज की मौज लिखी थी, पर तुमने गृहस्थी बसा चादर से बाहर पांव निकाल लिए तो मैं भी क्या करूं? पांव चादर के अंदर ही रखना किसका धर्म बनता है? मेरा या तुम्हारा? वैसे विश्वास न हो तो ये रिकार्ड देख लो।' कह वह अपने सूटकेस को वहीं खोलता आगे बोला, 'आप लोगों के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यही है।

इस दर्द की दवा क्या है!

अपने घर में वैसे तो हर रोज किसी को कुछ न कुछ हुआ करता है, किसी को जुकाम है तो किसी को खांसी। किसी को घुटने में दर्द रहता है तो किसी को सिर में दर्द। किसी को जुलाब लगे होते हैं तो किसी को कब्जी हुई होती है। कई बार तो ये सब देखकर मन करता है कि सरकार से अनुरोध करूं कि हे सरकार! मुझे कुछ दे या न दे पर मेरे घर में एक सरकारी अस्पताल का पट्टा ही लगा दे। कम से कम दफ्तर में साहब को भी मुझे बकने की बीमारी से मुक्ति मिले और मुझे भी साहब की किच-किच से मोक्ष मिले। रिटायरमेंट के इन बचे दो महीनों में तो शान से सिर उठाकर समय पर दफ्तर जा सकूं।

पर, जिसकी किस्मत में घरवालों ने इज्जत से जीने का एक पल भी शेष न रखा हो वहां विधाता भी बेचारा क्या लिखे! उस रोज विधाता मिला था, अचानक। तब मैं खुद से खुद की नजरें बचाता सड़ी सब्जी आधे दाम में ले रहा था। क्या करूं भाई साहब, मजबूरी है। अब परिवार को कुछ न कुछ तो खिलाना ही है न! आदमी कुछ खाकर बीमार हो तो बीमारी के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। दूसरी ओर घर के सफल मुखिया होने का भ्रम भी बना रहता है।

'और बंधु, क्या हाल हैं?' विधाता ने पीछे से मेरा झोला खींचा।

'कौन?' मुझे गुस्सा आया। पर फिर शांत हो गया कि यार तू इस वक्त बाजार में है और बाजार में किसी का कुछ भी खींचा जा सकता है। पीछे मुड़ा तो अजीब-सा बंदा देखा। बंदे बड़े-बड़े देखे पर ऐसा न देखा था। मैंने अपना गुस्सा आगे के बंदे पर पान की पीक के साथ पिचकते कहा, 'आपको मैंने पहले कहीं देखा नहीं, माफ कीजिएगा।'

'यार मैं वही हूं जिसके आगे तुम सबेरे उठने से पहले रोज नाक रगड़ते हो कि हे विधाता, आज से तो मेरी किस्मत बदल दे। आज कुछ फुर्सत में था तो मैंने सोचा कि आज क्यों न खुद-ब-खुद चलकर...' कह अपने को विधाता कहने वाला मुस्कुराया।

'तो यार, क्या किस्मत लिख तूने मुझे इस लोक में भेजा? जा मैं तुझसे कोई बात नहीं करता। गधे की भी इससे अच्छी किस्मत होती है। और मैं तो आदमी था!'

'गुस्सा थूको मित्रा! कुछ मेरी सुनो तो सच का पता चले।' कह विधाता ने बड़ी आत्मीयता से मेरे गृहस्थी के भार से टूटे कंधों पर अपने दोनों हाथ रखे तो मेरा गुस्सा कुछ शांत हुआ।

'तो कहो, क्या कहना चाहते हो? वैसे भी आज तक मैंने सभी को सुना ही है। कहने का मौका तो भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं।' कहते-कहते मेरा जुकाम से बंद हुआ गला और रुंध गया।

'मैं कहना यह चाहता हूं कि मैंने तो तुम्हें यहां भेजते हुए तुम्हारी किस्मत में मौज की मौज लिखी थी, पर तुमने गृहस्थी बसा चादर से बाहर पांव निकाल लिए तो मैं भी क्या करूं? पांव चादर के अंदर ही रखना किसका धर्म बनता है? मेरा या तुम्हारा? वैसे विश्वास न हो तो ये रिकार्ड देख लो।' कह वह अपने सूटकेस को वहीं खोलता आगे बोला, 'आप लोगों के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यही है। पंगा खुद लेते हो और दोष मुझे देते हो। अब मैं तो आप लोगों की जानदार किस्मत ही लिख सकता हूं न। किस्मत की इज्जत बचाए रखने के लिए संभलकर चलना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। फिर दोष देते फिरते हो। ये कहां का न्याय है बंधु? अब मैं चुप! बंदे ने कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं। बात उसकी बिलकुल सच थी।

'तो अब कुछ हो सकता है क्या?'

'क्यों नहीं, इस देश में हर चीज का इलाज करने वाले संसद से सड़क तक झोला खोला बैठे हैं करके, करवाके तो देखो। नहीं करने, करवाने के बहाने हजारों हैं, सरकार की तरह।'

'कैसे? यहां तो हर दवाई में खोट है। खोट वाली दवाई का क्या इलाज करेगी? सरकार महंगाई का इलाज करती है तो वह इलाज से बाहर हो जाती है, सरकार भुखमरी का इलाज करती है तो वह इलाज से बाहर हो जाती है, सरकार बेरोजगारी का इलाज करती है तो वह इलाज से परे हो जाती है, सरकार भ्रष्टाचार का इलाज करती है तो वह इलाज से परे हो जाता है, सरकार भय का इलाज करती है तो वह इलाज से परे हो जाता है, ऐसे में मैं कौन सी दवाई लूं?'

'ईमानदार होने की दवाई लो।' कह वे अंतर्ध्यान हो लिए।

ये दवाई किस स्टोर पर मिलेगी भाई साहब? सारा शहर तो छान चुका हूं। यहां के दवाई वालों के पास तो यह आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। आपके शहर हो तो कृपया भेज दीजिएगा।

● अशोक गौतम

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth
पाक्षिक
अक्स
www.akshnews.com

अक्स
डूबती अर्थव्यवस्था को चाहिए ऑक्सीजन
चुनौतियों के चक्रव्यूह
सांसों की सौदेबाजी
विपक्ष पस्त सरकार मस्त
प्राकृतिक आपदाएं खलनायक कौन?
तिरंगे का अपमान कौन जिम्मेदार...?
डायरियों का भ्रम जाल...!
कैसे खुशहाल होगा किसान?

E-Magazine पढ़ने और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं
www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल
फोन:0755-4017788,2575777

D-17008

Science House Medicals Pvt. Ltd.

Printer
mindray
BC 20s
USB port
Keyboard
Barcode Reader
LIS
WIFI

WIFI capability provides you an added option for data communication together with bi-directional LIS, USB port and LAN port, barcode reader, printer and keyboard.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 ✉ Email : shbpl@rediffmail.com
☎ Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687